असम में अतिक्रमण का क्या है मामला?

पुरातत्वः प्राचीन तमिल सभ्यता की खोज

क्या क्वाड दस्ता साध पाएगा चीन को?

13 अक्तूबर, 2021 50 रुपए

इंडिया टुडे

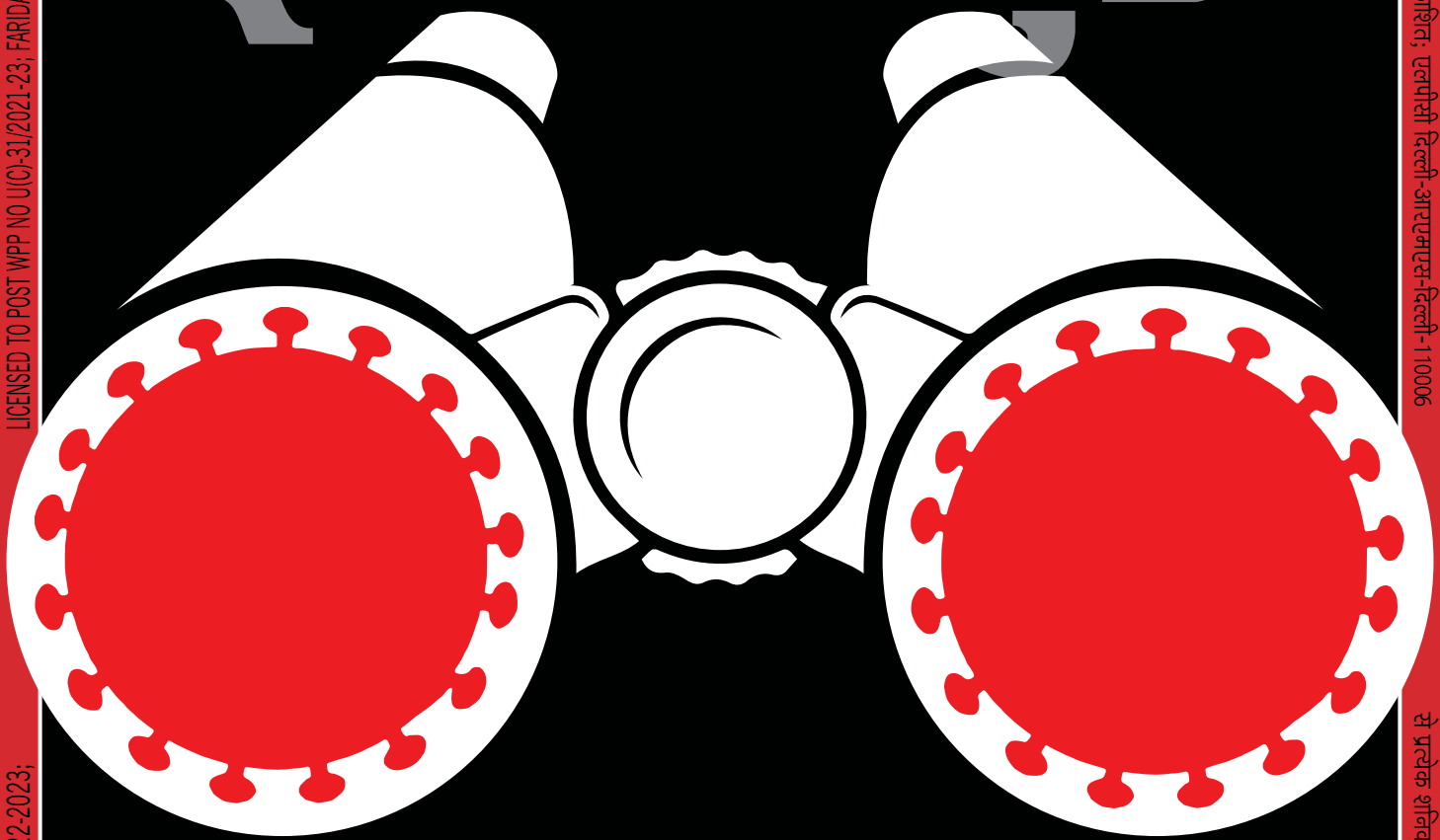

कोविड-19

खत्म हो गई महामारी?

संक्रमण के रोजाना मामलों में जबरदस्त गिरावट से उम्मीद बंधी है, लेकिन विशेषज्ञ किसी तरह की गफलत और समय से पहले जश्न मनाने के खिलाफ दे रहे चेतावनी

RNI NO 45823/86 REGISTERED NO. DL(ND)-11/6042/2021-22-2023; LICENSED TO POST WPP NO U(C)-31/2021-23; FARIDABAD/46/2020-22 www.indiatodayhindi.in

OO आश्विन सप्ताह के लिए प्रत्येक शनिवार को प्रकाशित; एलपीसी दिल्ली-आरएमएस-दिल्ली-110006 से प्रत्येक शनिवार और सोमवार को प्रेषित; कुल पन्नों की संख्या 62 (आवरण सहित)

VISIT…

INDIA TODAY

BREAKING NEWS

JUST A TAP AWAY

DOWNLOAD THE APP NOW

AVAILABLE ON

प्रधान संपादक की कलम से

हम आज अनिश्चय और संदेह के साए में जी रहे हैं. वह अदृश्य कोरोना वायरस अभी भी हमारे आसपास ही मंडरा रहा है. दो टीके लगवाने के बावजूद मेरे मन में एक डर कुंडली मारे बैठा है: क्या मैं सुरक्षित हूं? कोई सार्वजनिक जगहों या बंद कमरे में चाहे मास्क लगाकर जाए, एक असहज भाव डोलता रहता है. डेटा का अभाव भी एक समस्या है. हम नहीं जानते कि वैक्सीन कब तक बीमारी से बचाव करेगी या कौन-से नए म्युटेंट चारों ओर मंडरा रहे हैं. हालांकि कुछ उम्मीद के संकेतक हैं कि देश में महामारी उतार पर है. देश में लगातार 92 दिनों से रोजाना 50,000 से कम मामले दर्ज हुए हैं. 27 सितंबर को सिर्फ 26,041 नए मामले जुड़े. हफ्तावार टेस्ट पॉजिटिविटी दर का राष्ट्रीय औसत 3 फीसद से कम रहा है, जो 5 फीसद से कम होने के डब्ल्यूएचओ के मानक से काफी नीचे है. दिल्ली में लगातार तीसरे महीने रोजाना 100 से कम पॉजिटिव मामले आ रहे हैं. बड़े शहरों में अस्पतालों में कोविड के मरीजों का मामला उस चरम स्थिति के आसपास भी नहीं है, जो जानलेवा दूसरी लहर के वक्त दिखा था. दिल्ली में 27 सितंबर को कोविड बिस्तर 1 फीसद, ऑक्सीजन बिस्तर 1.9 फीसद, कोविड आइसीयू बिस्तर 2 फीसद और कोविड मरीजों के लिए वेंटिलेटर 3 फीसद ही इस्तेमाल में थे.

फिलहाल सबसे ज्यादा संक्रमण के सक्रिय मामलों वाले केरल में अस्पतालों में भर्ती हुए लोगों में सिर्फ 4 फीसद में ही गंभीर लक्षण थे. देश में कोविड-19 का आर-वैल्यू या वायरस वृद्धि दर अगस्त के अंत में 1.17 से गिरकर मध्य सितंबर में 0.92 पर आ गई. इसलिए वायरस भले विदा न हुआ हो, उसका प्रकोप महामारी जैसा नहीं है. इसके बदले, वह जल्दी ही डेंगू या कोढ़ की तरह आम बीमारी बन जा सकता है. इसका मतलब यह है कि कुछ खास इलाकों में उसका प्रकोप अनिश्चित काल तक रह सकता है, मगर उसे ठीक किया जा सकेगा.

3 मार्च, 2021 का आवरण

only books magazine

इसके बावजूद, सावधानियों से हाथ झाड़ लेना जल्दबाजी होगी. इसी साल, कुछ महीने पहले हमें विनाशकारी दूसरी लहर के दौरान खूनी सबक मिल चुका है इसलिए कोविड-19 को कभी हल्के में नहीं लिया जा सकता. सार्स कोव-2 वायरस घातक, अचानक मारक शक्ल अख्तियार करने और तेजी से म्युटेट करने वाला है और ऐसे वक्त हमला बोल देता है, जब उसकी आशंका बहुत कम होती है. बेहद मोटे आकलन के हिसाब से भी इस साल हमारे शहरों में दूसरी लहर से करीब 2,00,000 लोग जान गंवा बैठे और मई में करीब 4,00,000 संक्रमण रोजाना की बुलंदी पर पहुंच गया था.

स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि अभी भी इतने पर्याप्त डेटा नहीं हैं, जिससे यह ऐलान किया जा सके कि बदतरीन दौर यकीनन बीत चुका है, लेकिन महामारी का हर संकेतक इसी ओर इशारा करता दिखता है कि मामला कुछ ऐसा ही है. हमारा टीकाकरण अभियान अब रफ्तार पकड़ चुका है. 1 मार्च और 28 सितंबर के बीच कोविड के 87.1 करोड़ टीके लग चुके हैं. यह पूरे यूरोप की आबादी से अधिक है. देश की तकरीबन दो-तिहाई वयस्क आबादी को एक टीका और एक-चौथाई को दोनों टीके लग चुके हैं. हमारे टीकाकरण का मामला पिछले कुछ महीनों में बेहतर रहा है और रफ्तार पकड़ रहा है. स्वास्थ्य संबंधी अधिकारी दिसंबर तक पूरी वयस्क आबादी को टीका लगाने के विशाल लक्ष्य से इधर-उधर होने को बिल्कुल तैयार नहीं हैं. उन लोगों ने दुर्गम इलाकों, दूर-दराज के क्षेत्रों, बुनियादी सुविधाओं, सांस्कृतिक दृष्टि से संवेदनशील पहलुओं और गलत खबरों की चुनौतियों से पार पा लिया है. हमारे पास अब एक दिन में 2.5 करोड़ टीके लगाने का विश्व रिकॉर्ड है, जो 17 सितंबर को प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर कायम हुआ.

आर्थिक गतिविधियां जोर पकड़ रही हैं. शेयर बाजार उछाल ले रहा है, जो आर्थिक वृद्धि के सकारात्मक रुझान का संकेत है. बेशक, बदतर दौर बीत चुका है, मगर बेफिक्र न हो जाने के लिए कई चेतावनियां और अनेक वजहें हैं. एक, बहुसंख्यक हकदार आबादी का टीकाकरण अभी पूरा नहीं हुआ है, इसलिए उन पर खतरा बना हुआ है. इसलिए भी कि त्योहारों का मौसम बस कुछ हफ्ते ही दूर है और तब लोगों में कोविड की सावधानियों को छोड़ देने की फितरत उछाल मार सकती है. अंदेशा इस बात का भी है कि वायरस के नए म्यूटेंट स्ट्रेन तेजी से बढ़ सकते हैं और इस साल अप्रैल-मई वाले डेल्टा वैरिएंट जैसी ही तबाही मचा सकते हैं. जैसा कि संक्रामक रोगों के एक विशेषज्ञ ने हमें बताया, ''मामले भले घट गए हों, मगर हम कोविड और उसकी भयावहता को हल्के में नहीं ले सकते.''

ज्यादातर राज्यों में मई 2021 में दूसरी लहर के चरम के मुकाबले संक्रमण के मामलों और पॉजिटिविटी दर में काफी गिरावट आ चुकी है, मगर चिंता के कुछ द्वीप अभी बने हुए हैं. मसलन, केरल में 28 सितंबर को पॉजिटिविटी दर 15 फीसद और सक्रिय मामले 1,57,204 थे. बेफिक्री के आम रुझान को 'हर्ड इम्युनिटी' की सोच भी बढ़ा रही है, जिसे कई जानकार संदिग्ध विचार बताकर चेता रहे हैं. सीरोप्रीवैलेंस अध्ययन कोविड के प्रकोप और उसके रुख को समझने के लिए अहम हैं, लेकिन ऊंची सीरोपॉजिटिविटी से यह नहीं पता चलता कि महामारी खत्म हो गई है. बदकिस्मती से, कोविड से रक्षा में ऐंटीबॉडी की भूमिका और उसके स्तर को लेकर पर्याप्त डेटा उपलब्ध नहीं है. यही नहीं, वायरस के उप-प्रकार भी दूसरे देशों और अपने कुछ राज्यों में पाए गए हैं. मसलन, एक उप-प्रकार सबसे पहले इज्राएल में पाया गया, जिससे संक्रमण की ऐसी लहर आई कि 60 फीसद आबादी के पूरी तरह टीकाकरण से भी फर्क नहीं पड़ा.

हमारी आवरण कथा 'खत्म हो गई महामारी?' कई बड़े सवाल पूछती है, जिसे सीनियर एसोसिएट एडिटर सोनाली आचार्जी ने लिखा है. क्या कोविड-19 आम बीमारी जैसी हो जाएगा? कब तब टीके हमारा कवच बनेंगे? और सबसे बढ़कर, क्या तीसरी लहर आएगी?

यह आज इसलिए मौजूं है क्योंकि त्योहारों का मौसम सामने है और असली परीक्षा यह देखना होगी कि उसके बाद संक्रमण और मृत्यु दर बढ़ती तो नहीं है. इस वायरस के अप्रत्याशित रुख और इस तथ्य की वजह से हमें इसके साथ जीना सीखना होगा कि शायद यह हमेशा बना रहे. हमें मास्क पहनने, आपसी दूर का ख्याल रखने और कोविड से जुड़ी तमाम सावधानियां बरतने की जरूरत है. मामूली कोताही या लापरवाही भी तबाही ला सकती है. इसलिए सुरक्षित रहें.

अरुण पुरी

(अरुण पुरी)

इंडिया टुडे

www.indiatodayhindi.in

चेयरमैन और प्रधान संपादक: अरुण पुरी
वाइस चेयरपर्सन: कली पुरी
ग्रुप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर: दिनेश भाटिया
ग्रुप एडिटोरियल डायरेक्टर: राज चेंगप्पा
चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर: मनोज शर्मा
एडिटर: अंशुमान तिवारी
सीनियर एडिटर: मोहम्मद वक़ास
एसोसिएट एडिटर: शिवकेश मिश्र, शुभम शंखधर, आशीष मिश्र (लखनऊ)
असिस्टेंट एडिटर: मनीष दीक्षित, सुजीत ठाकुर
राज्य ब्यूरो:, अभिताभ श्रीवास्तव (पटना), रोहित परिहार (जयपुर), एम.जी. अरुण (मुंबई), राहुल नरोन्हा (भोपाल), अमरनाथ के. मेनन (हैदराबाद)
ग्रुप क्रिएटिव एडिटर: नीलांजन दास
एसोसिएट आर्ट डायरेक्टर: चंद्रमोहन ज्योति
असिस्टेंट आर्ट डायरेक्टर: असित रॉय
ग्रुप फोटो एडिटर: बंदीप सिंह
फोटो डिपार्टमेंट: यासिर इकबाल, राजवंत रावत, चंद्रदीप कुमार, मंदार सुरेश देवधर (मुंबई)
चीफ फोटो रिसर्चर: प्रभाकर तिवारी
प्रिंसिपल फोटो रिसर्चर: सलोनी वैद
प्रोडक्शन चीफ: अभिनव पुगला

एसोसिएट पब्लिशर: विद्या मेनन (इंपैक्ट)
इंपैक्ट टीम
नेशनल हेड: सुपर्णा कुमार (गवर्नमेंट ऐंड पीएसयू)
सीनियर जनरल मैनेजर: जीतेंद्र लाड (वेस्ट)
जनरल मैनेजर: मयूर रस्तोगी (नॉर्थ), उपेंद्र सिंह (बेंगलूरू)
डिप्टी जनरल मैनेजर: इंद्रनील चटर्जी (ईस्ट)
ग्रुप चीफ मार्केटिंग ऑफिसर: विवेक मल्होत्रा
सेल्स एवं ऑपरेशन
सीनियर जनरल मैनेजर: दीपक भट्ट (नेशनल सेल्स)
जनरल मैनेजर: विपिन बग्गा (ऑपरेशंस)
डिप्टी जनरल मैनेजर: राजीव गांधी (नॉर्थ)
डिप्टी रीजनल सेल्स मैनेजर: योगेश गोधनलाल गौतम (वेस्ट)
डिप्टी रीजनल सेल्स मैनेजर: एस. परमशिवम (साउथ)
सीनियर सेल्स मैनेजर: पीयूष रंजन दास (ईस्ट)

INDIA TODAY GROUP

वर्ष: 35; अंक: 46; 7-13 अक्तूबर, 2021; प्रत्येक शनिवार को प्रकाशित

- **संपादकीय कॉर्पोरेट कार्यालय:** लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड, इंडिया टुडे ग्रुप मीडियाप्लेक्स, एफसी-8, सेक्टर 16-ए, फिल्म सिटी, नोएडा-201301, फोन: 0120-4807100;
- **ग्राहकी चंदा भेजें:** इंडिया टुडे (हिंदी), पो. बॉक्स 114, नई दिल्ली-110001
- **ग्राहक सेवा:** कस्टमर केयर, इंडिया टुडे ग्रुप, सी-9, सेक्टर-10, नोएडा (उत्तर प्रदेश)-201301, टोल फ्री फोन नं. 1800 1800 100 (बीएसएनएल/एमटीएनएल लाइनों से) फोन: दिल्ली, फरीदाबाद से (95120) 2479900; शेष भारत से (0120) 2479900. (सोम से शुक्र-सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक), फैक्स: (0120) 4078080. ई-मेल: wecare@intoday.com
- **सर्कुलेशन कार्यालय:** लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड, सी-9, सेक्टर-10, नोएडा (उत्तर प्रदेश)-201301
- **इंपैक्ट कार्यालय:** 1201, 12वां तल, टावर 2ए, वन इंडियाबुल्स सेंटर, (जुपिटर मिल्स) एस.बी. मार्ग, लोअर परेल (पश्चिम)-मुंबई-400013. फोन: 022-66063355 फैक्स: 022-66063226
- **क्षेत्रीय विज्ञापन कार्यालय:** ए1-ए2, एनके सेंटर, विनुज्य निकुंज, उद्योग विहार, फेज-5, गुड़गांव, हरियाणा, फोन: 0124-4948400;
- 201-204 रिचमंड टावर्स, द्वितीय मंजिल, 12 रिचमंड रोड, बंगलुरु-560 025 फोन: 2212448, 226233, टेलेक्स: 0845-2217 INTO IN. फैक्स: 080-2218335.
- रजिस्टर्ड कार्यालय: एफ-26, फर्स्ट फ्लोर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001
- लिविंग मीडिया इंडिया लि. विश्व भर में सर्वाधिकार सुरक्षित. किसी भी रूप में सामग्री की नकल प्रतिबंधित. इंडिया टुडे अनिमंत्रित प्रकाशन सामग्री को लौटाने की जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता.
- सभी विवादों का निबटारा दिल्ली/नई दिल्ली की सीमा में आने वाली सक्षम अदालतों और फोरमों में किया जाएगा.
- **लिविंग मीडिया इंडिया लि. के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक मनोज शर्मा द्वारा एफ-26, फर्स्ट फ्लोर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 से प्रकाशित और थॉमसन प्रेस इंडिया लि., 18-35, माइलस्टोन, दिल्ली-मथुरा रोड, फरीदाबाद-121 007 (हरियाणा) में मुद्रित. संपादक: राज चेंगप्पा**

भीतर

सुर्खियां
पंजाब: क्या कांग्रेस फंस गई है?
पेज 6

अर्थात्: कसौटियों की कसौटी
पेज 28

फुरसत
सिनेमा/प्रतीक गांधी: अब और जद्दोजहद नहीं
पेज 58

सवाल-जवाब/इंदिरा नूई: जिंदगी मेरी, फैसले मेरे
पेज 60

इलस्ट्रेशन: नीलांजन दास

30

आवरण कथा

क्या गुजर गया बदतरीन दौर?

घटता संक्रमण और कुछ दूसरे तथ्यों से कोविड-19 महामारी के शांत पड़ने के संकेत. पर विशेषज्ञ किसी तरह की ढिलाई या समय से पहले ही जश्न मनाने को लेकर सावधान कर रहे

कूटनीति

38 **क्वाड की पलटन**

भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया क्या आक्रामक चीन को नकेल लगा पाएंगे?

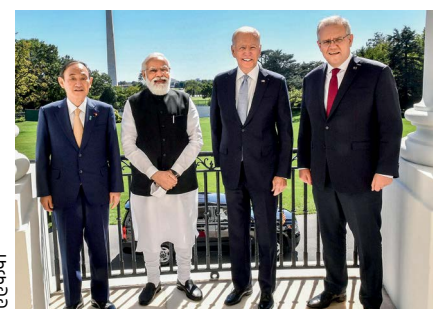

एपएफ

खास रपट: असम

44 **बेदखली की सियासत**

हिंसक बेदखली अभियान से भाजपा सरकार का पूर्वाग्रही रवैया उजागर

मानस दास

इंडिया टुडे

इंडिया टुडे मैगजीन मिलने में दिक्कत हो रही है?
9311409555 पर नाम पता या 'हेलो' संदेश भेजें.
या मेल करें: Moreinfo@intoday.com
हम आपसे संपर्क कर लेंगे.

आवरण इलस्ट्रेशन: नीलांजन दास

पाठकों के लिए सूचना: कभी-कभी आपको इंडिया टुडे पत्रिका में 'इम्पैक्ट फीचर' या 'एडवरटोरियल' या 'फोकस' के पन्ने नजर आएंगे. ये विज्ञापन होंगे और इन्हें बनाने में पत्रिका के संपादकीय स्टाफ शामिल नहीं होते.

INDIA TODAY GROUP

पाठकों को सलाह दी जाती है कि पत्रिका में प्रकाशित किसी भी सेवा या व्यक्ति के विज्ञापन और प्रचार से संबंधित सामग्री से वचनबद्धता कायम करने, पैसा भेजने या खर्च करने से पहले उचित जांच-पड़ताल कर लें. विज्ञापनदाताओं के किसी भी दावे का उत्तरदायित्व इंडिया टुडे ग्रुप का नहीं है. ऐसे किसी भी तरह के दावों को विज्ञापनदाता अगर नहीं पूरा करता है तो इंडिया टुडे ग्रुप के प्रकाशनों के मुद्रक, प्रकाशक, एडिटर-इन-चीफ और एडिटर इसके लिए जिम्मेदार नहीं होंगे.

INDIA TODAY CONCLAVE 2021

8/9 OCT
NEW DELHI

only books magazine

INDIA TODAY GROUP

DR IAN LIPKIN

VIRUS ORACLE | ACE EPIDEMIOLOGIST

On contagion,
containment.
And a next crisis

PANDEMICS
#ABetterNormal

PRESENTING SPONSOR

ITC
Enduring Value

CONCLAVE PARTNERS

HINDUSTAN POWER

Darwin
DARWIN PLATFORM GROUP OF COMPANIES
VISIONARIES

KNOWLEDGE PARTNER

JGI JAIN
DEEMED-TO-BE UNIVERSITY

BANKING PARTNER

IDFC FIRST Bank
ALWAYS YOU FIRST

LUXURY MOBILITY PARTNER

BMW

STATE PARTNER

INSURANCE PARTNER

LIC
भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

PARTNER

SHRIRAM
Transport Finance Company Limited
A WINNING RELATIONSHIP

CELEBRATION PARTNER

THE GLENLIVET
BOOKS

BESPOKE PARTNER

DA MILANO
ITALIA

उत्तराखंडः
धुवीकरण का दांव
पेज 10

उत्तर प्रदेशः मंत्रिमंडल विस्तार
से साधे समीकरण
पेज 12

सुर्खियां

बिहारः कांग्रेस की
नजर युवाओं पर
पेज 16

तृणमूल बनाम ईडी/सीबीआइः
तो क्या अब होकर ही
रहेगी मुठभेड़? पेज 20

समीर सहगल/गेट्टी इमेजेज

नया अलगाव
पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और उप-मुख्यमंत्री सुखजिंदर रंधावा के साथ नवजोत सिद्धू (बाएं से)

only books magazine

पंजाब

क्या कांग्रेस फंस गई है?

अनिलेश एस. महाजन

आठ सितंबर को दोपहर करीब 3 बजे पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीपीसीसी) के प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू ने अपना इस्तीफा ट्वीट करके एक बार फिर कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी. जल्द ही, उनके दो समर्थकों, कैबिनेट मंत्री रजिया सुल्तान और परगट सिंह ने भी अपने इस्तीफे दे दिए. जाहिर है, सिद्धू महत्वपूर्ण नियुक्तियों पर नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के स्वतंत्र राह अपनाने से नाराज थे. उनमें राज्य मंत्रिमंडल में विवादास्पद विधायक और शराब कारोबारी राणा गुरजीत सिंह को शामिल करना; राज्य के अटॉर्नी जनरल के रूप में ए.पी.एस. देओल और डीजीपी के रूप में इकबाल प्रीत सिंह सहोता को नियुक्त करना; और सिद्धू के कट्टर विरोधी सुखजिंदर सिंह रंधावा को गृह मंत्रालय सौंपना शामिल था.

29 सितंबर की देर रात तक पार्टी आलाकमान ने इस्तीफे स्वीकार नहीं किए थे. फरवरी 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए, कांग्रेस राज्य के ड्रग माफिया और अवैध रेत खनन और नकली शराब की बिक्री में शामिल लोगों पर कार्रवाई के साथ अपनी छवि बदलने की योजना बना रही थी, साथ ही 2015 में गुरु ग्रंथ साहिब के अपमान की गड़बड़ी को सुलझाने की भी कोशिश कर रही थी. इसके लिए गृह मंत्री, पुलिस प्रमुख और महाधिवक्ता का पद महत्वपूर्ण था. सिद्धू भारत के पूर्व हॉकी कप्तान परगट सिंह को गृह मंत्री

INDIA TODAY CONCLAVE 2021

8/9 OCT
NEW DELHI

INDIA TODAY GROUP

GEN. DAVID H. PETRAEUS

ELDER WARRIOR | COMMANDER,
US FORCES, IRAQ-AFGHANISTAN

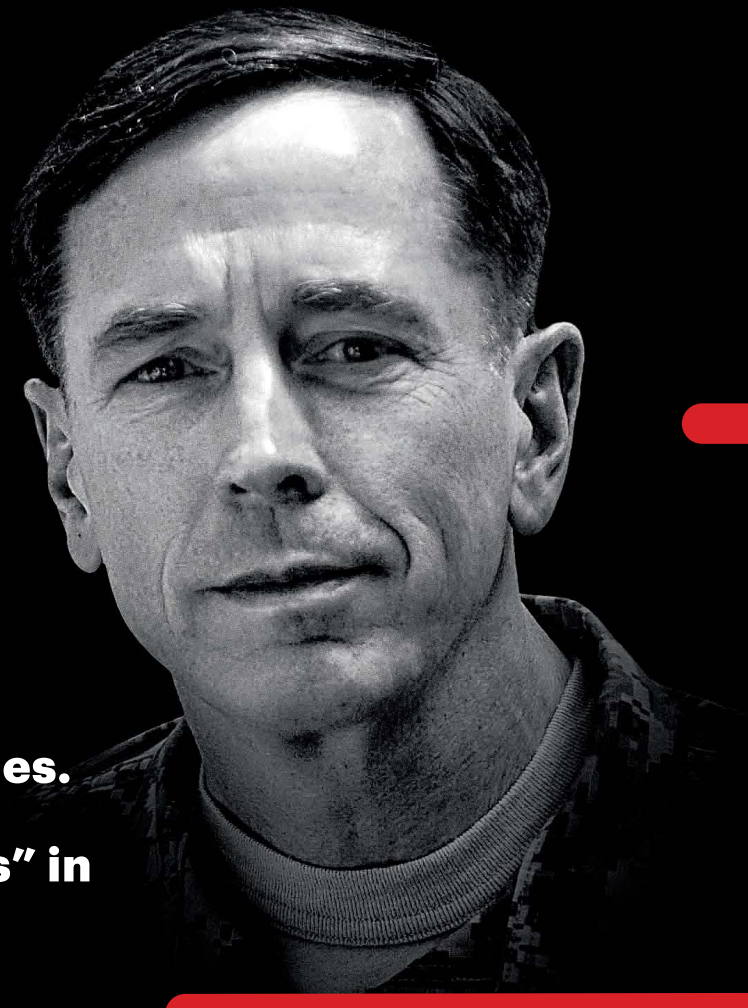

On counter-terrorism, building armies. And fighting "forever wars" in foreign lands

PEACE-KEEPING
#ABetterNormal

PRESENTING SPONSOR

ITC Enduring Value

CONCLAVE PARTNERS

HINDUSTAN POWER | Darwin DARWIN PLATFORM GROUP OF COMPANIES VISIONARIES

KNOWLEDGE PARTNER

JGI JAIN DEEMED-TO-BE UNIVERSITY

BANKING PARTNER

IDFC FIRST Bank
ALWAYS YOU FIRST

LUXURY MOBILITY PARTNER

BMW

STATE PARTNER

INSURANCE PARTNER

LIC भारतीय जीवन बीमा निगम LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

PARTNER

SHRIRAM Transport Finance Company Limited
A WINNING RELATIONSHIP

CELEBRATION PARTNER

THE GLENLIVET BOOKS

BESPOKE PARTNER

DA MILANO ITALIA

रवि कुमार/गेट्टी इमेजेज

कैप्टन का दांव
18 सितंबर को मीडिया से मुखातिब पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह

और 1986 बैच के आइपीएस अधिकारी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय को पुलिस प्रमुख बनाना चाहते थे. हालांकि, वर्तमान नियुक्तियों से पता चला है कि चन्नी, सिद्धू के अपने आदमी हैं. इसके बावजूद सिद्धू को पता होना चाहिए था कि नए मुख्यमंत्री चतुर राजनेता हैं. केवल 15 वर्षों में, चन्नी ने बिना किसी गॉडफादर के नगरपालिका समिति के सदस्य से लेकर पंजाब के पहले दलित मुख्यमंत्री तक का सफर तय किया है.

कांग्रेस ने जाट सिखों के अलग-थलग पड़ने का जोखिम उठाकर चन्नी को सीएम बनाया है. अब यह सियासी आत्महत्या साबित होगी, अगर यह धारणा बने कि सिद्धू को खुश करने के लिए चन्नी को कमतर आंका जा रहा

अब सवाल यह है कि 'जज्बाती' सिद्धू को पार्टी अनुशासन मानने के लिए कौन मनाएगा. पंजाब में पार्टी के नेताओं ने कोशिश की, पर कोई लाभ नहीं हुआ. 29 सितंबर को प्रियंका गांधी को यह कार्य सौंपा गया था. पांच महीने में होने वाले विधानसभा चुनाव के साथ, कांग्रेस नेता सिद्धू को अच्छे मिजाज में रखना चाहते हैं और सिख युवाओं के बीच समर्थन बढ़ाने के लिए उनके भाषण कौशल का उपयोग करना चाहते हैं. लेकिन क्या उन्होंने पूर्व क्रिकेटर के साथ अपना दांव खो दिया है? राज्य कांग्रेस के एक शीर्ष नेता कहते हैं, ''राज्य कांग्रेस के अब एक महीने पहले से ज्यादा गुट हो गए हैं, तब सिर्फ सिद्धू या अमरिंदर खेमा था.''

इसलिए कांग्रेस नेतृत्व प्रचार अभियान मोड में होने के बजाए संकट प्रबंधन में फिर फंस गया है. पार्टी आलाकमान पर निशाना साधते हुए, हाल ही में अपदस्थ मुख्यमंत्री ने कहा, ''मैंने आपसे कहा था...यह आदमी अस्थिर है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता.'' पीसीसी में सिद्धू के पूर्ववर्ती सुनील जाखड़ ने भी उन पर कटाक्ष किया, जबकि आनंदपुर साहिब के सांसद मनीष तिवारी ने गूढ़ ट्वीट्स में अपनी पीड़ा व्यक्त की.

कांग्रेस के सामने गंभीर दुविधा है. 20 सितंबर को चन्नी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और इस पद पर जाट सिखों की पकड़ को तोड़ते हुए राज्य में 32 प्रतिशत दलित वोटों के सहारे कांग्रेस जीत की स्थिति में थी. ऐसा जाट सिखों को अलग-थलग करने का जोखिम उठाकर किया गया था. अब, अगर यह धारणा निकले कि जाट सिख नेता सिद्धू को खुश करने के लिए दलित मुख्यमंत्री को कमतर आंका जा रहा है तो यह राजनैतिक आत्महत्या साबित होगी.

ये घटनाक्रम कांग्रेस मुख्यालय के रणनीतिकारों, विशेष रूप से राहुल और प्रियंका गांधी के लिए चिंता का विषय होना चाहिए. उन्होंने ही सिद्धू के लिए राज्य इकाई में समर्थन जुटाया था और तत्कालीन मुख्यमंत्री अमरिंदर के विरोध को क्रिकेटर से नेता बने सिद्धू को पीसीसी अध्यक्ष पद सौंपने के लिए उकसाया था. अगर संकट को जल्द खत्म नहीं किया गया, तो राज्य कांग्रेस विभिन्न गुटों में टूट सकती है. पंजाब में कई कांग्रेस विधायक नाराज हैं, जिन्हें या तो हटा दिया गया है या जिन्हें कैबिनेट में शामिल नहीं किया जा सका है.

चन्नी मंत्रिमंडल को भी जाट सिख प्रभुत्व और क्षेत्रीय असंतुलन की अमरिंदर की विरासत मिली है. 18 मंत्रियों में से आठ जाट सिख हैं, वहीं सिर्फ तीन (मुख्यमंत्री सहित) दलित हैं. कृषि आंदोलन के केंद्र दक्षिण-पश्चिम पंजाब को चार मंत्री मिले हैं (उनमें से रजिया सुल्तान ने इस्तीफा दे दिया है). मंत्री के रूप में, चन्नी इस तरह के असंतुलन का विरोध करने में मुखर रहा करते थे.

नाराज विधायकों में से कई या तो अमरिंदर के साथ मिल रहे हैं या पार्टी के बाहर मौके तलाश रहे हैं. कांग्रेस अपने विधायकों के जाने को बर्दाश्त नहीं कर सकती. सुखबीर बादल के नेतृत्व वाली शिरोमणि अकाली दल (शिअद) पहले से ही अभियान मोड में है और, एक छोटी पार्टी और किसान यूनियनों के साथ एक भेंट के बाद, लड़ रही 97 सीटों में से 60 से अधिक के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की है (सहयोगी बसपा को अन्य 20 आवंटित). विशेष रूप से खराब काडर संरचना और नेतृत्व संकट (भगवंत मान बनाम पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल) के कारण पंजाब में आम आदमी पार्टी (आप) की परियोजना अभी तक शुरू नहीं हुई है. लेकिन कहा जाता है कि कई कांग्रेस नेता आप नेताओं के संपर्क में हैं और अगर पार्टी में उथल-पुथल जारी रहती है, तो वे आप का रुख कर सकते हैं.

इस बीच, भाजपा अपने शहरी हिंदू मतदाता आधार को मजबूत करने की कोशिश कर रही है और अमरिंदर के संपर्क में है. जिस दिन सिद्धू ने इस्तीफा दिया, अमरिंदर नई दिल्ली पहुंचे और कपूरथला हाउस में राज्य के मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास को खाली करने के अलावा, वे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने वाले थे. लेकिन बैठक को 29 सितंबर के लिए पुनर्निर्धारित किया गया. अफवाह है कि अमरिंदर भगवा खेमे में जाने से पहले किसान आंदोलन के लिए कोई समाधान निकाल रहे हैं. पटियाला के पूर्व शासक के 'अपमानजनक' निष्कासन ने पंजाब में उदारवादी सिखों और शहरी हिंदुओं के बीच सहानुभूति पैदा की है, जो आने वाले चुनाव में गेमचेंजर साबित हो सकती है. ■

INDIA TODAY CONCLAVE 2021

8/9 OCT
NEW DELHI

INDIA TODAY GROUP

NITIN GADKARI

GREEN PATHFINDER | MINISTER, TRANSPORT & HIGHWAYS

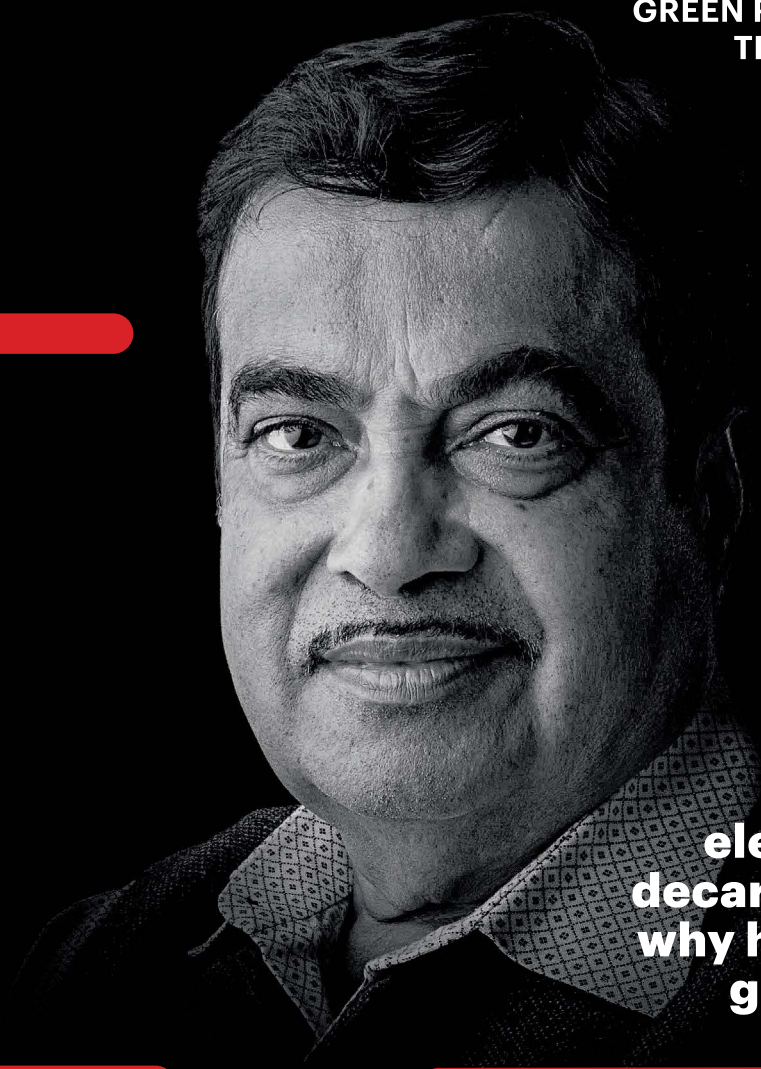

On India's electric mission, decarbonising. And why he advocates a green economy

CLIMATE ACTION
#ABetterNormal

PRESENTING SPONSOR

ITC
Enduring Value

CONCLAVE PARTNERS

HINDUSTAN POWER | Darwin DARWIN PLATFORM GROUP OF COMPANIES VISIONARIES

KNOWLEDGE PARTNER

JGI JAIN DEEMED-TO-BE UNIVERSITY

BANKING PARTNER

IDFC FIRST Bank
ALWAYS YOU FIRST

LUXURY MOBILITY PARTNER

BMW

STATE PARTNER

उत्तर प्रदेश सरकार

INSURANCE PARTNER

LIC भारतीय जीवन बीमा निगम LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

PARTNER

SHRIRAM Transport Finance Company Limited
A WINNING RELATIONSHIP

CELEBRATION PARTNER

THE GLENLIVET BOOKS

BESPOKE PARTNER

DA MILANO ITALIA

फोटोः रामेश्वर गौड़

उत्तराखंड में भूकानून के लिए गठित समिति के अध्यक्ष सुभाष कुमार से समुदाय विशेष के लिए जमीन की खरीद-फरोख्त को लेकर कड़े नियम बनाने को ज्ञापन देते अजेंद्र अजय

उत्तराखंड

ध्रुवीकरण का दांव

अखिलेश पांडे

उत्तराखंड में विधानसभा चुनावों से ठीक पहले भाजपा धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश में जुटती नजर आ रही है. भाजपा के केदारघाटी में सक्रिय नेता एवं पूर्व दायित्वधारी अजेंद्र अजय ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर पर्वतीय क्षेत्र को 'विशेष क्षेत्र अधिसूचित' करके एक समुदाय विशेष के धर्मस्थलों के निर्माण पर प्रतिबंध लगाने और भूमि के क्रय-विक्रय के लिए विशेष प्रावधान करने की मांग की है. उनका आरोप है कि पहाड़ी कस्बों में एक खास समुदाय के लोगों के भूमि खरीदने और उनके धर्मस्थलों की संख्या बढ़ने की शिकायतें मिल रही हैं. वे इसे 'लैंड जिहाद' तक कहते हैं और आरोप लगाते हैं कि इससे कई कस्बों और तीर्थ स्थलों का संतुलन बिगड़ने की संभावना है. इसके बाद सरकार ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखा है.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पत्रकारों के इस मामले में कहा, ''लंबे समय से चर्चा चल रही है कि राज्य में कुछ इस प्रकार के लोग आकर बस गए हैं जिससे डेमोग्राफिक परिवर्तन देखने को मिल रहा है, जिसकी जांच होनी चाहिए.'' धामी यह भी कहते हैं कि यह जांच किसी को निशाना बनाने के लिए नहीं की जा रही है. 24 सितंबर को सरकार के एक बयान में कहा गया, ''राज्य के कुछ क्षेत्रों में तेजी से जनसंख्या वृद्धि के कारण डेमोग्राफिक परिवर्तन आया, जिसका दुष्परिणाम कुछ समुदायों के लोगों के प्रवास के रूप में दिखना शुरू हो गया. कुछ जगहों पर सांप्रदायिक माहौल खराब होने की आशंका है. सरकार ने स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए डीजीपी, सभी जिलों के डीएम और एसएसपी को समस्या के समाधान के लिए एहतियाती कदम उठाने का निर्देश दिया है.'' उन लोगों की जिलेवार सूची तैयार करने को कहा गया है जो दूसरे राज्यों से आए हैं और जिनका आपराधिक अतीत है. अवैध भूमि सौदों पर भी नजर रखने कहा गया है.

विपक्षी पार्टियां इसे चुनाव से पहले ध्रुवीकरण का प्रयास बता रही हैं लेकिन भाजपा इससे इनकार करती है. उसका कहना है कि खुद कांग्रेस ने सख्त भूमि कानून की मांग करके इस बहस की शुरुआत की थी. कांग्रेस का आरोप था कि दूसरे राज्यों के लोग उत्तराखंड में जमीन खरीदकर स्थानीय संस्कृति को नुक्सान पहुंचा रहे हैं. जब एक अन्य व्यक्ति ने इस बारे सरकार को लिखा तब राज्य सरकार ने इसकी जांच का फैसला किया. यह किसी खास समुदाय के विरुद्ध नहीं है.

लेकिन प्रदेश में मुख्य विपक्षी कांग्रेस और राज्य में उभर रही आम आदमी पार्टी इसे आम मुद्दों से ध्यान भटकाने की साजिश बता रहे हैं. उनका कहना है कि आसन्न चुनावों के मद्देनजर भाजपा और उसकी सरकार एक नया मुद्दा पैदा करके राज्य में एक धर्म विशेष के लोगों के मतों के ध्रुवीकरण का प्रयास कर रही है. कांग्रेस के उपाध्यक्ष धीरेंद्र प्रताप के अनुसार, ''चुनाव सिर पर हैं और सत्तारूढ़ भाजपा पांच साल में कोई भी ऐसा काम नहीं कर पाई जिसे वह अपनी उपलब्धि बताए और उस पर वोट मांगे. इसलिए ऐसे मुद्दों के कवच में छिपकर वह चुनावी युद्ध की तैयारी कर रही है.'' पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अशिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव में सभी धर्म-जाति के गरीबों में जनसंख्या वृद्धि दर चिंताजनक है, और सरकार को इस दर को नियंत्रित करने के उचित कदम उठाने चाहिए, न कि समुदाय विशेष को टारगेट कर सियासी लाभ उठाने की कोशिश करनी चाहिए.

विपक्षी दलों का आरोप है कि सत्तासीन भाजपा अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए धार्मिक ध्रुवीकरण का दांव चल रही है

वहीं, उत्तराखंड क्रांति दल के मीडिया प्रभारी रहे शिव प्रकाश सेमवाल कहते हैं कि भाजपा की त्रिवेंद्र सरकार ने पलायन आयोग का गठन कर वाहवाही लूटने की कोशिश की थी. आयोग की रिपोर्ट में साफ कहा गया कि राज्य में बेहतर चिकित्सा स्वास्थ्य शिक्षा और रोजगार का कोई जरिया नहीं होना पलायन का सबसे बड़ा कारण है. इस बात के सामने आने के बाद भी सरकार न तो इन कारणों को दूर करने की कुछ योजनाएं बना पाई, न ही 'भुतहा गांवों' में कोविड संकट के दौरान घर लौटे प्रवासियों को रोक पाई. अब चुनाव में ये बातें मुद्दा न बन जाएं, इससे डरकर वह 'लैंड जिहाद' जैसी भ्रामक बातें कर रही है और ध्रुवीकरण की साजिश रच रही है.

भाजपा की ध्रुवीकरण की कवायद कितनी सफल होगी यह तो चुनाव में पता चलेगा, पर यह मुद्दा शांत माने जाने वाले उत्तराखंड में सामाजिक विघटन पैदा कर सकता है. ■

INDIA TODAY CONCLAVE 2021

8/9 OCT
NEW DELHI

INDIA TODAY GROUP

ARIF MOHAMMAD KHAN

SCRIPTURE SCHOLAR | GOV. KERALA

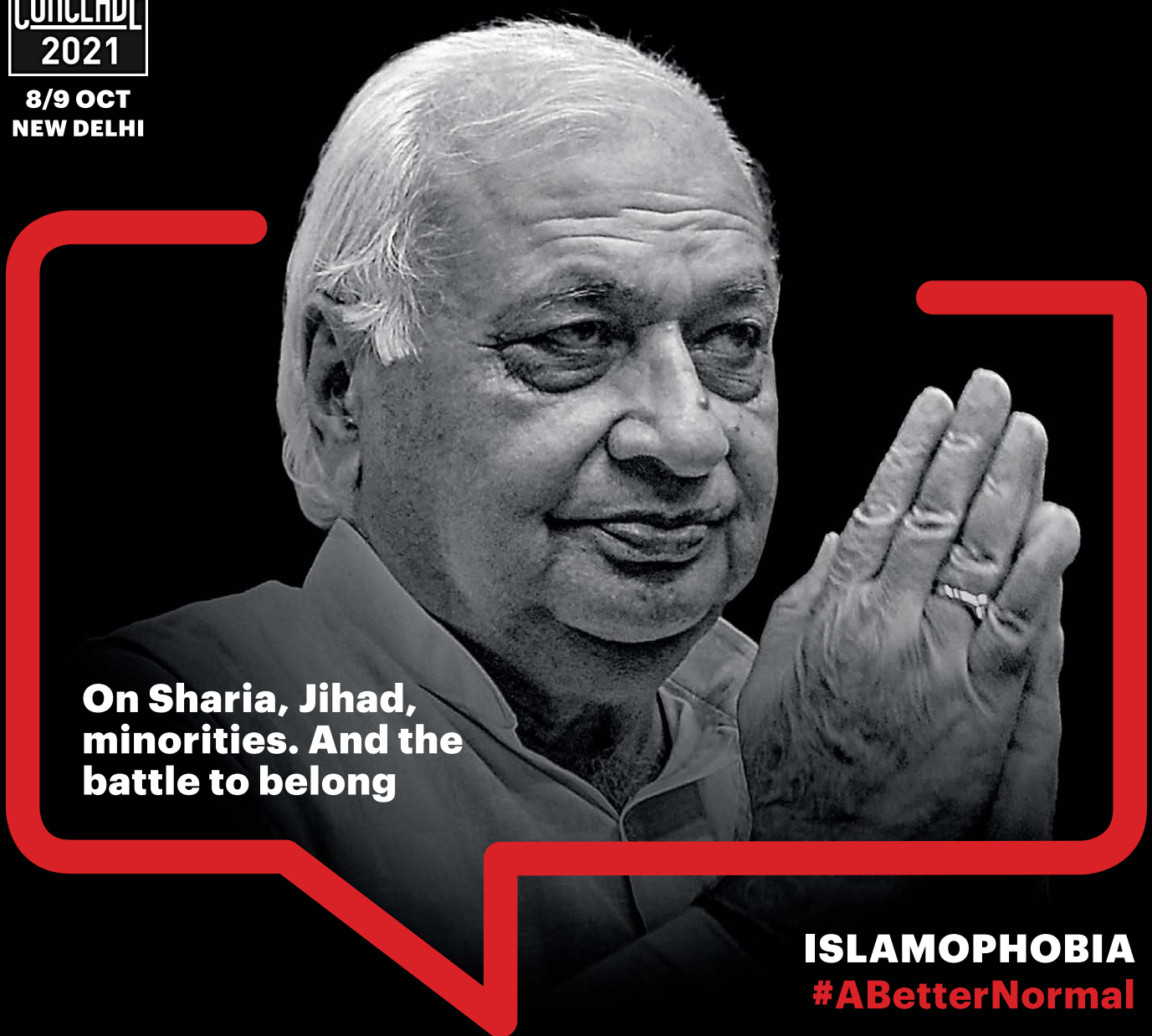

On Sharia, Jihad, minorities. And the battle to belong

ISLAMOPHOBIA

#ABetterNormal

PRESENTING SPONSOR

ITC
Enduring Value

CONCLAVE PARTNERS

HINDUSTAN POWER

Darwin
DARWIN PLATFORM GROUP OF COMPANIES
VISIONARIES

KNOWLEDGE PARTNER

JGI JAIN
DEEMED-TO-BE UNIVERSITY

BANKING PARTNER

IDFC FIRST Bank
ALWAYS YOU FIRST

LUXURY MOBILITY PARTNER

BMW

STATE PARTNER

उत्तर प्रदेश सरकार

INSURANCE PARTNER

LIC
भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

PARTNER

SHRIRAM
Transport Finance Company Limited
A WINNING RELATIONSHIP

CELEBRATION PARTNER

THE GLENLIVET
BOOKS

BESPOKE PARTNER

DA MILANO
ITALIA

संतुलन शपथ ग्रहण के बाद नए मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल

मनीष अग्निहोत्री

उत्तर प्रदेश

मंत्रिमंडल विस्तार से साधे समीकरण

आशीष मिश्र

उत्तर प्रदेश में जून में संपन्न हुए पंचायत चुनाव के बाद से ही योगी मंत्रिमंडल के विस्तार की अटकलें शुरू हो गई थीं. मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक कई बार भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेताओं के बीच बैठकों का दौर चला. 23 सितंबर को लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर भाजपा के विधानसभा चुनाव प्रभारी और केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में हुई भाजपा कोर कमेटी की बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार पर सहमति बनी. वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने में तीन महीने से कुछ ज्यादा ही समय शेष रह गया है. ऐसे में भाजपा ने पितृपक्ष में शुभकार्य न करने की परिपाटी को तोड़ते हुए 26 सितंबर को योगी मंत्रिमंडल विस्तार का बहुप्रतिक्षित विस्तार कर दिया. शाम छह बजे राजभवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, डॉ. दिनेश शर्मा, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह की मौजूदगी में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने एक कैबिनेट और छह राज्यमंत्रियों को शपथ ग्रहण कराई.

कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने कैबिनेट मंत्री की शपथ ली. बलरामपुर के विधायक पलटूराम, सोनभद्र के ओबरा से विधायक संजीव कुमार गोंड, गाजीपुर से विधायक संगीता बिंद, मेरठ से विधायक दिनेश खटीक, आगरा से विधायक धर्मवीर प्रजापति और बरेली के बहेड़ी से विधायक छत्रपाल गंगवार को राज्यमंत्री के रूप शपथ दिलाई गई. भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष विजय बहादुर पाठक बताते हैं, ''मंत्रिमंडल विस्तार में सामाजिक समरसता और संतुलन का खास ध्यान रखा गया है. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चिंतक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के एक दिन बाद हुए मंत्रिमंडल विस्तार में दीनदयाल के अंत्योदय के सपनों को साकार करते हुए

INDIA TODAY CONCLAVE 2021

8/9 OCT
NEW DELHI

INDIA TODAY GROUP

SHASHI THAROOR

VERBAL SWORDSMAN | CONGRESS LEADER

On bitter fights over history. And bridging divides between Hindutva & liberals

HISTORY DEBATES

#ABetterNormal

PRESENTING SPONSOR

ITC
Enduring Value

CONCLAVE PARTNERS

HINDUSTAN POWER | Darwin DARWIN PLATFORM GROUP OF COMPANIES VISIONARIES

KNOWLEDGE PARTNER

JGI JAIN DEEMED-TO-BE UNIVERSITY

BANKING PARTNER

IDFC FIRST Bank
ALWAYS YOU FIRST

LUXURY MOBILITY PARTNER

BMW

STATE PARTNER

उत्तर प्रदेश सरकार

INSURANCE PARTNER

LIC भारतीय जीवन बीमा निगम LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

PARTNER

SHRIRAM Transport Finance Company Limited
A WINNING RELATIONSHIP

CELEBRATION PARTNER

THE GLENLIVET BOOKS

BESPOKE PARTNER

DA MILANO ITALIA

खटीक, बिंद, प्रजापति जैसे अति पिछड़े और अति दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व दिया गया है जिन्हें कभी अवसर नहीं मिला था.'' योगी मंत्रिमंडल में शामिल किए गए नए चेहरों में एक ब्राह्मण (अगड़ा), तीन पिछड़े और, दो अनुसूचित जाति और एक अनुसूचित जनजाति से आते हैं. संजीव कुमार गोंड के रूप में किसी अनुसूचित जनजाति से संबंध रखने वाले नेता को मंत्रिमंडल में शामिल कर भाजपा ने आदिवासियों और वनवासियों का समर्थन बटोरने की रणनीति बनाई है. सोनभद्र से आने वाले संजीव कुमार गोंड भाजपा के लिए इसलिए भी जरूरी हैं कि इसी जिले में उम्भा गांव में हुए नरसंहार में 10 आदिवासी मारे गए थे. इसके बाद से आदिवासी समाज में भाजपा के खिलाफ नाराजगी पनप रही थी जिसका फायदा उठाने की जुगत में विपक्षी दल लगे हुए थे. योगी मंत्रिमंडल विस्तार से यह स्पष्ट हो गया कि भाजपा वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में पिछड़ी जातियों पर दांव लगाने में काई चूक नहीं करना चाहती है. बरेली से भाजपा के सांसद संतोष गंगवार के मोदी मंत्रिमंडल से हटाए जाने के बाद रुहेलखंड इलाके के कुर्मी समुदाय में नाराजगी पनप रही थी. इसी नाराजगी को दूर करने के लिए भाजपा ने बरेली से आने वाले छत्रपाल गंगवार को योगी मंत्रिमंडल में शामिल किया है. योगी मंत्रिमंडल विस्तार को विपक्ष महज जनता का ध्यान बांटने वाली कवायद बता रहा है. कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत कहते हैं, ''अगले विधानसभा चुनाव में योगी सरकार के पास जनता को बताने के लिए कोई काम नहीं है. ऐसे में वह चेहरे के पीछे अपनी नाकामी छिपाना चाहती है लेकिन जनता भाजपा की चाल को समझ चुकी है.''

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपनी टीम में क्षेत्रीय संतुलन बनाने की भी कोशिश की है. मंत्रिमंडल विस्तार में पश्चिमी यूपी के जिले शाहजहांपुर, आगरा, मेरठ और बरेली से एक-एक मंत्री बनाया गया है. जबकि पूर्वांचल के गाजीपुर, सोनभद्र और अवध के बलरामपुर से एक मंत्री बनाया गया है. योगी सरकार में मंत्रिमंडल का पहला विस्तार 22 अगस्त, 2019 को हुआ था. उसय समय मंत्रिमंडल की सदस्य संख्या 56 हुई थीं. उसमें 25 कैबिनेट, 9 राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार और 22 राज्यमंत्री थे. लेकिन बीते डेढ़ वर्ष में कोरोना संक्रमण से कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान, कमला रानी वरुण और राज्यमंत्री विजय कश्यप का निधन होने से तीन पद खाली हो गए थे. योगी मंत्रिमंडल विस्तार के बाद पहली बार प्रदेश सरकार में मंत्रियों की संख्या 60 हो गई है. योगी सरकार में अब 24 कैबिनेट मंत्री, 9 राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार, 27 राज्यमंत्री हैं. योगी मंत्रिमंडल में चार महिला मंत्रियों की संख्या बरकरार रखी गई है. दिवंगत कमला रानी वरुण के निधन के बाद गाजीपुर विधायक डॉ. संगीता बलवंद बिंद को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है. नीमिला कटियार, स्वाति सिंह और गुलाबदेवी पहले से मंत्रिमंडल में शामिल हैं.

भाजपा ने विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) के लिए शाहजहांपुर के जितिन प्रसाद, शामली के चौधरी वीरेंद्र सिंह गुर्जर, गोरखपुर के निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद और मुरादाबाद के गोपाल अंजान भुर्जी के नाम पर मुहर लगा दी है. साकेत कॉलेज, अयोध्या के पूर्व प्राचार्य वी.एन. अरोरा बताते हैं, ''योगी मंत्रिमंडल विस्तार में सरकार ने सोशल इंजीनियरिंग के साथ क्षेत्रीय समीकरण का भी खासा ध्यान रखा है. भाजपा ने पहली बार अनुसूचित जनजाति के नेता को मंत्री बनाने के साथ पहली बार भुर्जी समुदाय के नेता को एमएलसी बनाने की संस्तुति करके सामाजिक संतुलन साधने का भरसक प्रयास किया है.'' संजय निषाद को एमएलसी बनाने की संस्तुति कर भाजपा ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की भरपाई करने की कोशिश की है. वर्ष 2017 में ओम प्रकाश राजभर ने भाजपा के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ा था लेकिन वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद वे योगी मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिए गए थे. इसके बाद से ओम प्रकार राजभर भाजपा के विरोध में भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाकर राजभर के अलावा प्रजापति, बिंद, पाल, कश्यप जैसी अति पिछड़ी जातियों पर अधारित क्षेत्रीय दलों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं. इसी काट के लिए भाजपा ने योगी सरकार में बिंद, गुर्जर, गडरिया, निषाद, चौहान, सैनी, लोध जैसी पिछड़ी जातियों के नेताओं के मंत्री के रूप में शामिल किया है.

योगी आदित्यनाथ सरकार के मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय और सामाजिक समीकरणों का गुलदस्ता वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में कितनी सुगंध बिखेरता है, यह चुनाव के नतीजे ही बता पाएंगे. ■

योगी मंत्रिमंडल का जातीय संतुलन

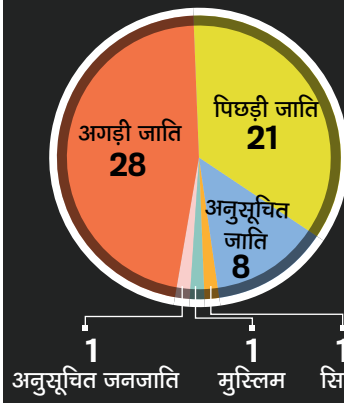

नोटः योगी मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या 60 हैं

अगड़ी जातियों का प्रतिनिधित्व
(कुल मंत्रियों की संख्या 28)

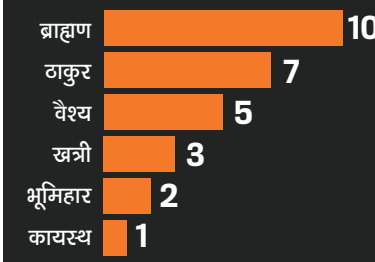

पिछड़ी जातियों का प्रतिनिधित्व
(कुल मंत्रियों की संख्या 21)

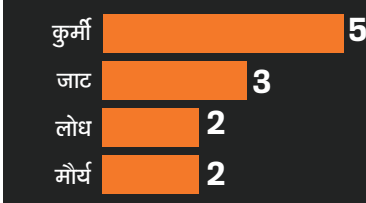

(बिंद, गुर्जर, गडरिया, कंहार, निषाद, चौहान, सैनी, यादव राजभर जाति के एक-एक मंत्री)

- अनुसूचित जाति के मंत्रियों की संख्या 8
- अनुसूचित जनजाति के मंत्रियों की संख्या 1
- महिला मंत्रियों की संख्या 4

ग्राफिकः असित रॉय

INDIA TODAY CONCLAVE 2021

8/9 OCT
NEW DELHI

INDIA TODAY GROUP

TOM FRIEDMAN

GLOBAL TREND DINER | 3-TIME PULITZER WINNER

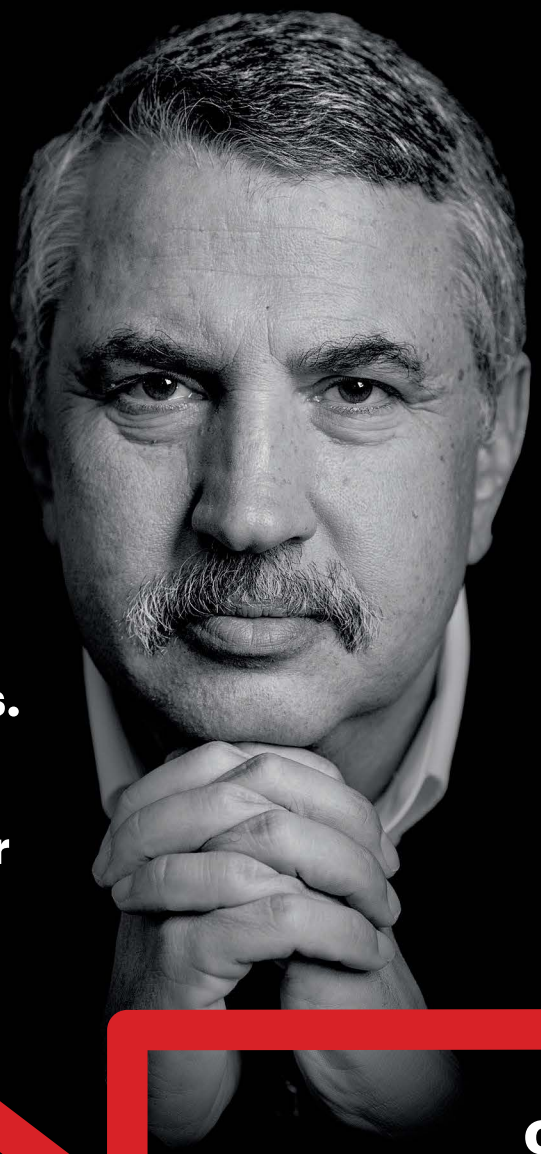

On shifting global dynamics. A diminished America. And rethinking super power in the 21st century

GEO-POLITICS

#ABetterNormal

PRESENTING SPONSOR

ITC Enduring Value

CONCLAVE PARTNERS

HINDUSTAN POWER | Darwin DARWIN PLATFORM GROUP OF COMPANIES VISIONARIES

KNOWLEDGE PARTNER

JGI JAIN DEEMED-TO-BE UNIVERSITY

BANKING PARTNER

IDFC FIRST Bank
ALWAYS YOU FIRST

LUXURY MOBILITY PARTNER

BMW

STATE PARTNER

उत्तर प्रदेश सरकार

INSURANCE PARTNER

LIC भारतीय जीवन बीमा निगम LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

PARTNER

SHRIRAM Transport Finance Company Limited
A WINNING RELATIONSHIP

CELEBRATION PARTNER

THE GLENLIVET BOOKS

BESPOKE PARTNER

DA MILANO ITALIA

चंद्रदीप कुमार

हाथ का साथ
28 सितंबर को कांग्रेस में शामिल होने के बाद कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवाणी (नीली शर्ट में)

बिहार

कांग्रेस की नजर युवाओं पर

अमिताभ श्रीवास्तव

कांग्रेस में जिस दिन पंजाब में घमासान मचा हुआ था, उसी दिन दिल्ली में पार्टी एक अन्य महत्वाकांक्षी योजना के साथ आगे बढ़ रही थी. 28 सितंबर की दोपहर राहुल गांधी की उपस्थिति में पार्टी ने दो होनहार युवा नेताओं का स्वागत किया—34 वर्षीय कन्हैया कुमार और गुजरात के 38 वर्षीय दलित विधायक जिग्नेश मेवाणी.

बताया जाता है कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को गांधी भाई-बहन ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले लेटरल एंट्री के जरिए एक नई और युवा टीम का खाका तैयार करने को कहा है कन्हैया का शामिल होना और मेवाणी का समर्थन देना भविष्य की उस बड़ी योजना की पहली झलक हो सकता है. 2014 और 2019 में लगातार दो आम चुनावों में बुरी तरह हार के बाद पार्टी को यह एहसास है कि उसे दिखावटी बदलावों की नहीं बल्कि आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है और उसके लिए नए सिरे से पार्टी का गठन करना होगा. पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की जगह एक दलित को मुख्यमंत्री बनाकर यह दिखाने की कोशिश की गई है कि कांग्रेस जोखिम लेने से हिचकेगी नहीं (हालांकि राज्य में मची खींचतान से इस रणनीति के गलत साबित होने का जोखिम भी बना हुआ है) और कन्हैया तथा मेवाणी को लेकर आना दिखाता है कि पार्टी जड़ से बदलाव को तैयार है. ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद और सुष्मिता देव जैसे कई युवा नेताओं ने इसे छोड़कर राजनैतिक रूप से सुरक्षित जगहें तलाश लीं तो कहा जाने लगा कि कांग्रेस एक डूबता जहाज है. नए और युवा नेताओं के आने से कांग्रेस को इस धारणा को खत्म करने में भी मदद मिलेगी.

बिहार के लिए कन्हैया के शामिल होने का क्या मतलब है? नाम जाहिर न किए जाने की शर्त पर पटना में कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता कहते हैं, ''कन्हैया कुमार का पार्टी में शामिल होना निश्चित रूप से बिहार में कांग्रेस के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी. हमारे पास आखिरी करिश्माई नेता जगन्नाथ मिश्रा थे, जो 1990 में बिहार के मुख्यमंत्री थे जब लालू प्रसाद यादव

INDIA TODAY CONCLAVE 2021

8/9 OCT
NEW DELHI

INDIA TODAY GROUP

ADAR POONAWALA

VACCINE ANGEL | CEO, SERUM INSTITUTE

On fighting a pandemic. And the highs and lows of producing a human shield for the world

WAR ON DISEASE
#ABetterNormal

PRESENTING SPONSOR

ITC
Enduring Value

CONCLAVE PARTNERS

HINDUSTAN POWER | Darwin DARWIN PLATFORM GROUP OF COMPANIES VISIONARIES

KNOWLEDGE PARTNER

JGI JAIN DEEMED-TO-BE UNIVERSITY

BANKING PARTNER

IDFC FIRST Bank
ALWAYS YOU FIRST

LUXURY MOBILITY PARTNER

BMW

STATE PARTNER

उत्तर प्रदेश सरकार

INSURANCE PARTNER

LIC भारतीय जीवन बीमा निगम LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

PARTNER

SHRIRAM Transport Finance Company Limited
A WINNING RELATIONSHIP

CELEBRATION PARTNER

THE GLENLIVET BOOKS

BESPOKE PARTNER

DA MILANO ITALIA

ने उनसे सत्ता छीन ली थी. तब से, पार्टी सिर्फ चुनाव प्रबंधकों के भरोसे चल रही है. कन्हैया निश्चित रूप से बिहार कांग्रेस में एक नया जोश भरेंगे, एक नए दौर की शुरुआत करेंगे. उनकी बात शहरी युवाओं या हिंदी पट्टी के ग्रामीणों पर असर छोड़ती है.''

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया उस समय सुर्खियों में आए जब अफजल गुरु की तीसरी बरसी के उपलक्ष्य में फरवरी 2016 में आयोजित एक कार्यक्रम में कथित रूप से 'राष्ट्र-विरोधी' नारे लगाने के लिए उन पर देशद्रोह का आरोप लगाया गया था. बाद में वे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो गए और उन्होंने बेगूसराय निर्वाचन क्षेत्र से 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा. लेकिन भाजपा के गिरिराज सिंह के हाथों उन्हें करारी हार मिली. कन्हैया 4,00,000 से अधिक मतों के अंतर से हारे थे.

पहले ही चुनाव में ऐसी बड़ी हार झेल चुके कन्हैया, बिहार में कांग्रेस को फिर से खड़ा करने में कितने सफल हो पाएंगे? पार्टी, राज्य में लगातार कमजोर हो रही है. वर्ष 2020 में राष्ट्रीय जनता दल और वाम दलों के साथ गठबंधन में यह 70 विधानसभा सीटों पर लड़ी लेकिन केवल 19 सीटें जीत सकी, जो 2015 की तुलना में आठ कम है. बिहार कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष मदन मोहन झा ने पार्टी के खराब प्रदर्शन के बाद अपना पद छोड़ने की पेशकश भी की थी. बिहार में सरकार बनाने से 12 सीटें पीछे रह जाने का ठीकरा, राजद ने कांग्रेस के माथे फोड़ा था.

1990 के दशक तक कांग्रेस ने अगड़ों, दलितों और मुसलमान मतदाताओं को अपने साथ जोड़कर बिहार पर शासन किया. हालांकि, लालू प्रसाद यादव के राजद और नीतीश कुमार के जनता दल (यूनाइटेड) के उदय के साथ, इसका वोट बैंक फिसलकर क्षेत्रीय दलों में चला गया. जहां दलित और मुसलमान राजद और जद (यू) के साथ चले गए, वहीं अधिकांश अगड़े मतदाता भाजपा के करीब हो गए. अपनी शक्ति और प्रभाव कम होने के साथ, कांग्रेस के पास बिहार में लालू के ओबीसी (15 प्रतिशत) और मुसलमानों (16 प्रतिशत) के मजबूत समर्थन आधार पर अपना कंधा टिकाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प शेष नहीं था. बिहार में वापसी के लिए, कांग्रेस और कन्हैया को राजद से अलग एक राह तलाशनी होगी. वैसे भी कन्हैया को तेजस्वी यादव के नेतृत्व के लिए चुनौती माना जा रहा है बेगूसराय में उनकी बड़ी हार की वजह राजद बताया जाता है. क्योंकि राजद ने अपना उम्मीदवार वापस लेने से इनकार कर दिया था, जिससे मुकाबला त्रिकोणीय हो गया था कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता के अनुसार, केंद्रीय नेतृत्व राज्य में नेताओं के बीच गतिरोध और खराब नेतृत्व के साथ-साथ मतदाताओं के कांग्रेस से बढ़ते मोहभंग और असंतोष को लेकर चौकन्ना हो गया है. कन्हैया के रूप में कांग्रेस के पास एक ऐसा युवा नेता होगा जिसकी पहुंच और अपील बड़ी है और राज्य में पार्टी के पुनर्निर्माण के लिए इसकी बड़ी जरूरत है. राहुल गांधी, पार्टी के भीतर बड़े संगठनात्मक बदलाव लाने के लिए प्रयासरत हैं और वे कन्हैया को संगठन-निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका सौंप सकते हैं. और अगर कांग्रेस को बिहार में एक ऊर्जस्वी चेहरे की जरूरत है तो कन्हैया कुमार का भी अपनी पिछली पार्टी भाकपा से मोहभंग हो चुका था. उन्हें लगने लगा था कि भारत की वर्तमान राजनैतिक वास्तविकताओं के बीच वे सीमित संगठन शक्ति वाली भाकपा के साथ अपना अच्छा राजनैतिक भविष्य नहीं दे पा रहे थे.

राष्ट्र निर्माताओं को नमन
कन्हैया कुमार, राहुल गांधी को राष्ट्र निर्माताओं की तस्वीर भेंट करते हुए

एएनआइ

कन्हैया कुमार के रूप में कांग्रेस के पास बिहार में पार्टी को नए सिरे से खड़ा करने के लिए एक ऊर्जावान नेता आ गया है. इसके लिए पार्टी को उन्हें पूरी आजादी देनी होगी

हालांकि, बिहार में बदलाव लाने के लिए कन्हैया कुमार को पूरी आजादी देनी होगी. वे वाकपटु हैं और हर जाति, धर्म और क्षेत्र में उनके लिए एक अपील है, लेकिन वे अपनी इन क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल तभी कर पाएंगे अगर उन्हें काम करने की पूरी आजादी दी जाए. यह तथ्य कि राज्य में अगला विधानसभा चुनाव चार साल दूर है, कांग्रेस और कन्हैया कुमार, दोनों को राज्य में पार्टी को नए सिरे से खड़ा करने के लिए भरपूर समय मिलेगा.

जुलाई में, राहुल गांधी ने नई दिल्ली में अपने आवास पर विधायकों सहित बिहार के कम से कम 35 नेताओं से पूरे दिन मुलाकात की थी, जिससे अटकलें तेज हो गईं कि उन्होंने आखिरकार 40 लोकसभा सांसदों वाले राज्य बिहार पर ध्यान देना शुरू कर दिया है. हालांकि कांग्रेस नेतृत्व लंबे समय से राज्य में पार्टी को पुनर्जीवित करना चाहता था, लेकिन उसके पास अपनी योजना को लागू करने के लिए योग्य नेता नहीं थे. अब कन्हैया के पार्टी में शामिल होने के बाद वे अपनी योजना पर अमल कर सकते हैं.

संयोग से, माना जाता है कि कांग्रेस में शामिल होने से एक महीने पहले, कन्हैया कुमार ने पटना में भाकपा कार्यालय से वह एयर कंडिशनर निकलवा लिया था जो उन्होंने लगवाया था. अब यह यूथ आइकन कांग्रेसी हो चुके हैं और बिहार में राजनैतिक तापमान बढ़ाने के लिए तैयार हैं. लेकिन नई पार्टी में तापमान को नियंत्रित रखने के लिए उन्हें भी अपने दिमाग को ठंडा रखने की जरूरत पड़ने वाली है. ■

INDIA TODAY CONCLAVE 2021

8/9 OCT
NEW DELHI

INDIA TODAY GROUP

J.P. NADDA

FAMILY MAN | PRESIDENT, BJP

On high-octane elections. And the internal machinery of the world's largest political party

POLITICS

#ABetterNormal

PRESENTING SPONSOR

ITC
Enduring Value

CONCLAVE PARTNERS

HINDUSTAN POWER

Darwin
DARWIN PLATFORM GROUP OF COMPANIES
VISIONARIES

KNOWLEDGE PARTNER

JGI JAIN
DEEMED-TO-BE UNIVERSITY

BANKING PARTNER

IDFC FIRST Bank
ALWAYS YOU FIRST

LUXURY MOBILITY PARTNER

BMW

STATE PARTNER

उत्तर प्रदेश सरकार

INSURANCE PARTNER

LIC
भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

PARTNER

SHRIRAM
Transport Finance Company Limited
A WINNING RELATIONSHIP

CELEBRATION PARTNER

THE GLENLIVET
BOOKS

BESPOKE PARTNER

DA MILANO
ITALIA

तृणमूल बनाम ईडी/सीबीआइ

तो क्या अब होकर ही रहेगी मुठभेड़?

रोमिता दत्ता

पश्चिम बंगाल में कोयले की अवैध तस्करी से जुड़े धनशोधन मामले में तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को महज दो हफ्ते के भीतर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से सितंबर के शुरू में तीसरा सम्मन मिला. उन्हें 21 सितंबर को ईडी के नई दिल्ली दफ्तर में पेश होने को कहा गया था. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक ने 6 सितंबर को ईडी अधिकारियों की नौ घंटे की पूछताछ झेली थी और 8 सितंबर की पेशी के लिए अगले सम्मन को यह कहकर नजरअंदाज कर दिया कि बहुत कम समय का नोटिस दिया गया.

ईडी ने 1 सितंबर को नारद स्टिंग ऑपरेशन मामले में तृणमूल के मंत्रियों फरहाद हाकिम और सुब्रत मुखर्जी, पार्टी के विधायक मदन मित्रा, कोलकाता के पूर्व मेयर सोभन चटर्जी और पूर्व आइपीएस अधिकारी एस.एम.एच मिर्जा के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था. 14 सितंबर को उसने कोयला तस्करी मामले में कानून मंत्री मलय घटक को तलब किया था. एक दिन पहले ही सीबीआइ (केंद्रीय जांच ब्यूरो) ने उद्योग मंत्री पार्थ चटर्जी से 2015 के आइ-कोर चिट फंड मामले में पूछताछ की थी.

केंद्रीय जांच एजेंसियों की ये ताबड़तोड़ गतिविधियां 30 सितंबर को बहुप्रतीक्षित भवानीपुर विधानसभा उपचुनाव से ऐन पहले की हैं, जिसमें ममता चुनाव लड़ रही हैं. उन्हें विधानसभा में पहुंचने और मुख्यमंत्री का पद बरकरार रखने को इसे जीतना जरूरी है. तृणमूल के नेता ईडी की कार्रवाई को महज संयोग नहीं मानते. वे इसे राजनैतिक प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों के इस्तेमाल की भाजपा की चिरपरिचित चाल के रूप में देख रहे हैं. वे मिसाल देते हैं कि बंगाल में आठ चरणों में विधानसभा चुनाव शुरू होने से ठीक महीने भर पहले अभिषेक की पत्नी रुजिरा से सीबीआइ ने कोयले की अवैध तस्करी के मामले में पूछताछ की और विधानसभा चुनाव में 2 मई को पार्टी की शानदार जीत के ठीक बाद तृणमूल के चार वरिष्ठ नेताओं को नारद घोटाले में गिरफ्तार कर लिया गया.

नारद मामला 2016 में नारद न्यूज नाम की समाचार वेबसाइट पर प्रकाशित एक स्टिंग ऑपरेशन की फुटेज से जुड़ा है, जिसमें सांसदों और मंत्रियों समेत तृणमूल के 12 नेताओं

डरने वाला नहीं
अभिषेक बनर्जी दिल्ली में 6 सितंबर को ईडी की पूछताछ के बाद मीडिया से बात करते हुए

आकाश अंशुमान

INDIA TODAY CONCLAVE 2021

8/9 OCT
NEW DELHI

INDIA TODAY GROUP

GENERAL M.M. NARAVANE

NATIONAL SHIELD | CHIEF OF THE ARMY STAFF, INDIA

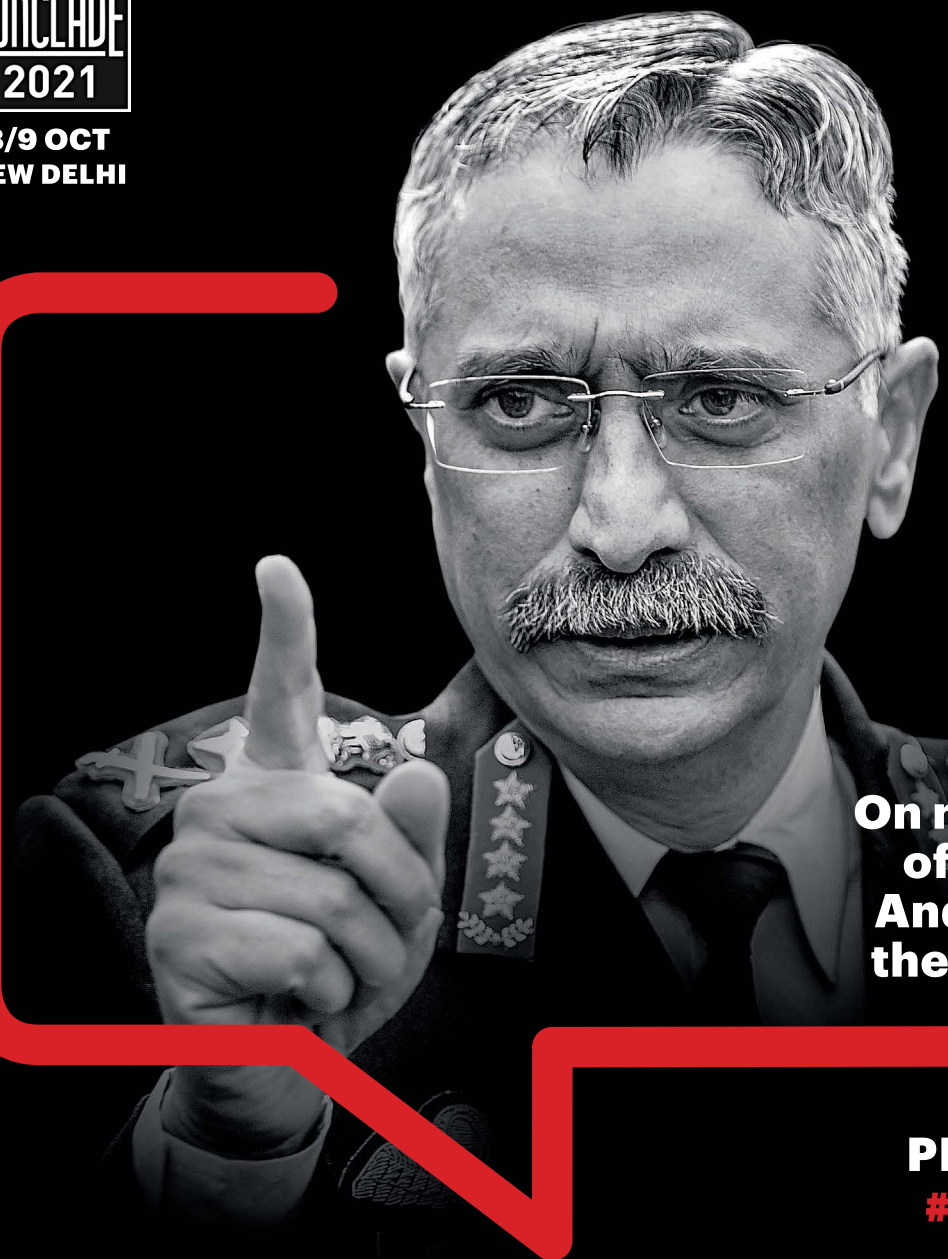

On new theatres of aggression. And insights on the Indian army

PEACE-KEEPING

#ABetterNormal

PRESENTING SPONSOR

ITC
Enduring Value

CONCLAVE PARTNERS

HINDUSTAN POWER

Darwin
DARWIN PLATFORM GROUP OF COMPANIES
VISIONARIES

KNOWLEDGE PARTNER

JGI JAIN
DEEMED-TO-BE UNIVERSITY

BANKING PARTNER

IDFC FIRST Bank
ALWAYS YOU FIRST

LUXURY MOBILITY PARTNER

BMW

STATE PARTNER

INSURANCE PARTNER

LIC
भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

PARTNER

SHRIRAM
Transport Finance Company Limited
A WINNING RELATIONSHIP

CELEBRATION PARTNER

THE GLENLIVET
BOOKS

BESPOKE PARTNER

DA MILANO
ITALIA

को एक काल्पनिक कंपनी इम्पेक्स कंसल्टेंसी सॉल्यूशंस की ओर से कथित तौर पर रिश्वत के बदले समर्थन का वादा करते दिखाया गया है. इस मामले की 2017 से जांच कर रही सीबीआइ ने अभियुक्तों पर भारतीय दंड संहिता (आइपीसी) और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की विभिन्न धाराओं के तहत मामले दर्ज किए हैं. ईडी के आरोपपत्र में फंदा कस दिया गया है—काला धन शोधन निरोधक कानून के तहत लगाए गए आरोपों में तीन से सात साल के सश्रम कारावास की सजा का प्रावधान है.

तृणमूल प्रतिशोध की राजनीति का हल्ला इसलिए भी ज्यादा कर रही है क्योंकि नारद घोटाले में एक और अभियुक्त —भाजपा के सुभेंदु अधिकारी के खिलाफ लंबे अरसे से कार्रवाई लंबित है. 2014 में स्टिंग के समय वे तृणमूल के सांसद थे. इस साल विधानसभा चुनाव से पूर्व वे भाजपा में शामिल हो गए और उन्होंने नंदीग्राम सीट से ममता को हरा दिया.

ममता की पार्टी का आरोप है कि लोकसभा अध्यक्ष की लंबित मंजूरी के बहाने अधिकारी को बचाया जा रहा है; लेकिन केंद्रीय एजेंसियों ने तृणमूल विधायकों और मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई से पहले बंगाल विधानसभा अध्यक्ष की मंजूरी लेने की जहमत नहीं की. नारद जांच से जुड़े, ईडी टीम के एक वरिष्ठ अधिकारी नाम न छापने की शर्त पर बताते हैं, ''आरोपपत्र तैयार करने में भेदभाव से मामला कमजोर हो जाता है, खासकर जब हमारे पास अभियुक्तों के खिलाफ ठोस सबूत थे. इससे विपक्ष को राजनैतिक पूर्वाग्रह का आरोप लगाने का आधार भी मिल जाता है.''

काला धन शोधन के जिस मामले में अभिषेक और उनकी पत्नी से पूछताछ हो रही है उसकी जांच नवंबर 2020 में बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले शुरू हुई थी. एक ओर जहां बंगाल में ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड (ईसीएल) की खानों से तस्करी के लिए अवैध खनन का मामला दशकों से चल रहा है, वहीं जांचकर्ताओं का मानना है कि यह तृणमूल के शासन में संगठित घोटाले में तब्दील हो गया है, जिससे अभिषेक और पार्टी के दूसरे नेताओं को कथित लाभ मिल रहा है. तृणमूल इस आरोप को खारिज करती है.

इस मामले में एक स्थानीय ठेकेदार अनूप माझी कथित तौर पर मुख्य संदिग्ध है. उसने कोयले की तस्करी करने के लिए तृणमूल यूथ कांग्रेस के नेता विनय मिश्र और पुलिस अधिकारी अशोक मिश्र से कथित तौर पर मदद ली. माझी को सुरक्षा देने की एवज में विनय और अशोक ने कथित तौर पर रिश्वत ली और रिश्वत का कुछ पैसा इधर-उधर कर दिया. ईडी 1,300 करोड़ रुपए के लेनदेन का हवाला देती है, जिसमें से कथित तौर पर आधे विनय को गए. उसने यह रकम कथित तौर पर देश में और थाइलैंड तथा लंदन के विभिन्न खातों में जमा करा दी. अभिषेक का करीबी माना जाने वाला विनय फरार है. उसकी तलाश का नोटिस जनवरी में जारी कर दिया गया.

ममता का दावा है कि भाजपा विधानसभा चुनाव में अपनी हार का बदला लेने के लिए अभिषेक को निशाना बना रही है. उन्होंने कहा, ''भाजपा और केंद्र सरकार हमसे राजनैतिक रूप से नहीं लड़ सकती. वे हमारे नेताओं के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर रहे हैं. मैं ऐसे दर्जनों केंद्रीय मंत्रियों को जानती हूं जिन्होंने आसनसोल के कोयला क्षेत्र को लूटा है.'' अभिषेक ने 27 सितंबर को ईडी को चुनौती दी कि वह उन्हें और उनकी पत्नी रिजुरा को गिरफ्तार करके तो दिखाए. दिल्ली में 6 सितंबर को पूछताछ के बाद उन्होंने भाजपा को खुली चुनौती दी: ''तृणमूल दूसरे राज्यों में विस्तार करेगी और उन्हें आपसे (भाजपा से) छीनेगी.''

तृणमूल प्रतिशोध की राजनीति का मसला इसलिए जोर-शोर से उठा रही है क्योंकि नारद घोटाले के एक अन्य अभियुक्त भाजपा के शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई अभी लंबित है

लेकिन कोयले की तस्करी और नारद मामलों की जांच कर रहे एक अधिकारी का कहना है कि किसी अभियुक्त को बार-बार बुलाया जाना उसके खिलाफ मामले की गंभीरता का संकेत हो सकता है. उस अधिकारी ने बताया, ''ईडी हाथ गंदे नहीं करती जब तक उसे काला धन शोधन का ठोस सबूत नहीं मिल जाता, और अगर वह हवाला कारोबार से जुड़ा हो तो और भी गंभीर हो जाता है. हमें यकीन है कि नारद घोटाले में घोटाले का पहलू है.''

बंगाल विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी ने मंत्रियों और विधायकों के खिलाफ उनकी अनुमति लिए बगैर नारद मामले में आरोपपत्र तैयार करने के सिलसिले में ईडी के अधिकारियों को हाल में तलब किया था. पर कानून के कुछ जानकारों का मानना है कि विधानसभा अध्यक्ष की मंजूरी जरूरी नहीं. माकपा के राज्यसभा सांसद और वकील बिकास रंजन भट्टाचार्य का कहना है, ''विधानसभा अध्यक्ष अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर चले गए. जांच और आरोपपत्र दाखिल करने का काम अदालत के आदेशों से हो रहा है.''

दिलचस्प है कि केंद्रीय एजेंसियां नारद घोटाले के छह अभियुक्त सांसदों—पांच तृणमूल के और अधिकारी—के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति का इंतजार कर रही हैं. अनुमति की अर्जी 2107 से ही लोकसभा अध्यक्ष के पास पड़ी है.

पिछले साल जुलाई में भट्टाचार्य ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से लंबित अनुमति के बारे में पता किया था और उन्हें एक महीने के भीतर प्रतिक्रिया देने का आश्वासन दिया गया था. वे कहते हैं, ''मैंने इस साल अगस्त में कोलकाता हाइकोर्ट में यह जानने के लिए एक याचिका दायर की कि नारद घोटाले के अभियुक्त सांसदों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल करने में जांच एजेंसियां देर क्यों कर रही हैं.''

इस बीच, अधिकारी दिल्ली का बार-बार दौरा कर रहे हैं. वे विभिन्न दूसरे मंत्रियों के अलावा जून से अब तक तीन बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर चुके हैं. जुलाई में अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने भारत के महाधिवक्ता तुषार मेहता से मुलाकात की. तृणमूल का कहना है कि अधिकारी की राजनैतिक संबद्धता के मद्देनजर केंद्रीय जांच एजेंसियां उन्हें बहुत छूट दे रही हैं. पार्टी प्रवक्ता कुणाल घोष पूछते हैं, ''ईडी ने आरोपपत्र में अधिकारी का नाम शामिल क्यों नहीं किया? क्या वह विशेष रूप से सिर्फ तृणमूल नेताओं या भाजपा छोड़ चुके लोगों को ही नामित कर रही है?''

इन दोनों मामलों में जांच को लेकर तृणमूल और भाजपा एक-दूसरे पर कीचड़ उछाल रही हैं, जिससे आने वाले कुछ महीनों तक बंगाल में राजनैतिक पारा चढ़ा रहना तय है. लेकिन 3 अक्तूबर को भवानीपुर उपचुनाव का नतीजा आने के साथ ही यह तय हो जाएगा कि निकट भविष्य में किसे बढ़त हासिल रहेगी. ■

INDIA TODAY CONCLAVE 2021

8/9 OCT
NEW DELHI

INDIA TODAY GROUP

BASAVARAJ BOMMAI

SOUTHERN BRIDGE | CHIEF MINISTER, KARNATAKA

On the BJP's agenda. And breaching the south

POLITICS

#ABetterNormal

PRESENTING SPONSOR

ITC Enduring Value

CONCLAVE PARTNERS

HINDUSTAN POWER | Darwin Platform Group of Companies VISIONARIES

KNOWLEDGE PARTNER

JGI JAIN DEEMED-TO-BE UNIVERSITY

BANKING PARTNER

IDFC FIRST Bank
ALWAYS YOU FIRST

LUXURY MOBILITY PARTNER

BMW

STATE PARTNER

INSURANCE PARTNER

LIC भारतीय जीवन बीमा निगम LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

PARTNER

SHRIRAM Transport Finance Company Limited
A WINNING RELATIONSHIP

CELEBRATION PARTNER

THE GLENLIVET BOOKS

BESPOKE PARTNER

DA MILANO ITALIA

लगातार उछाल
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने 24 सितंबर को जब 60,000 का आंकड़ा छुआ

फ्रांसिस मैसकरेनहस/रॉयटर्स

शेयर बाजार

लगातार ऊपर चढ़ता सेंसेक्स

एम.जी. अरुण

बीते 24 सितंबर को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) से जुड़े सेंसेक्स ने 60,000 का आंकड़ा छू लिया जो पिछले कुछ महीनों से ज्यादातर तेजी का रुख दिखा रहे भारतीय शेयर बाजारों का नया उच्चतम बिंदु और बाजार के लिए उत्साह का क्षण है. इस साल सेंसेक्स की बढ़त का सिलसिला पिछले साल पहली बार 28 फरवरी को 1,448 अंकों की एक दिन से सबसे बड़ी गिरावट में से एक और फिर कोविड-19 मामले बढ़ने पर 23 मार्च को लॉकडाउन की घोषणा के फलस्वरूप एक में दिन में 3,935 अंकों की सबसे बड़ी गिरावट के बाद शुरू हुआ है.

हालांकि 2020 के उत्तरार्ध में सेंसेक्स तेजी से ऊपर गया था और दिसंबर में इस संवेदी सूचकांक ने 45,000 का स्तर पा लिया था. फिर यह बढ़ता हुआ इस साल 21 जनवरी को 50,000 को भी पार कर गया. तब से अब तक सेंसेक्स को और 10,000 अंकों की बढ़त हासिल करने में सिर्फ आठ महीने लगे और—27 सितंबर को सेंसेक्स 60,077 पर बंद हुआ. समाचारों के मुताबिक, हालांकि 10,000 अंकों की इस बढ़त का आधा हिस्सा तो 30 में से सिर्फ पांच स्टॉक की भूमिका है, विशेषज्ञों का कहना है कि यह उछाल चौतरफा है.

जो बात किसी हद तक उल्टी लगती है, वह यह कि जब अर्थव्यवस्था महामारी से बुरी तरह तबाह हो गई है तब सेंसेक्स के हवाले से दिख रहा शेयर बाजार ऊपर कैसे चढ़ रहा है? पिछले साल भारतीय अर्थव्यवस्था बीते चार दशकों में पहली बार मंदी का शिकार हुई जिसके परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद 7.3 प्रतिशत की दर से घटा. देश में बेरोजगारी फैली है और विशाल अनौपचारिक क्षेत्र तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) जैसे क्षेत्र वापसी के लिए संघर्ष कर रहे हैं.

फिर भी, सेंसेक्स में उछाल की वजहें कहीं और हैं. उनमें से एक है औपचारिक क्षेत्र का प्रदर्शन जो कंपनियों के अच्छे वित्तीय परिणाम में दिखता है. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) के विश्लेषण के अनुसार, 2,610 कंपनियों ने अप्रैल-जून 2021 के बिक्री के आंकड़ों में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 61 प्रतिशत की बढ़त के साथ 9.87 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि दर्ज की. यहां तक कि बढ़ती लागत जैसे चुनौतियों के बीच कॉर्पोरेट क्षेत्र बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की छंटनी, वेतन में कटौती और यात्रा जैसे भार को कम करने जैसी लागत-कटौती उपायों का सहारा लेकर अपने मुनाफे की रक्षा करने में सक्षम रहा.

शेयर बाजार के प्रभावशाली प्रदर्शन का एक और बड़ा कारण रहा विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआइआइ) की दिलचस्पी: 2020-21 में भारतीय इक्विटी में एफआइआइ का कुल प्रवाह करीब 37.6 अरब डॉलर (करीब 2.78 लाख करोड़ रुपए) था—जो

INDIA TODAY CONCLAVE 2021

8/9 OCT
NEW DELHI

INDIA TODAY GROUP

HUSSAIN HAQQANI

POLITICAL SAVANT | AUTHOR, PAKISTANI DIPLOMAT

On the return of the Taliban. And the security implications for the world

INTERNATIONAL RELATIONS

#ABetterNormal

PRESENTING SPONSOR

ITC Enduring Value

CONCLAVE PARTNERS

HINDUSTAN POWER | Darwin — DARWIN PLATFORM GROUP OF COMPANIES — VISIONARIES

KNOWLEDGE PARTNER

JGI JAIN DEEMED-TO-BE UNIVERSITY

BANKING PARTNER

IDFC FIRST Bank — ALWAYS YOU FIRST

LUXURY MOBILITY PARTNER

BMW

STATE PARTNER

उत्तर प्रदेश सरकार

INSURANCE PARTNER

LIC — भारतीय जीवन बीमा निगम — LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

PARTNER

SHRIRAM Transport Finance Company Limited — A WINNING RELATIONSHIP

CELEBRATION PARTNER

THE GLENLIVET BOOKS

BESPOKE PARTNER

DA MILANO ITALIA

किसी भी वित्तीय वर्ष में अब तक का सबसे अधिक है. केजरीवाल रिसर्च ऐंड इनवेस्टमेंट सर्विसेज के संस्थापक अरुण केजरीवाल कहते हैं, ''अगस्त में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआइ) ने बिक्री ही बिक्री की, लेकिन सितंबर में उन्होंने लगातार खरीदारी की.'' बाजार में तरलता का एक नया दौर शुरू हो गया है. उनका कहना है कि पहले से अधिक पैसा उन्हीं शेयरों का पीछा कर रहा है जिससे बाजारों में तेजी आ रही है.

केवल बड़े पैसे वाले एफआइआइ ही भारतीय शेयर बाजार की ओर आकर्षित नहीं हुए हैं बल्कि व्यक्तिगत निवेशक, छोटे और बड़े दोनों, यहां आ रहे हैं. बॉन्ड और रियल एस्टेट जैसे निवेश के अन्य रास्ते निराशाजनक दिख रहे हैं और छोटे बचत साधनों पर ब्याज दरों में कमी आई है, फिर भी शेयर बाजार में बहुत सारे नए खुदरा निवेशक देखे गए हैं. भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआइ) की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2020-21 में जब कोविड-19 अर्थव्यवस्था को रौंद रहा था, तब 1.42 करोड़ नए व्यक्तिगत निवेशक शेयर बाजारों में शामिल हुए. महामारी के दौरान डीमैट खातों (सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों को रखने वाले खातों) की संख्या दोगुनी हो गई. बाजार नियामक सेबी के अनुसार, अप्रैल 2020 और जनवरी 2021 के बीच 1.07 करोड़ नए डीमैट खाते खोले गए. इसकी तुलना में 2019-20 में केवल 47 लाख नए डीमैट खाते खुले थे.

शेयर बाजारों में तेजी का दूसरा कारण बाजारों में बड़े पैमाने पर धन की उगाही है, जिसमें 38 कंपनियों ने इस कैलेंडर वर्ष में अगस्त तक 71,800 करोड़ रुपए जुटाए, जबकि 16 आइपीओ (प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश) से 2020 में 31,128 करोड़ रुपए की आवक हुई थी. बाजार से धन एकत्रित करने वाली फर्मों में जोमैटो जैसे स्टार्ट-अप भी शामिल हैं जिन्होंने ऑनलाइन ऑर्डरिंग में उछाल के नतीजतन महामारी के दौरान अच्छा प्रदर्शन किया है. विभिन्न फर्मों से बाहर निकलने के लिए सही समय की प्रतीक्षा कर रहे निजी इक्विटी निवेशकों को यह आदर्श मौका मिला है: केजरीवाल का कहना है कि बीते 15 महीनों में बाजार से जुटाई गई 75 फीसद रकम ऐसे निवेशकों के विनिवेश के जरिए आई है.

इसका एक अन्य कारक यह है कि दुनिया भर के देश 'चीन प्लस वन' रणनीति लागू कर रहे हैं जिससे विश्व मंच पर भारत की ओर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है. यह रणनीति महामारी का एक परिणाम है जिसमें दुनिया भर के व्यवसाय महसूस कर रहे हैं कि कच्चे माल के लिए एक ही देश (इस मामले में, चीन) पर निर्भर रहना उचित नहीं है. भारत इन कंपनियों का संभावित गंतव्य है और सरकार की हालिया नीतिगत बदलावों ने इन संभावनाओं को बढ़ाया है. मिसाल के तौर पर, सरकार की ओर निर्माताओं के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन, पूर्वव्यापी कराधान का समापन और दूरसंचार कंपनियों को बकाया भुगतान के लिए ज्यादा समय देना. शेयर बाजार में उत्साह के कुछ अन्य कारक हैं: अर्थव्यवस्था में नीची ब्याज दरें (उधार लेने को इच्छुक कंपनियों के लिए अच्छा है, जोखिम से बचने वाले व्यक्तिगत निवेशकों के लिए भले इतना अच्छा नहीं है जो अपनी बैंक जमा और छोटी बचत से अधिक चाहते हैं), तेजी से बढ़ता कमोडिटी चक्र, केंद्र और आरबीआइ के प्रोत्साहन उपाय और उम्मीद कि महामारी का सबसे बुरा दौर पीछे छूट गया है.

ऐसी चिंताएं हैं कि एवरग्रांडे संकट—जिसमें सरकार की मदद न मिलने पर चीन के सबसे बड़े रियल एस्टेट डेवलपर्स में से एक का पतन हो सकता है—और अगली फरवरी में बीजिंग में शीतकालीन ओलंपिक से पहले चीन की ओर से उत्सर्जन पर अंकुश लगाए जाने की वजह से आसन्न ऊर्जा संकट जैसी वैश्विक घटनाएं बाजार में 'सुधार' (डाउनस्विंग) का कारण बन सकती हैं. पर कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी के प्रबंध निदेशक नीलेश शाह जैसे विशेषज्ञों का कहना है कि एवरग्रांडे का मुद्दा काफी हद तक चीन तक ही सीमित रहेगा. वे कहते हैं, ''एवरग्रांडे वैश्विक समस्या से अधिक चीन की समस्या है.'' उन्हें लगता है कि ऐसा कोई संकट वास्तव में भारत के लिए एक अवसर हो सकता है, क्योंकि यह ''पूंजी आवंटनकर्ताओं को आश्वस्त कर सकता है कि चीन के विकल्प के रूप में उन्हें भारत में निवेश करने की आवश्यकता है.'' हालांकि वे बाजार में गिरावट से इनकार नहीं करते हैं, लेकिन उनका कहना है कि हर 'सुधार' पर खरीदारी करने का मौका भी मिलता है. दूसरों का कहना है कि 10 फीसद तक की भी गिरावट से बाजार को ज्यादा नुक्सान नहीं होगा. वैसे, लाभ कमाने को इच्छुक निवेशकों को सावधानी बरतनी चाहिए: अगर उनके पास सही स्टॉक चुनने की विशेषज्ञता नहीं है तो उन्हें अपने निवेश उद्देश्यों के साथ म्यूचुअल फंड पर विचार करना चाहिए या फिर अपनी ओर से निवेश करने के लिए अनुभवी पोर्टफोलियो प्रबंधकों को ढूंढना चाहिए. ■

बाजार में उछाल

भारतीय शेयर बाजार नें हाल में एफआइआइ और खुदरा, दोनों तरह के निवेशकों को लुभाया है

37.6
अरब डॉलर
वित्त वर्ष 2021 में एफआइआइ की कुल आमद

16.2
लाख करोड़ रु.
जून 2021 में रिटेल होल्डिंग का मूल्य, अब तक का सर्वाधिक

फायदे में भरोसा

अनौपचारिक क्षेत्र अभी भी डांवाडोल है, पर औपचारिक अर्थव्यवस्था ने जोर पकड़ लिया है

61%
वृद्धि हुई है 2,610 कंपनियों की बिक्री में जून 2020 के मुकाबले जून 2021 में

90,325
करोड़ रुपए
कुल लाभ इन कंपनियों का जून 2021 में, जून 2020 में 2,646 करोड़ रु. का घाटा हुआ था

1,000 से 60,000: सेंसेक्स का सफर

50,000 से 60,000 तक पहुंचने में सेंसेक्स को सिर्फ 166 ट्रेडिंग सत्र लगे

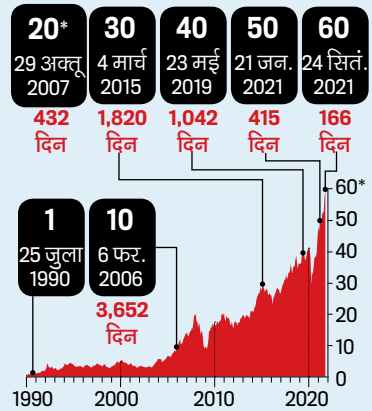

*आंकड़े हजार में

बाजार के वाहक

सेंसेक्स की 50,000 से 60,000 तक की यात्रा में पांच स्टॉक ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई (3 फरवरी और 24 सितंबर के बीच)

	बदलाव (%)	योगदान (अंक)
आरआइएल	29	1,646
इन्फोसिस	39	1,642
टीसीएस	22	652
आइसीआइसीआइ बैंक	16	644
बजाज फाइनेंस	49	617

स्रोतः ब्लूमबर्ग, बीएसई, आरबीआइ

INDIA TODAY CONCLAVE 2021

8/9 OCT
NEW DELHI

INDIA TODAY GROUP

NEERAJ CHOPRA & ABHINAV BINDRA

PSYCHE TRANSFORMERS | OLYMPIC GOLD MEDALLISTS

On reaching for the stars.
And the science of winning

ATHLETICISM
#ABetterNormal

PRESENTING SPONSOR

ITC
Enduring Value

CONCLAVE PARTNERS

HINDUSTAN POWER | Darwin DARWIN PLATFORM GROUP OF COMPANIES VISIONARIES

KNOWLEDGE PARTNER

JGI JAIN DEEMED-TO-BE UNIVERSITY

BANKING PARTNER

IDFC FIRST Bank
ALWAYS YOU FIRST

LUXURY MOBILITY PARTNER | STATE PARTNER | INSURANCE PARTNER | PARTNER | CELEBRATION PARTNER | BESPOKE PARTNER

BMW | उत्तर प्रदेश सरकार | LIC भारतीय जीवन बीमा निगम LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA | SHRIRAM Transport Finance Company Limited A WINNING RELATIONSHIP | THE GLENLIVET BOOKS | DA MILANO ITALIA

अर्थात्

कसौटियों की कसौटी

अंशुमान तिवारी

अगर आप भारत की सरकार को जिद्दी, नकचढ़ा और लापरवाह बच्चा मान लें तो यह बच्चा अब दुनिया के सबसे सख्त स्कूल में भर्ती होने जा रहा है. 2022 की शुरुआत में भारत सरकार के बॉन्ड ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स का हिस्सा हो जाएंगे. यह 1993 में भारतीय शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों के प्रवेश से कम क्रांतिकारी नहीं है, जिनके आने से शेयर बाजार की सूरत, सीरत और तबियत पूरी तरह बदल गई.

ग्लोबल बॉन्ड बाजार सरकारों का कमांडो ट्रेनिंग स्कूल है. सरकारों लिए यह बाजार इतना बेमुरव्वत क्यों है, इसके लिए हमें जेम्स कार्वाइल से मिलना होगा. बिल क्लिंटन को राष्ट्रपति की कुर्सी तक पहुंचाने वाले दुनिया के सबसे मशहूर राजनैतिक और चुनावी रणनीतिकार (प्रशांत किशोर के पेशे के स्टीव जॉब्स), कार्वाइल अब 76 साल के हो चले हैं. उन्होंने कहा था कि पहले मैं पोप या कि बेसबाल हिटर के तौर पर पुनर्जन्म लेना चाहता था लेकिन अब मैं बॉन्ड मार्केट के तौर पर वापस आना चाहूंगा, जो सरकारों को हमेशा डराता रहता है.

कार्वाइल बजा फरमाते हैं. इस स्कूल में बने रहने के लिए सरकारों को बुरी आदतें छोड़नी होती हैं. इस दिशा में पहला कदम बीते साल बजट में उठाया गया था जब सरकारी बॉन्ड और ट्रेजरी बिल में विदेशी निवेशकों के निवेश को खोल (फुली एक्ससेबल रूट) दिया गया.

भारत में सरकारी बॉन्ड का बाजार करीब एक ट्रिलियन डॉलर का है. अधिकांश निवेश सरकारी बैंकों (38%), सरकारी बीमा कंपनियां (25%), रिजर्व बैंक (16%), म्युचुअल फंड आदि, अन्य निवेशक (13%) प्रॉविडेंट फंड (4%) और कोऑपरेटिव (2%) का है. विदेशी निवेशक केवल दो फीसद हिस्सा रखते हैं.

भारत के सरकार के बॉन्ड को ग्लोबल सूचकांकों में शामिल कराने का रास्ता यूरोक्लियर (अंतरराष्ट्रीय क्लियरिंग हाउस डिपॉजिटरी) की मंजूरी यानी ग्लोबल सेटलमेंट नियमों के भारतीय बॉन्डों के प्रवेश से होकर जाता है. मोर्गन स्टेनले की एक ताजा रिपोर्ट बता रही है कि भारत सरकार के बॉन्ड को जेपीएम जीबीआइ-ईएम ग्लोबल डाइवर्सिफाइड इंडेक्स और ब्लूमबर्ग ग्लोबल एग्रीगेट इंडेक्स में जगह मिलेगी. प्रवेश का ऐलान अगले साल की पहली तिमाही में संभव है.

इन सूचकांकों के जरिए विदेशी निवेशक सरकारी बॉन्ड खरीद सकेंगे. ऊंचे ब्याज दर के कारण भारत का बाजार खासा आकर्षक है. मोर्गन का मानना है कि 2022 में करीब 40 अरब डॉलर की अतिरिक्त विदेशी पूंजी भारत आ सकती है. आगे भी सालाना करीब 18-20 अरब डॉलर आते रहेंगे. 2031 तक सरकारी बॉन्ड बाजार में विदेशी निवेशक करीब 9 फीसद (वर्तमान 2%) का हिस्सा से ले सकते हैं, जिसका मूल्य 190 अरब डॉलर होगा.

भारत सरकार दुनिया के सबसे सख्त निवेशकों के स्कूल में भर्ती होने जा रही है

भारत का अल्पविकसित बॉन्ड बाजार इस सुधार का इंतजार लंबे वक्त से कर रहा था. फायदों की सूची छोटी नहीं है.

- यह विदेशी निवेश सरकार के कर्ज कार्यक्रम का हिस्सा होगा, इसलिए सरकार के पास बजट बढ़ाने और घरेलू बैंकों के कर्ज को सीमित करने का विकल्प होगा
- इसके बाद सरकारें निवेश बढ़ाने और टैक्स कम करने का विकल्प चुन सकती हैं
- यह पूंजी बाजार में आकर ब्याज दरें कम रखने में मदद करेगी.
- रुपए में क्रमशः मजबूती व स्थिरता आने की संभावना है, जिसकी वजह यही पूंजी होगी जो विदेशी मुद्रा भंडार में आएगी
- सरकारी बॉन्ड बाजार में विदेशी सक्रियता के सहारे घरेलू कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार में निवेश बढ़ेगा
- शेयर बाजार पहले ही विदेशी निवेशकों से गुलजार है, बॉन्ड बाजार में बढ़ी साख इसे और ताकत देगी. भारत को संप्रभु रेटिंग अब बेहतर हो सकती है जो कबाड़ दर्जे से (जंक) से बस एक पायदान ऊपर है

लेकिन डायनासोरी सरकारी खर्च के लिए कर्ज देने वाला बॉन्ड मार्केट सरकारों की हेकड़ी छुड़ा देता है. यह कड़ा अनुशासन मांगता है. लापरवाही व कुप्रबंध पर आग बबूला निवेशक, बॉन्ड बेचने लगते हैं.

यही वजह है कि ग्लोबल इंडेक्स में भारत सरकार के बॉन्ड का प्रवेश, मौद्रिक और राजकोषीय व्यवस्था का नया प्रस्थान बिंदु है. यह बदलाव सरकार व बैंकों की आदतें हमेशा के लिए बदल देगा. अब सरकार को...

- महंगाई थाम कर रखनी होगी. खासतौर पर महंगा कच्चा तेल और जिंस सबसे बड़ी कमजोरी हैं. बॉन्ड ईल्ड और महंगाई के बीच छत्तीस का आंकड़ा है. अगर महंगाई बढ़ी तो बॉन्ड निवेशक भड़केंगे
- टैक्स के नियम मौसम तरह नहीं बदलने होंगे. सरकारी बॉन्ड में विदेशी निवेश को लेकर टैक्स अनिश्चितता सबसे बड़ी उलझन है
- घाटे पर काबू रखकर अर्थव्यवस्था में तेज विकास दर बनाए रखनी होगी

शेयर बाजार के मिजाज की अनदेखी हो सकती है लेकिन बॉन्ड बाजार सीधे देश की संप्रभु साख का पैमाना है, यहां सरकार का कर्ज बिकता है, यह भड़कता है तो बड़े-बड़े देशों को लेने के देने पड़ जाते हैं. कम महंगाई, तेज विकास दर, सरकारी खर्च और घाटे में कमी, बॉन्ड बाजार भी वही मांगेगा जो भारत के आम लोगों को भी चाहिए. बस फर्क यह है कि लोग अक्सर ठगे जाने पर मन मसोस कर रह जाते हैं लेकिन बॉन्ड निवेशक सरकारों को माफ नहीं करते.

@anshuman1tiwari

इलस्ट्रेशनः असित रॉय

INDIA TODAY CONCLAVE 2021

8/9 OCT
NEW DELHI

INDIA TODAY GROUP

DEVENDRA JHAJHARIA, PRAMOD BHAGAT, GAURAV KHANNA & DEEPA MALIK

SPIRIT SOLDIERS | PARALYMPIAN CHAMPIONS

On endurance, determination. And turning adversity into triumph

INCLUSIVITY
#ABetterNormal

PRESENTING SPONSOR

ITC
Enduring Value

CONCLAVE PARTNERS

HINDUSTAN POWER | Darwin — DARWIN PLATFORM GROUP OF COMPANIES — VISIONARIES

KNOWLEDGE PARTNER

JGI JAIN DEEMED-TO-BE UNIVERSITY

BANKING PARTNER

IDFC FIRST Bank
ALWAYS YOU FIRST

LUXURY MOBILITY PARTNER

BMW

STATE PARTNER

उत्तर प्रदेश सरकार

INSURANCE PARTNER

LIC
भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

PARTNER

SHRIRAM Transport Finance Company Limited
A WINNING RELATIONSHIP

CELEBRATION PARTNER

THE GLENLIVET
BOOKS

BESPOKE PARTNER

DA MILANO
ITALIA

क्या गुजर गया

रोजाना संक्रमणों की गिरती रफ्तार और बड़े पैमाने पर टीका अभियान से उम्मीदें बढ़ीं कि संभावित तीसरी लहर उतनी विनाशकारी शायद न हो जितनी दूसरी थी, मगर वायरस के बदलते रूपों का मंडराता खतरा और आसन्न त्यौहारों के चलते विशेषज्ञों ने कोविड संबंधी सावधानियों के पालन की अहमियत पर जोर दिया

सोनाली आचार्जी

गेट्टी इमेजेज

बदतरीन दौर?

कोविड के दौर में भीड़-भाड़
गणेश चतुर्थी के अवसर पर मुंबई में दादर के फूल बाजार का नजारा

अ

आम लोगों को कोविड के टीके लगाने का अभियान देश में 1 मार्च से शुरू हुआ. तब से 28 सितंबर तक 87.1 करोड़ टीके लगा देना कोई छोटी कामयाबी नहीं है. देश के आकार और आबादी के मद्देनजर अधिकारियों और टीके लगाने वालों को न सिर्फ भारी-भरकम लक्ष्य का पीछा करना था, बल्कि उन्हें बुनियादी ढांचे, मुश्किल और दूरदराज के इलाकों, सांस्कृतिक संवदेनशीलताओं और लोगों के बीच टीके लगवाने में हिचक पैदा करने वाली बहुत-सी गलत जानकारियों की चुनौतियों से भी पार पाना था. राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के तहत काम में लगे हजारों स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की अथक कोशिशों से तमाम मुश्किलों से पार पाया जा सका और हम सफलता की अनोखी कहानियों से रू-ब-रू हुए.

मसलन, केरल के पलक्कड़ जिले की माधवी पिल्लै को लीजिए. 92 बरस की विधवा पिल्लै पूरे वक्त दो घरेलू सहायकों की मदद से जिंदगी बसर करती हैं. वे टीका लगवाने नजदीकी टीका केंद्र तक जा पातीं, इसकी कोई उम्मीद नहीं थी. मदद के लिए स्थानीय आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आगे आईं और पिल्लै को टीका केंद्र तक लेकर गईं. हिमाचल प्रदेश में पूरी हकदार आबादी को पहला टीका लग चुका है, मगर वहां टीका लगाने वाले चंबा जिले में सुदूर बालोथ गांव के लिए पहाड़ी रास्तों से 20 किमी चढ़कर पैदल गए और वहां टीका शिविर लगाया. उन्होंने हिलोतवां में बिस्तर पर पड़े एक मरीज की खातिर वन्यजीव अभयारण्य में भी शिविर लगाया.

कोविड पर राष्ट्रीय टास्कफोर्स के चेयरमैन डॉ वी.के. पॉल कहते हैं, ''हमने जो हासिल किया, वह जबरदस्त है. टीकाकरण की रफ्तार बढ़ रही है. इतनी विशाल और भौगोलिक तौर पर दूर-दूर बसी आबादी तक पहुंचने के मद्देनजर यह खास तौर पर गौर करने लायक है. करीब दो-तिहाई वयस्क आबादी को पहला टीका लगा चुका है. करीब एक-चौथाई वयस्क आबादी दोनों टीका ले चुकी है.''

देश में 17 सितंबर को एक दिन में रिकॉर्ड 2.5 करोड़ कोविड के टीके लगे. अभी तक छह राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में हकदार आबादी को पहला टीका लग चुका है. ये हैं लक्षद्वीप, चंडीगढ़, गोवा, हिमाचल प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह और सिक्किम.

क्या कोविड देश में आम बीमारी जैसा होता जा रहा है?

महत्वपूर्ण संकेतकों से तो महामारी के गुजरते जाने का अंदाजा लगता है

उछाल और गिरावट

महामारी का प्रकोप शुरू होने के बाद से देश में संक्रमण के सक्रिय मामलों का ग्राफ

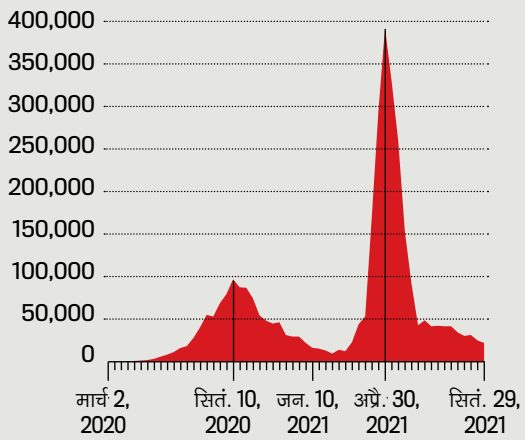

संकेत 1

पहले की लहरों के मुकाबले टेस्ट पॉजिटिविटी दर में गिरावट

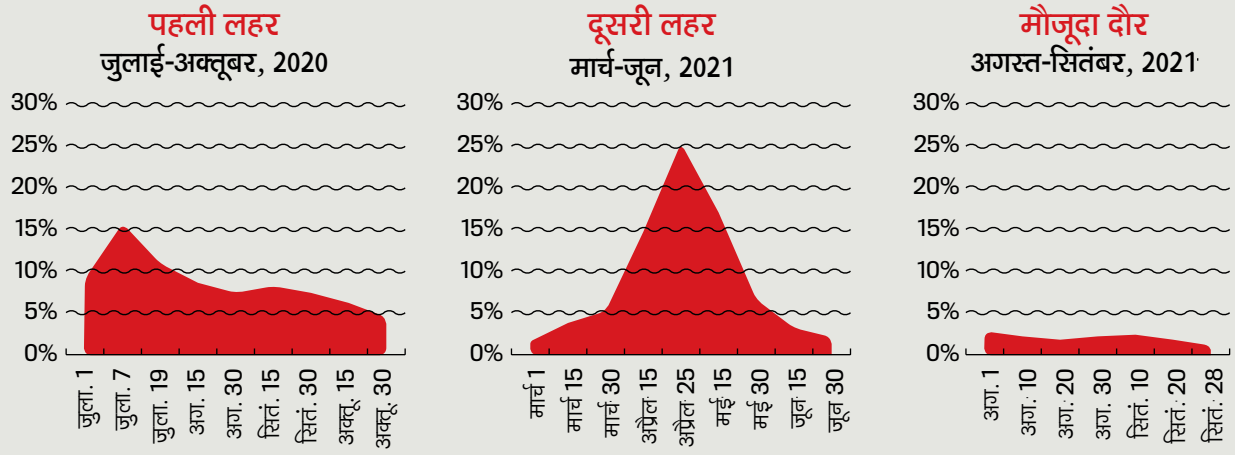

टेस्ट पॉजिटिविटी दरः कोविड टेस्ट में पॉजिटिव लोगों का प्रतिशत
आर-वैल्यूः संक्रमण के शिकार किसी व्यक्ति से दूसरों को संक्रमण लगने का औसत

संकेत 2

आर-वैल्यू 1 से कम (मध्य सितंबर, 2021) का मतलब है कि संक्रमण का प्रकोप घट रहा है

संकेत 3

देश में रोजाना नए मामलों की संख्या पिछले तीन महीने से 50,000 से कम रही है

28 सितंबर तक
स्रोतः स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, राज्य सरकारें

संकेत 4

ज्यादातर राज्यों में अस्पतालों के बिस्तर पूरे नहीं भरे हैं

(कुल बिस्तरों में भर्ती %)

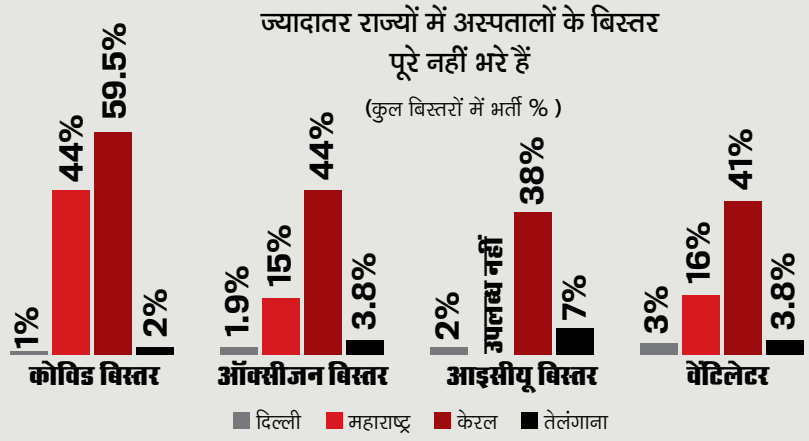

चिंताजनक इलाके

10,000 से ज्यादा संक्रमण के सक्रिय मामले

- सक्रिय मामले
- रोजाना नए मामले
- टेस्ट पॉजिटिविटी दर
- पिछले 7 दिनों के मुकाबले मामलों में हफ्तेवार वृद्धि

28 सितंबर तक
स्रोतः स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

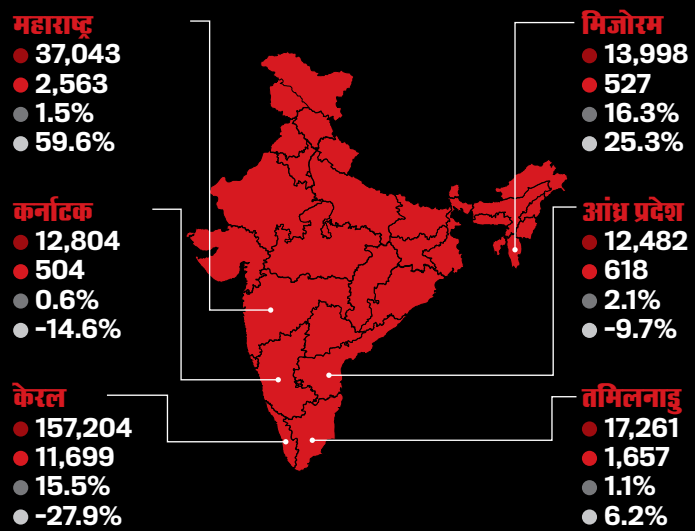

चार अन्य—दादरा और नगर हवेली, केरल, लद्दाख और उत्तराखंड—में पहला टीका लगाने का 90 फीसद से ज्यादा काम पूरा हो चुका है. टीकों की कमतर आपूर्ति से शुरुआती महीनों में टीका अभियान धीमा था, मगर अब सुधार आया है. केंद्र ने 83.50 करोड़ टीके मुहैया कराए हैं. 1.1 करोड़ और आ रहा है. यह भारी-भरकम काम था, जिसमें नई और अनदेखी मुश्किलें कभी भी आ सकती थीं. एक मुश्किल लोगों की मानसिकता भी थी. एम्स नई दिल्ली के डायरेक्टर डॉ. रणदीप गुलेरिया कहते हैं, ''एक चुनौती लोगों को वैक्सीन के डर से उबारने की थी, ताकि वे पहले टीके के लिए आएं. दूसरी चुनौती उनका मनोबल बनाए रखने की थी, ताकि वे दूसरे टीके के लिए लौटें.''

खुश होना अभी जल्दबाजी

मगर स्वास्थ्य विशेषज्ञों को अभी भरोसा नहीं है कि अभी चल रहे कोविड टीका कार्यक्रम का मतलब महामारी को जल्द पीछे छोड़ देना होगा. वे कहते हैं कि फिलहाल इतने पर्याप्त आंकड़े नहीं हैं, जिनके आधार माना जा सके कि बदतरीन वक्त गुजर चुका है. डॉ. पॉल कहते हैं, ''कोविड के मामले में ढेरों लगातार बदलती सचाइयां हैं. हम जो उपाय कर रहे हैं, वे रिसर्च और विज्ञान पर आधारित हैं. हम सबको कम से कम अगले एक साल तक मास्क पहनना और कोविड की सावधानियों का पालन करना होगा.''

संक्रामक रोग विशेषज्ञ तथा महाराष्ट्र के कोविड टास्कफोर्स के सदस्य डॉ. ओम श्रीवास्तव कहते हैं कि महामारी के खात्मे की तारीख की भविष्यवाणी करना अभी काफी जल्दबाजी होगी. वे कहते हैं, ''हमें पक्का पता नहीं है कि कोविड वायरस आने वाले वक्त में कैसा बर्ताव करेगा. कुछ महीनों पहले हमने जो सोचा था (कि ऐसा होगा), वह आज से (जो हो रहा है उससे) अलग है. हर गुजरते दिन हमें नए डेटा मिल रहे हैं.''

फिर भी, संक्रमण और अस्पताल में भर्ती की मौजूदा दरें आशाजनक संकेत हैं और देश को खुशी मनाने की वजह देती हैं. देश में अब तीन महीनों से ज्यादा वक्त से रोज 50,000 से कम मामले आ रहे हैं. 27 सितंबर को महज 26,041 मामले आए. बीते 94 दिनों के लिए साप्ताहिक टेस्ट पॉजिटिव दरों का राष्ट्रीय औसत 3 फीसद से कम है, जो डब्ल्यूएचओ (विश्व स्वास्थ्य संगठन) के 5 फीसद से कम के मानक से नीचे है. बड़े शहरों के अस्पतालों में अप्रैल के मुकाबले बहुत कम कोविड मरीज देखे जा रहे हैं, जब कोविड के डेल्टा वैरिएंट ने देश में जानलेवा दूसरी लहर बरपा दी थी (देखें *क्या कोविड देश में आम बीमारी जैसा होता जा रहा है?*).

दिल्ली सरकार के आंकड़ों के मुताबिक, 28 सितंबर को राज्य में सिर्फ 1 फीसद कोविड बिस्तर, 1.9 फीसद ऑक्सीजन बिस्तर, 2 फीसद आइसीयू बिस्तर और 3 फीसद वेंटिलेटर मरीजों के काम आ रहे थे. केरल में, जहां सक्रिय मामले सबसे ज्यादा हैं, अस्पतालों में केवल 4 फीसद कोविड मरीजों को गंभीर लक्षण थे. फिर भी, डॉक्टर बेफिक्र न हो जाने की हिदायत देते हैं. नई दिल्ली के मणिपाल अस्पताल में संक्रामक रोगों की कंसल्टेंट डॉ. अंकिता बैद्य कहती हैं, ''मामलों की संख्या भले कम हो गई हो, पर कोविड और उसके घातक असर को कम करके नहीं आंका जा सकता.''

हालांकि अधिकांश राज्यों में मई की दूसरी लहर की भयावहता के बाद से मामलों और पॉजिटिव दरों में खासी कमी आई है, पर चिंताजनक इलाके बने हुए हैं. मसलन, केरल में 28 सितंबर को पॉजिटिव दर 25 फीसद और सक्रिय मामले 1,57,204 थे. मिजोरम में 24 सितंबर को खत्म सप्ताह में मामलों की तादाद में पिछले सात दिनों के मुकाबले 25 फीसद की बढ़ोतरी हुई. महाराष्ट्र में इसी अवधि के दौरान साप्ताहिक मामलों की बढ़ोतरी में 59 फीसद का इजाफा हुआ. दोनों राज्यों में कोविड का डेल्टा वैरिएंट हावी है. लेकिन नई लहर तभी आ सकती है, जब कोई स्ट्रेन हमारी रोगप्रतिरोधक क्षमता मात देने वाला आए. विशेषज्ञ जोर देकर कहते हैं कि वायरस को संक्रमित होने देना उसे म्यूटेट होने या नया रूप धारण करने के मौका देना है.

बड़े पैमाने पर लोग इसलिए आश्वस्त होते लग रहे हैं कि देश में 'हर्ड इम्यूनिटी' आ गई है. जुलाई में 70 जिलों में किया गया आइसीएमआर (भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद) का सर्वे बताता है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की दो-तिहाई के करीब आबादी में कोविड ऐंटीबॉडी विकसित हो चुके हैं. कोविड के खिलाफ इम्यूनिटी के ख्याल से दिल्ली की फैशन डिजाइनर 34 वर्षीया गौहर कौर ने इस साल दीवाली की पार्टी का मनसूबा बनाया है. वे कहती हैं, ''दिल्ली में महज कुछ सौ मामले हैं. अगर हममें से ज्यादातर कोविड के प्रति इम्यून हैं, तो डरकर क्यों जिएं?''

दोनों टीका लगाना ही टीकाकरण की कुंजी

87,1269,685 टीके कुल लगे

64,0797,309
पहला टीका लगा

23,0472,376
दोनों टीके लगे

69
करोड़ लोगों को देश में अभी पुरी तरह टीका लगना बाकी है

हकदार वयस्कों में सिर्फ एक-चौथाई को ही दोनों टीके लगे

डेल्टा वैरिएंट के खिलाफ कोविशील्ड का असर*

33% पहले टीके से

60% दूसरे टीके से

*पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड का अध्ययन, मई 2021

स्रोतः कोविन, पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड

28 सितंबर तक

बीमार होने से बेहतर है परहेज
एनसीआर में गाजियाबाद के इंदिरापुरम के एक मॉल में टीका लगावाने के लिए 27 सितंबर को लगी कतार

गेट्टी इमेजेज

विशेषज्ञ सतर्क हैं. सीरोप्रीवैलेंस अध्ययन कोविड के प्रकोप और रुख को समझने में मदद तो करता है, लेकिन यह हर्ड इम्यूनिटी का निश्चित संकेत कतई नहीं है. डॉ. श्रीवास्तव कहते हैं, ''लोग अक्सर ऐंटीबॉडी टेस्ट करवाते हैं और सोचते हैं कि वे सुरक्षित हैं, पर खास बात यह देखना है कि ऐंटीबॉडी कैसी है और कितने वक्त से है.'' डॉ. बैद्य कहती हैं, ''कोविड इम्यूनिटी के लिए कम से कम दो या तीन महीनों तक ऐंटीबॉडी को बेअसर करने की जरूरत होती है. महज ऐंटीबॉडी की गिनती भर से यह नहीं बताया जा सकता कि आपके शरीर में कोविड से सुरक्षा के लिए जरूरी कारगर ऐंटीबॉडी हैं या नहीं.'' डॉ. बैद्य यह भी कहती हैं कि इंटरनेट की जानकारियों के आधार पर लोगों का रवैया वायरस के नए वैरिएंट के लिए मददगार हो सकता है. वे कहती हैं, ''हमें यह भी नहीं पता कि वैक्सीन हमें कितने लंबे वक्त तक सुरक्षित रखेगी. लिहाजा सावधानी ही आज का दस्तूर होना चाहिए.''

टीकों का असर कब तक?

भुवनेश्वर में आइसीएमआर के क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र में 614 ऐसे स्वास्थ्यकर्मियों पर एक अध्ययन किया गया, जिन्हें दो टीके लग चुके थे. अध्ययन में दूसरे टीके के चार महीने के भीतर कोविड ऐंटीबॉडी में काफी गिरावट देखी गई. सितंबर में प्रकाशित अध्ययन की सह-लेखिका डॉ. संघमित्रा पति कहती हैं, ''इसका मतलब यह नहीं है कि व्यक्ति पूरी तरह सुरक्षित नहीं है. टी और बी सेल भी वायरस से लड़ने की मेमोरी बनाने में मदद करते हैं.'' यह समझना महत्वपूर्ण है कि ऐंटीबॉडी केवल हमारी प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया का एक हिस्साभर हैं, अपने आप में पूरा प्रतिरक्षा तंत्र नहीं.

> **“हमें पता नहीं है कि कोविड वायरस का रवैया आगे कैसा रहेगा और उसका प्रकोप किस रूप में दिखेगा. हम कुछ महीने पहले जो सोच रहे थे कि ऐसा होगा, आज हकीकत उससे काफी अलग है”**
>
> डॉ. ओम श्रीवास्तव
> संक्रामक रोग विशेषज्ञ तथा महाराष्ट्र कोविड टास्कफोर्स के सदस्य

श्वेत रक्त कोशिकाएं शरीर पर धावा बोलने वाले बाहरी तत्वों के खिलाफ लड़ने वाली शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली की सेना हैं. विशेष रूप से, शरीर को दो प्रकार की श्वेत रक्त कोशिकाओं—बी सेल या (बी कोशिकाएं) और टी सेल (टी कोशिकाएं)—की आवश्यकता होती है. श्वेत रक्त कोशिकाएं अस्थि मज्जा में विकसित होती हैं और बी सेल में विकसित होने के लिए वहीं बनी रहती हैं या फिर टी सेल के रूप में विकसित होने के लिए थाइमस ग्रंथि में चली जाती हैं. बी सेल वायरस को ढूंढती हैं, और फिर ऐंटीबॉडी बनाना शुरू करती हैं. ऐंटीबॉडी वायरस

म्युटेंट पर नजर

कोविड वायरस के एक दक्षिण अफ्रीकी स्ट्रेन में किसी भी दूसरे वैरिएंट से ज्यादा म्युटेशन हो चुका है और वह भारत तबाही मचा सकता है

वैरिएंटः सी.1.2

- लांब्डा का एक वैरिएंट, जो डब्ल्यूएचओ के लिए अब भी कुछ हद तक रहस्य बना हुआ है
- सी.1.2 पहली बार मई 2021 में दक्षिण अफ्रीका में पाया गया

स्ट्रेन में कुछ खास म्युटेशन

- डी614जी म्युटेशन अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा वैरिएंट में पाया गया है, जो वायरस के वैरिएंट तैयार करने की क्षमता में बढ़ोतरी कर सकता है
- एन501वाइ म्यूटेशन–यह भी अल्फा, बीटा और गामा में पाया गया है और स्पाइक प्रोटीन की कोशिकाओं से चिपकने की क्षमता बढ़ा देता है–जिससे वायरस और ज्यादा संक्रामक हो जाता है
- ई484के म्युटेशन–बीटा और गामा वैरिएंट में भी पाया गया है–टीके या पहले के वैरिएंट से उत्पन्न ऐंटीबॉडी को बेअसर करके बच निकलने में वायरस की मदद करता है
- सी.1.2 दूसरे म्युटेशन एक679के और वाइ449एच का वाहक भी है. इनके असर का अध्ययन किया जा रहा है

सी. 1.2 संक्रमण के मामलों वाले देश

130
मामले
दुनिया भर में

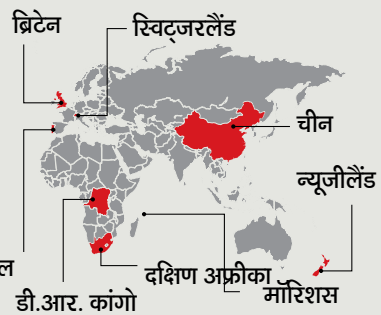

स्रोतः डब्ल्यूएचओ

को घेर तो लेते हैं, लेकिन बिना मदद के उन्हें नष्ट नहीं कर सकते. ये टी सेल हैं जो ऐंटीबॉडी द्वारा चिह्नित रोग पैदा करने वाले को नष्ट कर देती हैं. शरीर पर उसी रोगाणु के फिर से हमले से निपटने के लिए ऐंटीबॉडी अलग-अलग अवधि के लिए रक्त में बनी रहती है. कुछ इसी तरह टीके बीमारियों को रोकते हैं—वे शरीर के साथ वायरस का परिचय इस तरह कराते हैं कि वे शरीर को बिना प्रभावित किए ऐंटीबॉडी को रोगाणु को पहचानने में मददगार हों.

अध्ययनों से यह तो पता चला है कि कोविड टीकाकरण के कारण विकसित ऐंटीबॉडी का स्तर आगे चलकर गिर सकता है लेकन टी सेल की मेमोरी की भूमिका पर बहुत कम डेटा उपलब्ध है. 2020 में *नेचर* जर्नल में छपे 2003 में सार्स (सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम) महामारी से मिले सबक से संकेत मिला कि संक्रमित होने वाले कई व्यक्तियों में 17 साल बाद भी टी सेल मेमोरी मजबूत बनी रही. इससे पता चलता है कि टी सेल प्रतिक्रियाएं लंबे समय तक बनी रह सकती हैं.

हालांकि, टी सेल परीक्षण ऐंटीबॉडी परीक्षणों की तुलना में बाजार में दुर्लभ हैं और इनका परीक्षण भी बहुत अधिक तकनीकी है.

आइसीएमआर यह शोध कर रहा है कि कोविड-19 के खिलाफ शरीर की रोगरोधक क्षमता में ऐंटीबॉडी और टी सेल की सुरक्षा की भूमिका क्या है और वह कितने समय तक रहती है. इन अध्ययनों से इस पर रोशनी पड़ने की उम्मीद है कि टीके से तैयार हुई प्रतिरक्षा कितने समय तक चलती है और किन खास वजहों से यह तय होता है. प्रसिद्ध वायरोलॉजिस्ट डॉ. टी. जैकब जॉन कहते हैं, ''शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र में सुरक्षा का तत्व भी होता है जो गंभीर बीमारी के खिलाफ काम कर सकता है. हमने पाया है कि दोनों टीके लगा लेने से डेल्टा वैरिएंट भी घातक नहीं होता है.''

कोविशील्ड का ही उदाहरण लें, जिसके 76.4 करोड़ टीके भारत में दिए गए हैं. सशस्त्र बलों के 16 लाख स्वास्थ्य सेवा कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स पर एक अध्ययन से पता चला कि कोविशील्ड ने संक्रमण की आशंका को 93 प्रतिशत तक कम कर दिया और मृत्यु से पूरी तरह से सुरक्षित कर दिया. लेकिन आइसीएमआर के एक अध्ययन से पता चला कि कोविशील्ड लगवाने वाले 58 प्रतिशत लोगों में पहले टीके और 16 प्रतिशत लोगों में दोनों टीके लेने के बावजूद, कोई ऐंटीबॉडी मौजूद नहीं थी. इससे पता चलता है कि कम या बिना ऐंटीबॉडी के भी टीके संक्रमण और गंभीर कोविड रोग से सुरक्षा दे रहे हैं (देखें *दोनों टीके लगाना टीकाकरण की कुंजी है*).

कोविड से बचाव में ऐंटीबॉडी की भूमिका और ऐंटीबॉडी के आवश्यक स्तरों पर अधिक मजबूत डेटा के अभाव में, भारतीय विशेषज्ञ बूस्टर वैक्सीन के पक्ष में नहीं हैं. उनका मानना है कि बूस्टर टीका केवल उन लोगों को ही चाहिए, जिनका शारीरिक प्रतिरक्षा तंत्र खराब है. अमेरिका में, फूड ऐंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (एफडीए) 16 साल से ऊपर के सभी लोगों के लिए एक बूस्टर डोज पर विचार कर रहा है. हालांकि, डब्ल्यूएचओ ने अमीर और गरीब देशों के बीच भारी टीकाकरण अंतर का हवाला देकर बूस्टर टीके पर अस्थायी रोक लगाने की अपील की है.

डॉ. पॉल कहते हैं कि बूस्टर टीके अभी भी विकास की पक्रिया में हैं और भारत की प्राथमिकता पूरी आबादी को दो बार टीका लगाना है. डॉ. गुलेरिया कहते हैं, ''फिलहाल बूस्टर टीके की आवश्यकता नहीं है. बूस्टर वैक्सीन कैसी हो, और कब जरूरी है, यह तभी स्पष्ट होगा जब हमारे पास अधिक आंकड़े उपलब्ध होंगे.'' फिलहाल सबको मास्क लगाना जरूरी है. डॉ. गुलेरिया कहते हैं, ''आपको टीका लग चुका है या फिर आप कोविड से उबर रहे हैं तो भी आप वायरस को फैला सकते हैं. यह सोचना कि आप सुरक्षित हैं और एहतियात रखना छोड़ देना घातक गलती हो सकती है.''

महामारी से आम बीमारी बनने की ओर

महामारी समूचे समुदाय, आबादी या क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोगों को चपेट में ले लेती है. कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी का दायरा बहुत बड़ा होता है और यह कई देशों या महाद्वीपों में फैलती है. आम बीमारी का प्रकोप एक सीमित क्षेत्र में बराबर बना रहता है लेकिन उसका बचाव या इलाज संभव है. कोई भी आम संक्रामक बीमारी महामारी का रूप ले सकती है, अगर संक्रमण दर ऊंची और अचानक हो. मसलन, भारत में नियमित अंतराल में डेंगू या इन्फ्लूएंजा का प्रकोप होता है और उसमें उतार-चढ़ाव भी दिखता है. अगर पूरे वर्ष उसके संक्रमण की दर उच्च बनी रहती, तो वह महामारी का रूप ले लेती है. कोविड संक्रमण की वर्तमान दर को देखें तो लग सकता

है कि कोविड भारत में आम बीमारी होने की राह पर है. हमारी टेस्ट पॉजिटिविटी दर, रोजाना संक्रमणों की संख्या और आर-वैल्यू पिछले तीन महीनों से कम और स्थिर बनी हुई है.

चेन्नै के इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज के अनुसार, भारत में कोविड-19 के लिए आर-वैल्यू अगस्त के अंत में 1.17 से घटकर सितंबर के मध्य में 0.92 हो गई. सबसे अधिक सक्रिय मामलों वाले राज्य केरल और महाराष्ट्र में भी आर-वैल्यू 1 से नीचे है. क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, वेल्लूर की वायरोलॉजिस्ट डॉ. गगनदीप कंग कहती हैं, ''कोविड पूरी तरह से खत्म नहीं होने जा रहा, यह सामान्य बनकर रहेगा.'' वे कहती हैं कि अगर लोग आगामी त्योहारी सीजन के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते हैं, तो देशव्यापी तीसरी लहर की आशंका है, हालांकि यह दूसरी लहर की तरह गंभीर नहीं होगी.

विशेषज्ञ वायरस के ऐसे नए वैरिएंट से पैदा होने वाली घातक लहर को लेकर आशंकित हैं जो पिछली ऐंटीबॉडी को चकमा दे सकता है. डब्ल्यूएचओ ने ऐसे दो वैरिएंट की पहचान की है जो अभी तक भारत में नहीं पहुंचे हैं—एमयू और सी.1.2 (देखें, *म्यूटेंट परख*). डब्ल्यूएचओ का कहना है कि इस जनवरी में पहली बार कोलंबिया में पहचाने गए एमयू वेरिएंट में ऐंटीबॉडी को चकमा देने की क्षमता है. इसका वैश्विक प्रसार 0.1 प्रतिशत से कम हो गया है, लेकिन यह कोलंबिया (कुल मामलों का 39 प्रतिशत) और इक्वाडोर (13 प्रतिशत) में अब भी फैल रहा है. मई में दक्षिण अफ्रीका में पाया गया सी.1.2 वैरिएंट अधिक चिंता का विषय है क्योंकि उसमें अब तक ज्ञात सभी कोविड वैरिएंट में सबसे अधिक म्युटेशन हुआ है. दुनियाभर में इसके करीब 130 मामले पाए गए हैं.

डॉ. बैद्य कहती हैं, ''सी.1.2 वैरिएंट के अनुवांशिक स्वरूप में काफी अधिक परिवर्तन देखे गए हैं, जो इसे अधिक संक्रामक बना सकता है. यह टीकों को बेअसर कर सकता है और संक्रमण के लक्षणों की प्रकृति को बदल सकता है. इन कारकों पर डेटा आगे चलकर और अधिक अध्ययनों के बाद ही सामने आएगा.'' सी.1.2 वैरिएंट सी.1 से विकसित हुआ, जो मई 2020 में दक्षिण अफ्रीका में पहली लहर के दौरान हावी था. दक्षिण अफ्रीका के नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर कम्युनिकेबल डिजीज के शोधकर्ता सी.1.2 स्ट्रेन का अध्ययन कर रहे हैं और उनका कहना है कि इसमें वुहान से निकले मूल स्ट्रेन में सबसे अधिक म्यूटेशन हुआ है. इस स्ट्रेन की संक्रमण दर की तुलना शुरुआती दिनों में दक्षिण अफ्रीका के बीटा और डेल्टा वैरिएंट से की जाती है.

डेल्टा वैरिएंट का प्रकोप भारत में फिलहाल सबसे ज्यादा है. प्रकोप सिर्फ इसी का नहीं है. इससे निकले नए म्यूटेंट की संख्या पिछले कुछ महीनों में चार से 13 हो गई है. ये म्यूटेंट ही कोविड के नए मामले जोड़ रहे हैं और उनमें इजाफा कर रहे हैं. इसका एक वैरिएंट एवाइ.4 पहली बार ब्रिटेन में पाया गया था. बाद में महाराष्ट्र में इसके संक्रमण के सबूत मिले हैं. वहां अप्रैल में किए गए परीक्षण में 1 प्रतिशत नमूनों में यह पाया गया. लेकिन जुलाई में जांचे गए नमूनों में इसका अनुपात बढ़कर 2 फीसद और अगस्त में 44 फीसद हो गया. कर्नाटक में भी इसका ही प्रकोप तेजी से बढ़ा है. वहां सितंबर में 41.1 प्रतिशत नमूनों में एवाइ.4 वैरिएंट पाया गया था जो डेल्टा (40 प्रतिशत) के प्रकोप से अधिक है. इसका एक अन्य वैरिएंट एवाइ.12 पहली बार इज़्राएल में पाया गया, जहां पूरी तरह टीकाकरण हो जाने के बावजूद इसके संक्रमण की चपेट में 60 फीसद आबादी आई और एक नई लहर पैदा हुई. फिर, दिल्ली में सितंबर में किए गए परीक्षण में यह 10 फीसद नमूनों में पाया गया. कोविड-19 पर राष्ट्रीय टास्कफोर्स के सदस्य एन.के. अरोड़ा कहते हैं, ''देश की आबादी के एक बड़े हिस्से में अभी भी कोविड का संक्रमण नहीं फैला है. इस वजह से सिर्फ डेल्टा वैरिएंट ही कई क्षेत्रों में अपना प्रकोप फैला सकता है. इसलिए सावधान रहने की जरूरत है.''

> **"आशंकित तीसरी लहर कितनी खतरनाक और विनाशकारी होगी, यह बिलाशक लोगों के रुख और रुझान पर निर्भर करेगा. आप सोचते हों कि टीके लगाने के बाद सुरक्षित हो गए, तो भारी गलती कर बैठ सकते हैं"**
>
> डॉ. रणदीप गुलेरिया
> डायरेक्टर, एम्स, नई दिल्ली

इसमें दो राय नहीं कि कोविड का वायरस दुनिया में संक्रमण फैला चुके दूसरे वायरसों से बहुत हद तक अलग है. इसलिए मानव शरीर के लिए उसकी पहचान मुश्किल रही है और अभी भी इस पर काबू नहीं पाया जा सका है. स्वाइन फ्लू ने अपने पहले वर्ष (2009) में विश्व स्तर पर 2,84,000 लोगों की जान ली थी; कोविड ने 20 लाख जानें ली हैं. कोविड स्वाइन फ्लू की तुलना में काफी अधिक संक्रामक है. उसमें तेजी से म्युटेशन होने के कारण यह अधिक संक्रामक है और हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को चकमा देने में सक्षम है.

दरअसल, टीकाकरण का एक वर्ष से भी कम समय का आंकड़ा उपलब्ध है और अभी देश की कुछ ही आबादी को टीके लग सके हैं. इस वजह से शोधकर्ताओं का कहना है कि यह निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी कि क्या टीके लगवा चुके और वायरस के संपर्क में पहले आ चुके लोग कोविड के वर्तमान स्ट्रेन से बचे रहने में सक्षम होंगे. हालांकि, एक बात जो तय है, वह यह है कि मास्क लगाने, आपस में दूरी बनाए रखने और समय-समय पर जरूरत के मुताबिक खास इलाकों में लॉकडाउन लगाने से इसके संक्रमण की संख्या कम की जा सकती है. डॉ. गुलेरिया कहते हैं, ''कोविड की आशंकित तीसरी लहर कितनी विनाशकारी हो सकती है, यह लोगों के रुख और रुझानों पर निर्भर करता है.''

बहरहाल, अक्तूबर की शुरुआत में नवरात्रों के साथ शुरू होने वाला लंबा त्योहारी मौसम संक्रमण के प्रकोप के लिहाज से काफी अहम हो सकता, जैसा की दूसरी लहर के वक्त देखा गया है. तब सरकार भी यह दावा कर रही थी कि कोविड लगभग विदा हो चुका है. धड़ल्ले से विशाल धार्मिक आयोजन और बड़ी-बड़ी चुनावी रैलियां की जाने लगी थीं. लेकिन अगर देश में संक्रमण को इसके मौजूदा स्तर पर रोका जा सकता है तो कोविड धीरे-धीरे वैश्विक महामारी से आम बीमारी का रूप ले सकता है. यकीनन, वायरस अब हमारे बीच हमेशा बना रहने वाला है, और हमें इसके साथ जीना सीखना होगा. लेकिन टीकाकरण और उचित सावधानियों के साथ यह शायद बीमारी, मृत्यु और पीड़ा के उस स्तर का कारण नहीं बनेगा, जैसा कि देश ने इस साल गर्मियों की शुरुआत में डरावना मंजर देखा और झेला था. ■

कूटनीति

क्वाड की पलटन

क्या भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया मिलकर आक्रामक चीन को काबू कर सकते हैं

राज चेंगप्पा

पुरानी रोमन कहावत है कि शांति चाहते हो तो युद्ध की तैयारी करो. कई देशों के खिलाफ चीन के लगातार खम ठोकने के बीच, पिछले पखवाड़े हुए दो घटनाक्रम बताते हैं कि एक बढ़ता चीन-विरोधी गुट, जिसमें भारत भी है, कैसे लड़ाकू बीजिंग के खिलाफ रक्षात्मक दीवार खड़ी कर रहा है

पहले तो हैरत में डालने वाले एक घटनाक्रम में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन, ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति स्कॉट मॉरिसन ने मिलकर 15 सितंबर को हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए एक त्रिपक्षीय सुरक्षा गठबंधन बनाने का ऐलान किया. एयूकेयूएस या औकस नाम का यह गठबंधन साफ तौर पर सैन्य गठबंधन है, जिसमें अन्य बातों के अलावा अमेरिका और ब्रिटेन परमाणु शक्ति संपन्न पनडुब्बियां हासिल करने में ऑस्ट्रेलिया की मदद करेंगे. समूह ने जिक्र नहीं किया कि किस देश के खिलाफ वे यह तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जाहिर था कि यह हिंद-प्रशांत क्षेत्र और खासकर दक्षिण तथा पूर्व चीन समुद्र में चीन के आक्रामक सैन्य इरादों का मुकाबला करने के लिए है.

फिर एक हफ्ते बाद बाइडन ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए साझा दूरदृष्टि के साथ काम कर रहे चार लोकतांत्रिक देशों के गुट क्वाड के पहले आमने-सामने हुए शिखर सम्मेलन के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जापान के निवर्तमान प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा और ऑस्ट्रेलिया के मॉरिसन की मेजबानी की. चतुर्पक्षीय सुरक्षा संवाद के छोटे नाम क्वाड की शुरुआत 2007

में हुई थी, लेकिन एक दशक से ज्यादा वक्त यह उनींदा और निष्क्रिय पड़ा रहा, क्योंकि जापान को छोड़कर बाकी तीनों देश उभरते चीन से खुलकर पंगा लेना नहीं चाह रहे थे. मगर साल 2020 के बाद इस गुट ने बेहद जरूरी होने के एहसास से आगे कदम बढ़ाए. इतनी तेजी से कि 2021 में ही इसके शीर्ष नेताओं के दो शिखर सम्मेलन हो चुके हैं—मार्च 2021 में वर्चुअल और पिछले हफ्ते आमने-सामने.

क्वाड का शिखर सम्मेलन औकस के ऐलान की छाया से भले दब गया हो लेकिन इस बैठक में चारों देश हिंद-प्रशांत पर खास जोर देते हुए वैश्विक सार्वजनिक भलाई (देखें, आगे बढ़ते कदम) की कई पहल करने को राजी हुए. किसी बड़े सुरक्षा सहयोग के ऐलान से उन्होंने परहेज बरता, सिवाय इसके कि 'हिंद-प्रशांत और उसके आगे सुरक्षा और समृद्धि को सहारा देने के लिए स्वतंत्र, खुली, नियम-आधारित, अंतरराष्ट्रीय कानूनों पर टिकी और जोर-जबरदस्ती से निर्भीक व्यवस्था को बढ़ावा देने' की अपनी प्रतिबद्धता दोहरा भर दी.

सच कहें तो क्वाड के मौजूदा एजेंडे के केंद्र में तीन चीजें—बेहद अहम हैं और वे हैं—टेक्नोलॉजी, कोविड से मुकाबला और जलवायु परिवर्तन. इन तीनों का ही इस क्षेत्र के साथ दुनिया की सुरक्षा से भी गहरा वास्ता है. लेकिन, जैसा कि कारनेगी एंडोवमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस के सीनियर फेलो एश्ले जे. टेलिस कहते हैं, ''क्वाड अपनी शुरुआत से ही अशक्त रहा क्योंकि सीधे चीन का नाम लेने से कतराता रहा है. क्वाड का एजेंडा बहुत ज्यादा लंबा-चौड़ा हो गया है, हालांकि इसे चीन को बराबरी पर लाने के लिए बनाया गया था. क्वाड तरकश का उपयोगी तीर है लेकिन चीन के खिलाफ अमेरिका की मुख्य चुनौती बड़ी हद तक सैन्य है और वह दो मोर्चों पर है. एक, समुद्र और महाद्वीप दोनों में चीन के 'ग्रे जोन' पैंतरों का मुकाबला करना और दूसरा, ताइवान को प्रभावी सुरक्षा कैसे प्रदान की जाए. मेरी राय में क्वाड के पास फिलहाल दोनों का ही असल उत्तर नहीं है.''

तो क्या क्वाड की हैसियत घटकर वाकई उतनी रह गई है जिसे चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने ''समुद्र में झाग'' कहकर खारिज कर दिया, जो जल्द ही तितर-बितर हो जाएगा? क्या यह अब वह एशियाई नाटो नहीं रहा जिसे बनाने का आरोप चीन ने अमेरिका और जापान पर लगाया था? हां भी और नहीं भी. हां इसलिए क्योंकि, जैसा कि एक बड़े भारतीय अफसर कहते हैं, खुद को मुख्यत: चीन विरोधी गुट या सैन्य गठबंधन की स्थिति में रखना क्वाड के डीएनए में नहीं है—इसे 2004 की हिंद महासागर की सुनामी से पैदा मानवीय और आर्थिक संकट के नतीजतन बनाया गया था. ऐसा इसलिए है क्योंकि व्यापार के लिए चीन पर बहुत ज्यादा निर्भर कोई भी आसियान देश ऐसे किसी गुट के साथ नहीं आएगा जो खुल्लमखुल्ला बीजिंग विरोधी हो. यह अफसर कहते हैं, ''आप थाईलैंड जाकर यह नहीं कह सकते कि मेरी वैक्सीन लो क्योंकि यह चीन में नहीं बनी है. इसके बजाए आपको कहना होगा कि इसे लो क्योंकि यह अच्छी वैक्सीन है. आसियान देश चीन को काबू करने वाले किसी खेल का हिस्सा होने या महाशक्ति देशों के बीच नई प्रतिद्वंद्विता के झमेले में पड़ने को लेकर खासे चौकन्ने हैं.''

नहीं, इसलिए कि क्वाड ने अपने लिए जो एजेंडा तय किया है, वह ''चीन की वृद्धि के सामने सकारात्मक वैकल्पिक अफसाना'' देता है, जैसा कि एक अन्य बड़े अधिकारी ने कहा. मसलन, टेक्नोलॉजी के मोर्चे पर क्वाड ने ऐसे समूह को जोड़ा है जो 5जी, सेमीकंडक्टर चिप और आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस सरीखी अहम टेक्नोलॉजी पर काम करेगा और इन बेहद अहम क्षेत्रों में चीन के कथित दबदबे को अप्रत्यक्ष रूप से कमजोर करेगा. साइबर सुरक्षा और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, खासकर बाह्य अंतरिक्ष के अहम क्षेत्रों का तो जिक्र ही क्या, जिनमें चीन ने तेज छलांगें लगाई हैं.

पूर्व विदेश सचिव श्याम सरण मानते हैं कि दो समानांतर घटनाक्रम—औकस की घोषणा और क्वाड के एजेंडे का तय होना—अपने-अपने ढंग से चीन को पीछे धकेलने का इशारा हैं. वे कहते हैं, ''अब सैन्य हिस्सा दूसरे खाने में रख दिया गया है, ताकि आसियान देश बेचैन न हों. आप जलवायु परिवर्तन, टेक्नोलॉजी और अंतरिक्ष सरीखे सहयोग के दूसरे क्षेत्रों में, जो

एश्ले जे. टेलिस
सीनियर फेलो,
कानरेगी एंडोवमेंट फॉर
इंटरनेशनल पीस

"क्वाड अपनी शुरुआत से ही अशक्त रहा क्योंकि सीधे चीन का नाम लेने से कतराता रहा. अब इसका एजेंडा बहुत ज्यादा लंबा-चौड़ा हो गया है''

चार बनाम एक
चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के खिलाफ एकजुट हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापानी प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा

क्वाड का क्रमिक विकास

रफ्ता-रफ्ता रफ्तार पकड़ता

1.0 (2007-2017)

2004 में हिंद महासागर में सुनामी के मद्देनजर, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने आपदा राहत पर आपसी सहयोग के लिए एक अनौपचारिक गठबंधन बनाया. 2007 में, जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने गठबंधन को औपचारिक रूप देते हुए इसे क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग या क्वाड कहा जिसका मुख्य उद्देश्य चीन को अनियंत्रित होने से रोकना था. लेकिन अन्य तीन देश चाहते थे कि यह लो प्रोफाइल रहे, इसलिए क्वाड एक दशक तक निष्क्रिय सा रहा.

इवान वूची/एपी

2.0 (2017-2019)

2017 में शी जिनपिंग के नेतृत्व वाले चीन ने हेकड़ी दिखानी शुरू की तो हिंद-प्रशांत क्षेत्र में नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था स्थापित करने के व्यापक उद्देश्य के साथ क्वाड को पुनर्जीवित किया गया. क्वाड की महत्वाकांक्षाएं तो बहुत ऊंची थीं, लेकिन स्थायी निर्णय लेने वाली संस्था के अभाव में यह अशक्त बना रहा. इसके बजाए, सदस्य देशों ने मौजूदा समझौतों के विस्तार पर ध्यान केंद्रित किया और इसे महज एक बयानबाजी करने वाली संस्था के रूप में ही देखा गया.

3.0 (2020-

वर्ष 2020 के बाद, भारत-अमेरिका-जापान मालाबार नौसैनिक अभ्यासों का विस्तार करके इसमें ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल करने के साथ क्वाड गठजोड़ ने गति पकड़ी. यह सैन्य अभ्यास अपनी तरह का पहला कदम है. मार्च 2021 में क्वाड नेताओं ने आभासी रूप से मुलाकात की और 'द स्पिरिट ऑफ द क्वाड' यानी क्वाड की मूल भावना को रेखांकित किया. इसके बाद 24 सितंबर को एक व्यक्तिगत शिखर सम्मेलन हुआ जिसमें 'ग्लोबल पब्लिक गुड' के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया.

मुख्य फोकस क्षेत्र

आगे बढ़ते कदम

24 सितंबर को शिखर बैठक में क्वाड के नेताओं ने सात प्रमुख पहलों की रूपरेखा तैयार की

कोविड और वैश्विक स्वास्थ्य

क्वाड वैक्सीन पार्टनरशिप के तहत, वैश्विक स्तर पर कोविड टीके की 1.2 अरब से अधिक खुराक देने का वादा किया गया है. भारत, अक्तूबर से टीके का निर्यात फिर से शुरू करेगा. जापान अपने 3.3 अरब डॉलर के कोविड आपातकालीन सहायता ऋण कार्यक्रम के साथ इसमें सहयोग करेगा. ऑस्ट्रेलिया टीकों और अंतिम छोर तक सहायता पहुंचाने के लिए 43.1 करोड़ डॉलर का अनुदान देगा.

आधारभूत ढांचा

क्वाड हिंद-प्रशांत क्षेत्र में डिजिटल कनेक्टिविटी, जलवायु, स्वास्थ्य और लैंगिक समानता के लिए एक आधारभूत ढांचा साझेदारी कार्यक्रम बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड (बीउडब्ल्यू) का समर्थन करता है. क्षेत्रीय आधारभूत ढांचे की जरूरतों के आकलन को साझा करने और उच्च मानकों के आधारभूत ढांचा निर्माण के लिए आवश्यक समन्वय के लिए एक क्वाड इन्फ्रास्ट्रक्चर समन्वय समूह नियमित रूप से बैठक करेगा.

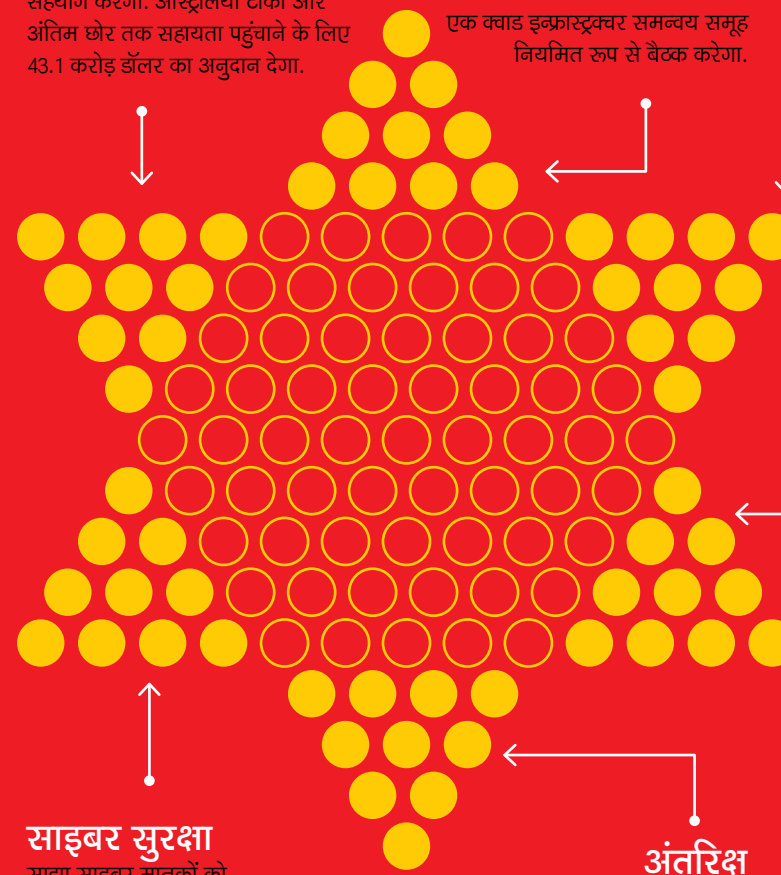

साइबर सुरक्षा

साझा साइबर मानकों को अपनाने और लागू करने, सुरक्षित सॉफ्टवेयर के विकास और एक भरोसेमंद डिजिटल बुनियादी ढांचे के निर्माण जैसे क्षेत्रों में निरंतर सुधार लाने के लिए सरकार और उद्योग के बीच नियमित रूप से मिलने की जरूरत महसूस की गई है. इस काम को आगे बढ़ाने के लिए लीडर स्तर के विशेषज्ञों के साथ एक क्वाड सीनियर ग्रुप शुरू किया जा रहा है.

अंतरिक्ष

क्वाड देश जलवायु परिवर्तन और आपदा तैयारियों की निगरानी के लिए उपग्रह डेटा के आदान-प्रदान के लिए एक नए कार्य समूह के साथ अंतरिक्ष में सहयोग शुरू करेंगे. यह आपसी हित के अंतरिक्ष उपयोगों को बढ़ाएगा और बाहरी अंतरिक्ष पर्यावरण की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए नियम निर्धारित करेगा.

जलवायु परिवर्तन

क्वाड देश राष्ट्रीय उत्सर्जन और नवीकरणीय ऊर्जा, स्वच्छ-ऊर्जा नवाचार के लिए 2030 तक के लक्ष्यों को तय करने और उनकी तैनाती के साथ-साथ अनुकूलन, लचीलापन और तैयारियों के लिए साथ मिलकर काम करेंगे. यह पर्यावरण अनुकूल बंदरगाहों का बुनियादी ढांचा खड़ा करने के लिए एक ग्रीन शिपिंग नेटवर्क बनाएगा और स्वच्छ हाइड्रोजन मूल्य शृंखला के सभी तत्वों में लागत को कम करने के लिए क्लीन-हाइड्रोजन साझेदारी की भी घोषणा की गई है.

महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियां

क्वाड लीडर्स एक खुले, सुलभ और सुरक्षित टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए काम करेंगे. क्वाड एक सेमीकंडक्टर आपूर्ति शृंखला पहल शुरू करेगा, 5जी लाने और विविधीकरण में सहयोग करेगा, उच्च-मानकों के नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए नियमों के निर्धारण करने के अलावा, उन्नत संचार और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर संपर्क समूह स्थापित करेगा.

लोगों के बीच आपसी मेलजोल और शिक्षा को समर्थन

क्वाड फेलोशिप जो कि अपनी तरह का पहला छात्रवृत्ति कार्यक्रम है, एक गैर-सरकारी टास्क फोर्स की तरफ से संचालित एक परोपकारी पहल होगी जिसमें प्रत्येक क्वाड देश के लीडर्स शामिल होंगे. यह अमेरिका में प्रमुख एसटीईएम (साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट) ग्रेजुएट विश्वविद्यालयों में मास्टर्स और डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने के लिए सालाना 100 छात्रों (प्रत्येक सदस्य देश से 25) को प्रायोजित करेगा.

क्षेत्र की सुरक्षा के बराबर ही महत्पूर्ण हैं, इन देशों के साथ काम कर सकते हैं. औकस और क्वाड दोनों चीन के खिलाफ भय प्रतिरोधक खड़ा करने के लिए एक दूसरे के समानांतर काम करेंगे.''

सरण कहते हैं कि क्वाड को चीन के खिलाफ सैन्य प्रतिरोधक होने से दूर करना कुछ ऐसा है जिससे भारत को सहज होना चाहिए. जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के विपरीत, भारत और चीन की जमीनी सरहदें मिलती हैं और इसलिए दांव कहीं ज्यादा ऊंचे हैं. यही नहीं, टेलिस कहते हैं, ''औकस के जरिए अमेरिका चीन के लिए जिंदगी दुश्वार बना रहा है. समुद्री क्षेत्र के आसपास के देशों के प्रति चीनी खतरे से निपटने का अकेला तरीका यह है कि आप उन समुद्री इलाकों में काम कर पाएं जिन्हें चीन ने चुपचाप चीनी समुद्रतटों में शमिल कर लिया है और परमाणु शक्ति संपन्न पनडुब्बियां यह कर सकती हैं. सबसे बड़ा संकेत यह है कि पहले चीन से मुकाबला करने में हिचकिचा रहा ऑस्ट्रेलिया अब चीन से टकराव होने की स्थिति में अमेरिका के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने को तैयार है.'' जब चीन का ध्यान अपने दक्षिणी और पूर्वी समुद्रतटों पर नई सैन्य तैयारियों में लगा है, तब कई सारे मोर्चे खोलने से बचने के लिए वह भारत के साथ सीमा विवाद पर दबाव ढीला कर सकता है.

श्याम सरण
पूर्व विदेश सचिव

“ औकस के साथ अब सैन्य हिस्से को अलग कर दिया गया है ताकि आसियान देश बेचैन न हों. **अब आप उनके साथ सहयोग के दूसरे क्षेत्रों में** काम कर सकते हैं''

इस बीच, अमेरिका ने जिस ढंग से औकस बनाया, उसने बड़े यूरोपीय देश फ्रांस को नाराज कर दिया जो ऑस्ट्रेलिया को पारंपरिक पनडुब्बियां बेचने के अंतिम चरण में था. फ्रांस ने इसे विश्वासघात माना और बड़ी तकरार पैदा करते हुए अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया से अपने राजदूत वापस बुला लिए. चीन को काबू करने में यूरोप का साथ आना लोकतांत्रिक दुनिया की कामयाबी के लिए बेहद अहम है और बाइडन ने जिस तरह गड़बड़ तरीके से औकस समझौते को अंजाम दिया, वह इस मोर्चे पर झटका है. चीन से निपटने को लेकर फ्रांस के अमेरिका के साथ पहले से ही मतभेद थे. मुद्दों से निपटने में चीन के आक्रामक पैंतरों का वह कड़ा विरोधी था, पर इनके समाधान के लिए नया शीत युद्ध या सैन्य टकराव छेड़ने के पक्ष में वह नहीं था. फ्रांस के एक कूटनीतिज्ञ कहते हैं, ''हमें क्षेत्र में स्थिरता लाने के लिए चीन से सामूहिक रूप से निपटने की और उदार व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए यूरोपीय संघ को साथ लेने की जरूरत थी. अप्रत्याशित ढंग से संकीर्ण गठबंधन बनाने की नहीं.'' यूरोप चीन को दुनिया के अहम आर्थिक इंजनों में से एक होने के अलावा जलवायु परिवर्तन से लड़ाई के लक्ष्य हासिल करने की भी कुंजी मानता है और यह भी कि उसके सहयोग की जरूरत पड़ेगी.

अमेरिका में फ्रांस के साथ रिश्ते ठीक करने की कोशिशें चल रही हैं, इधर विशेषज्ञ औकस को चीन को रोकने की कोशिशों में सैन्य गेमचेंजर के तौर पर देख रहे हैं. पूर्व सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन कहते हैं, ''जब आप परमाणु शक्ति संपन्न पनडुब्बियों से दक्षिण चीन सागर पर नजर रखकर उसे चीन की झील बनने से रोक सकें, तभी आप चीनियों को ताइवान पर कब्जा करने के लिए सैन्यबल का इस्तेमाल करने से भयपूर्वक रोक सकते हैं. इसलिए क्वाड की भले ही रंगाई-पुताई कर दी गई हो, ये भारत के लिए अच्छी घटनाएं हैं.'' मेनन कहते हैं कि हमारे पास समुद्री मोर्चे पर चीन का मुकाबला करने के साधन नहीं हैं इसीलिए दूसरे देश वह भूमिका निभा रहे हैं, जिससे भारत को ऐसी क्षमताएं विकसित करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है. वे यह भी कहते हैं कि इस बीच भारत को जमीनी सरहद पर अपनी सुरक्षा मजबूत करते रहना चाहिए और चीन को बता देना चाहिए कि अगर बीजिंग सरहद पर अपने दुश्मनी भरे इरादे दिखाना जारी रखता है तो वह भी घुसपैठ पर नियम तोड़ने से डरेगा नहीं. चीनी नेतृत्व का मौजूदा ध्यान आंतरिक मुद्दों और अमेरिका का

ग्राफिकः तन्मय चक्रवर्ती

मुकाबला करने पर है. खासकर जब शी महज कुछेक के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए समृद्धि पर जोर देकर अपनी आर्थिक नीति में बड़े बदलाव का इशारा कर रहे हैं (बड़े कारोबारों पर हालिया कड़ी कार्रवाई पर गौर कीजिए). ऐसे में मेनन की सलाह है: ''भारत को पड़ोसियों से रिश्ते मजबूत करने की दिशा में काम करने का यह मौका गंवाना नहीं चाहिए.'' मसलन, वह बंगाल की खाड़ी की सुरक्षा को लेकर बांग्लादेश, श्रीलंका और म्यांमार के साथ काम कर सकता है.

भारत के लिए इतना ही जरूरी यह भी है कि वह हिंद-प्रशांत में अपना प्रभाव बढ़ाए. 2014 में कमान संभालने के बाद से ही मोदी इस पर पूरी सरगर्मी से जोर देते आ रहे हैं. आसियान देशों के साथ-साथ चीन के उभार के चलते वैश्विक अर्थव्यवस्था और भू-राजनीति के गुरुत्वाकर्षण का केंद्र अटलांटिक-पार से हटकर प्रशांत-पार पर आ गया है. अमेरिका ने न केवल उस हिंद महासागर का महत्व पहचाना जहां भारत चौतरफा फैला है, बल्कि चीन को रोकने की अपनी योजनाओं में भारत की अहमियत को भी माना. यही वजह है कि उसने अपने एशिया-प्रशांत सैन्य कमान का नाम बदलकर हिंद-प्रशांत कर दिया. दुनिया का दो-तिहाई कंटेनर यातायात इन्हीं दो महासागरों से होकर गुजरता है और समुद्री सुरक्षा कायम रखना क्वाड का बेहद अहम हिस्सा है. जरूरत यह है कि क्वाड अपनी सभी प्रमुख पहलों पर आसियान देशों को अपने पाले में लाए. दक्षिण कोरिया और वियतनाम ने क्वाड की पहलों का हिस्सा बनने में पहले ही दिलचस्पी दिखाई है, जिससे क्वाड प्लस की चर्चा छिड़ गई है. एक भारतीय अफसर कहते हैं, ''हिंद-प्रशांत की स्थिरता में दुनिया भर का हित है और इसे नियम आधारित संस्थाओं और मानदंडों से संचालित प्रबंधन की जरूरत है. क्वाड इसी पर जोर दे रहा है.''

शिवशंकर मेनन
पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार

"जब आप परमाणु शक्ति संपन्न पनडुब्बियों से दक्षिण चीन सागर पर नजर रख सकेंगे तो **तो आप चीनियों को ताइवान पर कब्जा करने के लिए सैन्यबल का इस्तेमाल करने से** भयपूर्वक रोक सकते हैं''

तो भी, जैसा कि टेलिस बताते हैं, अभी इसे व्यावहारिक तौर पर आजमाया नहीं गया है और क्वाड की कामयाबी वादों को तेजी से जमीन पर उतारने और ज्यादा आसियान देशों को साथ लाने पर निर्भर करेगी. इस गुट ने चीन को इशारों-इशारों में बता दिया है कि लोकतांत्रिक देश चीनी ताकत से बेचैन हैं और इस ताकत के खुलने के तरीके से भी. सवाल वही है: इस मामले में वे क्या कर सकते हैं? बुनियादी ढांचे को लेकर क्या क्वाड खासकर हिंद-प्रशांत क्षेत्र में विशालकाय बेल्ट ऐंड रोड इनीशिएटिव (बीआरआइ) का मुकाबला कर सकता है? बीआरआइ परियोजना महामारी की वजह से और चीनी दबाव, वित्तीय पारदर्शिता के अभाव और इनसे उत्पन्न पर्यावरण के नुक्सानों की वजह से धीमी पड़ी है.

बीआरआइ से मुकाबले के लिए अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने ब्लू डॉट नेटवर्क पहल को हरी झंडी दिखाई है, जिसमें विदेशों में निवेश के लिए निजी पूंजी जुटाने की खातिर वित्तीय पारदर्शिता, पर्यावरण के स्थायित्व और आर्थिक विकास पर जोर दिया गया है. मगर उनकी कोशिशें अभी चीनी पहल के पासंग भी नहीं हैं. चीन क्वाड की व्यवस्था के प्रति आसियान देशों और यूरोप के समर्थन में दरार डालकर बांटने और राज करने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा रहा है. मगर डराने-धमकाने के उसके पैतरों के फूहड़पन ने ऑस्ट्रेलिया को मजबूती से विरोधी खेमे में धकेल दिया. हालांकि टेलिस मानते हैं कि क्वाड ''अभी खेल के शुरुआती चरण में है और तब तक कारगर नहीं होगा जब तक आप आसियान देशों और यूरोप को एक साथ नहीं लाते हैं.''

एक बड़े भारतीय कूटनीतिज्ञ सहमत हैं कि ''यह खेल की शुरुआत है'', लेकिन वे कहते हैं कि क्वाड और औकस अहम जवाब हैं, और जिस तरह दूसरे विश्व युद्ध के बाद अटलांटिक गठबंधन चरणों में बना, वैसे ही आने वाले सालों में कई और उभरेंगे. अलबत्ता अगर भारत चाहता है कि उसे क्वाड में बराबर

क्षेत्र जिस पर नजर रहेगी

- हिंद-प्रशांत क्षेत्र में दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश (चीन), सबसे अधिक आबादी वाला लोकतंत्र (भारत) और सबसे अधिक आबादी वाला मुस्लिम-बहुल देश (इंडोनेशिया) स्थित हैं
- दुनिया की 10 सबसे बड़ी स्थायी सेनाओं में से सात यहीं स्थित हैं
- हिंद-प्रशांत में जी-20 के छह सदस्य शामिल हैं और यह वैश्विक धन का लगभग 40% उत्पन्न करता है
- समुद्र के रास्ते वैश्विक कंटेनर परिवहन का दो-तिहाई हिस्सा इस क्षेत्र से गुजरता है
- 2019 में, कार्बन डाइऑक्साइड के वैश्विक उत्सर्जन में इस क्षेत्र का हिस्सा 45% था-30% उत्सर्जन चीन से हुआ. विश्व के 10 सबसे बड़े ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जक में से पांच-चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया और इंडोनेशिया, इसी क्षेत्र में स्थित हैं

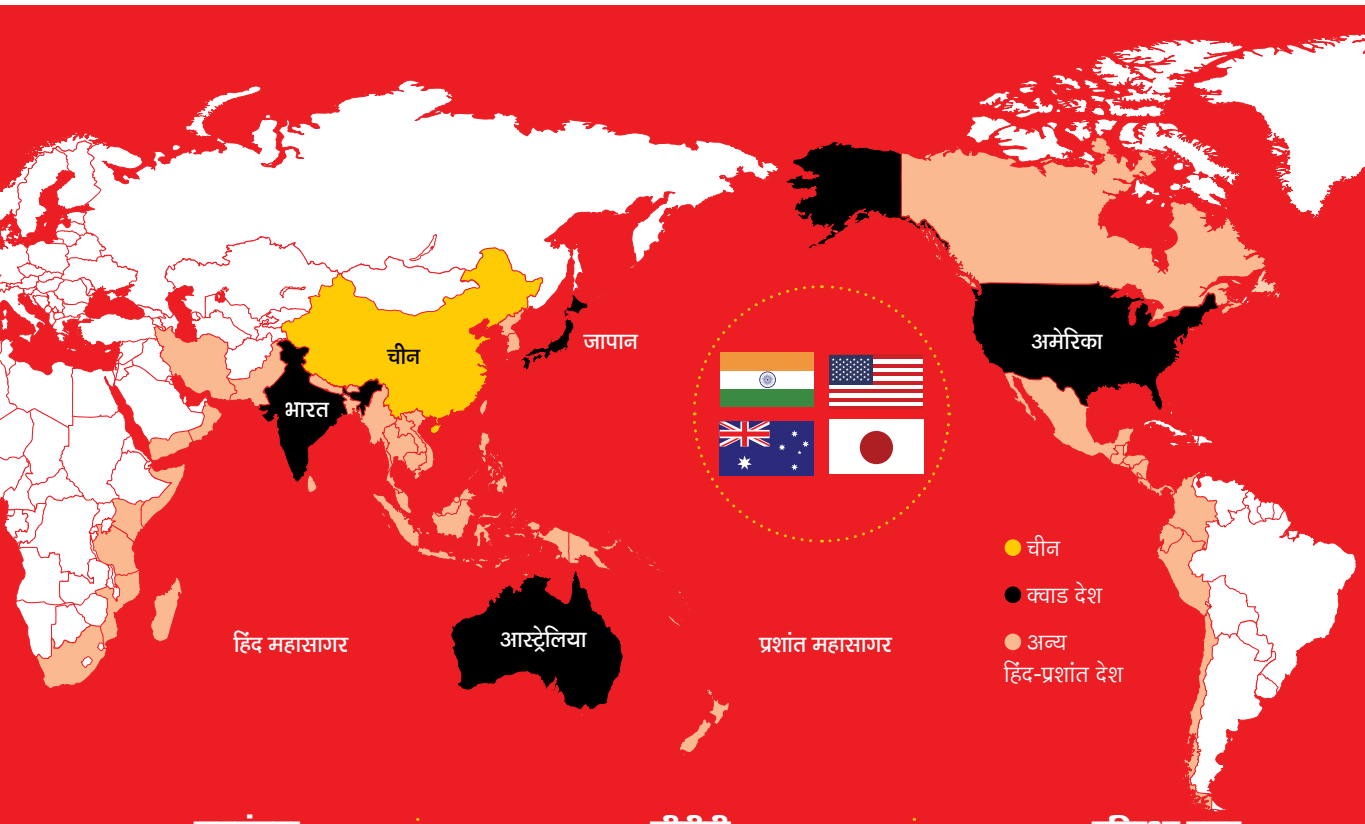

जनसंख्या
(करोड़ में)

चीन	140
भारत	137
अमेरिका	32.8
जापान	12.6
ऑस्ट्रेलिया	2.5

जीडीपी
ट्रिलियन डॉलर (लाख करोड़ रुपए) 2019

अमेरिका	21.4 (1,590)
चीन	14.3 (1,060)
जापान	5.1 (376)
भारत	2.9 (213)
ऑस्ट्रेलिया	1.4 (104)

प्रतिरक्षा बजट
अरब डॉलर (हजार करोड़ रु.) 2019

अमेरिका	703 (5,228)
चीन	251 (1,866)
भारत	68 (508)
जापान	46 (341)
ऑस्ट्रेलिया	25 (185)

का भागीदार माना जाए, तो उसके सामने कई चुनौतियां हैं, खासकर टेक्नोलॉजी के मोर्चे पर. एक तो आर्थिक विकास के रास्ते को लेकर अपने क्वाड भागीदारों के साथ उसके भारी मतभेद हैं, खासकर जब उनका भरोसा खालिस बाजार-संचालित समाधानों पर है. 5जी के मामले में अमेरिका और जापान किसी खास देश के बजाए निजी कंपनियों पर भरोसा करेंगे कि वे इसे विकसित और प्रतिस्पर्धा करें. सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी के मामले में दोनों देश मीलों आगे हैं और उनके बराबर आने के लिए भारत को अरबों डॉलर के निवेश की जरूरत होगी.

यही नहीं, हम क्षेत्रीय समग्र आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) या प्रशांत-पार भागीदारी के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौता (सीपीटीपीपी) सरीखे व्यापार समझौतों में शामिल होने को लेकर अनिच्छुक हैं और इसके बजाए हरेक देश के साथ दोतरफा समझौतों को तवज्जो देते हैं. इससे भी क्षेत्र में हमारी प्रभावित करने की क्षमता घटी है. मेनन कहते हैं, ''भारत को चाहिए कि अमेरिका को अपनी तरफ रखे, क्योंकि उसे चीन पर दबाव डालने के लिए जरूरी सैन्य टेक्नोलॉजी की दरकार है. इसके अलावा उसे अमेरिका का ध्यान लद्दाख में गलवान के बजाए ताइवान पर बनाए रखना चाहिए.'' यह बेशक ऊंचे दांव का खेल है. खुशकिस्मती से इसे निपुणता से खेलने के लिए महाशक्तियों की मेज पर भारत भी उठ-बैठ रहा है. ■

''अमेरिका, जापान और आस्ट्रेलिया के विपरीत, भारत और चीन की जमीनी सरहदें मिलती हैं. **और इसलिए दांव कहीं ज्यादा ऊंचे हैं''**

बेदखली की सियासत

असम की भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार, भूमि अतिक्रमण की समस्या को युद्धस्तर पर निपटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन भूमि सुधारों और पुनर्वास योजनाओं के अभाव में अतिक्रमण हटाने के ये अभियान राजनीति से प्रेरित कार्य बन गए हैं

कौशिक डेका

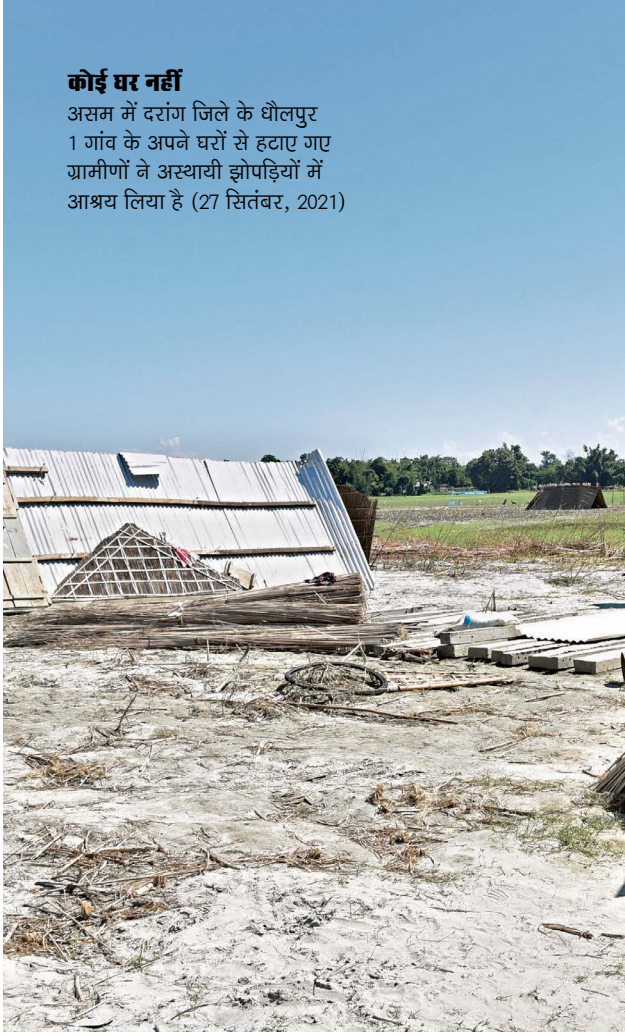

कोई घर नहीं
असम में दरांग जिले के धौलपुर 1 गांव के अपने घरों से हटाए गए ग्रामीणों ने अस्थायी झोपड़ियों में आश्रय लिया है (27 सितंबर, 2021)

सितंबर की एक उमस भरी सुबह. वकील हुसैन, ब्रह्मपुत्र नदी से निकली एक जलधारा के किनारे बैठे हैं. रह-रहकर दूर से आने वाली ठंडी हवा के झोंके एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे इस 18 वर्षीय युवक के मन के उस ताप के आगे बेअसर साबित हो रहे हैं जो उसके अंदर अपने फोन पर चल रहे असमिया चैनलों के समाचारों को देखने के बाद उपजा है. इन समाचारों के माध्यम से वे पिछले सप्ताह हुई घटनाओं को समझने की कोशिश करते हैं. एक बढ़ई के सहायक के रूप में काम करने वाले हुसैन, असम के दरांग जिले के सिपाझार इलाके के धौलपुर गांव के उन लोगों में से एक हैं, जिन्होंने 20 सितंबर को राज्य सरकार की ओर से अतिक्रमण के खिलाफ शुरू किए गए अभियान में अपना घर खो दिया था.

ब्रह्मपुत्र नदी की दो धाराओं के बीच रेत की विशाल पट्टी पर बसा धौलपुर, गुवाहाटी से सिर्फ 70 किमी उत्तर पूर्व में स्थित है. हुसैन अभी जहां बैठे हैं, उनका घर वहां से महज 100 मीटर की दूरी पर हुआ करता था. वे और उनके साथी ग्रामीणों ने प्रशासन के निर्देशानुसार, नदी की धारा के दूसरे किनारे पर टिन की अस्थायी संरचनाओं में डेरा डाल रखा है, हुसैन अक्सर धारा को पारकर अपने गिरा दिए 'घरों' के पास चले जाते हैं. अतिक्रमण हटाने के दौरान धौलपुर के लोगों ने ज्यादा प्रतिरोध नहीं किया था. यही वजह है कि हुसैन बार-बार समाचारों को खंगालते हैं ताकि वे यह समझ सकें कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के चौथे दिन यानी 23 सितंबर को ऐसा क्या गलत हुआ कि पुलिस ने गोली चला दी जिसमें दो ग्रामीणों की मौत हो गई.

हुसैन अकेले नही हैं. मोइनुल हक नामक शख्स को गोली मारने के बाद उसे पुलिसकर्मियों और सरकार के नियुक्त फोटोग्राफर की ओर से बेरहमी से पीटने के दिल दहला देने वाले वीडियो के वायरल होने के बाद, पूरे देश ने नाराजगी जताई. हक पर आरोप था कि उसने बेदखली के आदेशों का पालन करने से मना करते हुए पुलिसकर्मियों पर बांस के डंडे से हमला बोल दिया. पुलिस ने न सिर्फ उसे गोली मार दी, बल्कि उसकी लाश को घसीटते हुए उस पर लातें बरसाईं.

आलोचक इसे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार की ओर से शुरू किए गए धार्मिक उत्पीड़न का एक नमूना बताते हैं. धौलपुर से हटाए गए लोग मूलरूप से बांग्लाभाषी आप्रवासी मुसलमान थे. वहीं, सरकार का आरोप है कि अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया को हिंसक बनाने में विवादास्पद उग्रवादी मुस्लिम संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआइ) सहित कई बाहरी तत्वों ने बड़ी भूमिका निभाई और स्थानीय लोगों को हिंसा के लिए उकसाया गया. लेकिन, सच्चाई असम में भूमि अतिक्रमण के जटिल इतिहास में निहित है, जो अवैध आप्रवासियों तथा नदियों के कटाव के कारण और अधिक जटिल हो जाता है.

अतिक्रमण का इतिहास

राज्य सरकार के अनुसार, 6,652 वर्ग किमी सरकारी भूमि (गोवा के आकार का दोगुना) और असम की कुल 17,393 वर्ग किमी वन भूमि का 22 फीसद या 3,878.8 वर्ग किमी (दिल्ली के आकार का लगभग तीन गुना) अतिक्रमण के अधीन है. असम में भूमि अतिक्रमण की समस्या राजनैतिक मुद्दा

मानस दास

गुम होती जमीन

नदियों की ओर से कटाव के कारण हर साल असम में बहुत अधिक जमीन गुम हो जाती है और यहां अवैध अतिक्रमण भी एक बड़ा मसला है

6,652
वर्ग किमी
सरकारी जमीन—गोवा के आकार का दोगुना—अतिक्रमण के अधीन है

22
फीसद
या असम के कुल 17,393 वर्ग किमी वन भूमि का 3,878.8 वर्ग किमी (दिल्ली के आकार का तीन गुना) भूमि अवैध अतिक्रमण की शिकार है

4,200
वर्ग किमी
भूमि (सिक्किम के आकार के आधे से ज्यादा) आजादी के बाद से अब तक असम में कटाव की वजह से खत्म हो गई हैं

बन गई है क्योंकि इसे अक्सर बांग्लादेश से आए अवैध घुसपैठियों के मुद्दे से जोड़ा जाता है. असल में, अवैध घुसपैठ के खिलाफ असम का छह साल लंबा आंदोलन मंगलदोई लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में 45,000 अवैध नामों का पता चलने के साथ शुरू हुआ था. वर्तमान संघर्ष का केंद्र धौलपुर गांव उसी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है.

1985 में असम समझौते के साथ वह आंदोलन खत्म हो गया. समझौते में कहा गया था कि जो लोग 1971 से पहले बांग्लादेश से असम आए थे, उन्हें कानूनी रूप से भारतीय नागरिक माना जाएगा. वैसे, इनमें से कई बांग्लाभाषी आप्रवासी, पीढ़ियों से असम में रह रहे हैं, पर पूरे राज्य में एक आम धारणा यह है कि असम में अतिक्रमण 1971 के बाद आए अवैध प्रवासियों ने किया है. इस धारणा को 2017 में एक आधिकारिक स्वीकृति तब मिली, जब असम के मूल निवासियों के भूमि अधिकारों की सुरक्षा के लिए गठित छह सदस्यीय समिति की अंतरिम रिपोर्ट में कहा गया कि राज्य के 33 जिलों में से 15 में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए हावी हैं. रिपोर्ट में कहा गया, ''अवैध बांग्लादेशी, हमलावर सेना की तरह भूमि पर उतरते हैं...भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत और सांप्रदायिक नेताओं की शह पर नदी किनारे की भूमि पर रातोरात अवैध रूप से गांव खड़े कर देते हैं...'' रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के अतिक्रमण के बाद 18 सत्रों (वैष्णव मठ) की पहचान खतरे में थी.

यहां तक कि 2019 का संशोधित नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) भी इस मुद्दे को हल करने में विफल रहा. गुवाहाटी विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष अखिल रंजन दत्ता कहते हैं, ''सारे अतिक्रमणकारी अवैध घुसपैठिए हैं, यह एक गलत धारणा है. यहां तक कि सरकार ने भी उन्हें अवैध आप्रवासी घोषित नहीं किया है. यह भी सच है कि अतिक्रमण हुआ है लेकिन उसे हटाने की सभी आवश्यक कार्रवाई मानवीय और व्यावहारिक दृष्टिकोण के साथ की जानी चाहिए.''

असम में भूमि अतिक्रमण की समस्या एक राजनीतिक मुद्दा बन गई है क्योंकि इसे अक्सर बांग्लादेश से आए अवैध घुसपैठियों के मुद्दे से जोड़ा जाता है

जब *इंडिया टुडे* ने धौलपुर का दौरा किया, तो कई बेदखल लोगों ने स्थायी निवासी के प्रमाण के रूप में अपने आधार और मतदाता पहचान पत्र दिखा दिए, लेकिन माना कि उनमें से कुछ एनआरसी से बाहर हैं. अन्य लोगों ने यह दावा करते हुए जमीन के दस्तावेज दिखा दिए कि उन्होंने जमीन खरीदी थी और राजस्व करों का भुगतान किया था, लेकिन कागजात असल में सरकार के स्वामित्व वाली पेशेवर चराई भूमि (पीजीआर) के अवैध रूप से इस्तेमाल के लिए प्रशासन की ओर से लगाए गए जुर्माने के थे, जहां वे आज बस गए हैं. 55 वर्षीय दिहाड़ी मजदूर अशरफ का दावा है कि वे यहां से सिर्फ 10 किमी दूर स्थित रेतीली पट्टी अपरिया से पलायन करके आए थे. वे कहते हैं, ''मैं इन आधिकारिक दस्तावेजों को नहीं समझता. मैं केवल इतना कह सकता हूं कि मैंने 2005 में 10,000 रुपए का भुगतान करके धौलपुर में जमीन खरीदी थी.''

धौलपुर में बेदखली की दास्तान

असम के दरांग जिले में ब्रह्मपुत्र की दो धाराओं के बीच फंसा नदी तट का यह इलाका, जिसमें धौलपुर, फुहुराटोली, कुरुवा, खोलिहोइ और बझनापाठरांड सरीखे कई गांव हैं, 1980 के दशक से ही टकरावों का केंद्र रहा है

अमित रॉय

1983 में आठ असमिया मूल निवासी नौजवान संदिग्ध अवैध आप्रवासियों के हाथों मारे गए, जिसे लेकर काफी उपद्रव हुआ था

1993 में कांग्रेस सरकार ने फुहुराटोली के 199 बंगाली मुस्लिम परिवारों में से प्रत्येक को 5 बीघा जमीन आवंटित की. वीजीआर इलाका होने की वजह से अगले साल यह गैरकानूनी पाया गया. बेदखली के आदेश दिए गए. कोई कार्रवाई नहीं हुई.

2013 में आरटीआइ से पता चला कि इस इलाके में 77,420 बीघा सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर लिए गए हैं

फरवरी 2015 में दक्षिण मंगलदई गोवाला संस्था के अध्यक्ष कोबाड अली ने असम लैंड ग्रैबिंग (प्रोहिबिशन) ऐक्ट 2010 के तहत मंगलदई जिला अदालत में मुकदमा दायर किया और 77,420 बीघा जमीन से गैरकानूनी कब्जाधारियों को बेदखल करने की मांग की

2017 में कुरुवा गांव के आनंद दास की संदिग्ध अवैध अतिक्रमणकारियों ने हत्या कर दी. मामला 60 परिवारों की बेदखली के साथ खत्म हुआ

सितंबर में जिला प्रशासन ने करीब 10,000 बीघा सरकारी जमीन, जो प्राथमिक रूप से पीजीआर थी, खाली करवाने के लिए 1,000 से ज्यादा परिवारों को बेदखल करने का अभियान छेड़ा. अतिक्रमणकारियों और पुलिस के बीच झड़प में दो नागरिक मारे गए और 11 पुलिसकर्मी घायल हुए

जुलाई में 77,420 बीघा अतिक्रमित जमीन पर मूलनिवासी युवाओं के बीच वनारोपण और कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देने के कृषि परियोजना के लिए राज्य के बजट में 9.6 करोड़ रुपए रखे गए. कृषि विभाग के अनुरोध पर जिला प्रशासन ने इलाके को 'सामुदायिक कृषि भूमि' घोषित किया

जून 2021 में जिला प्रशासन ने 49 परिवारों को बेदखल करके 180 बीघा जमीन छुड़वाई, जिस पर एक पहाड़ी के ऊपर बने धोलपुर शिव मंदिर की संचालन समिति ने दावा किया था. स्थानीय लोगों का कहना है कि वे जल्द ही वापस चले आए

2020 में एक अन्य व्यक्ति ललित दास गुमशुदा हो गया. स्थानीय लोगों का कहना था कि अतिक्रमणकारियों ने उसे मार डाला

स्रोतः असम सरकार

अधिकतर आप्रवासी अक्सर नदियों के किनारे बनी रेतीली पट्टियों में बस जाते हैं. बाढ़ और कटाव के कारण उस रेतीली भूमि का अक्सर अस्तित्व ही खत्म जाता है और वे अन्य स्थानों पर चले जाते हैं. इस वजह से यह मुद्दा और अधिक जटिल हो जाता है. सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार, आजादी के बाद से असम ने 4,200 वर्ग किमी भूमि कटाव के कारण खो दी.

चराई भूमि पर कब्जे के कारण कई डेयरी सहकारी समितियां शिकायत दर्ज कराने को विवश हुईं. जब एक आरटीआइ के जवाब में यह पता चला कि सिपझार राजस्व सर्कल के तहत फुहुराटोली, धौलपुर, कुरुवा, खोलीहोई और बजनापाथर के गांवों की 77,420 बीघा से अधिक सरकारी स्वामित्व वाली ग्राम चारागाह भूमि (वीजीआर) और पीजीआर का अवैध अतिक्रमण हो चुका है तो वहां के मूल निवासी जो कि ज्यादातर असमिया भाषी हिंदू, मुस्लिम और नेपाली हैं, क्रोधित हो गए. दो साल बाद, दूध उत्पादकों के एक संगठन दक्षिण मंगलदाई गोवाला संस्था के अध्यक्ष कोबाड अली ने अवैध कब्जाधारियों को बेदखल करने की मांग करते हुए मंगलदाई जिला अदालत में एक मामला दायर किया. इसी तरह, 2019 में डेयरी किसानों की सहकारी संस्था दक्षिण कामरूप सियालमारा दुग्ध समाबे समिति ने शिकायत की कि कामरूप जिले के पलाशबाड़ी राजस्व सर्कल के तहत मोहमर्दिया चार में कई अवैध निवासियों ने 900 बीघा भूमि पर कब्जा कर लिया था. एक सरकारी जांच में पाया गया कि लगभग 400 बीघा पीजीआर भूमि पर अतिक्रमणकारी अवैध रूप से खेती कर रहे थे.

स्थानीय लोगों ने अतिक्रमणकारियों की ओर से आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा दिए जाने की भी शिकायत की है. 2017 में, संदिग्ध अवैध घुसपैठियों के हाथों धौलपुर के पास कुरुवा गांव के आनंद दास की हत्या के कारण 60 परिवार गांव छोड़कर चले गए थे. उसी गांव का एक अन्य व्यक्ति ललित दास 2020 में लापता हो गया था. धौलपुर से सटे सनोवा गांव के एक दूध उत्पादक किसान 52 वर्षीय जेहरुल इस्लाम कहते हैं, ''उन्होंने हमारे मवेशियों को चराने की जमीन पर कब्जा कर लिया है. वे हमारी भैंसें चुराते हैं. हमारी बेटियां घुसपैठियों से अपहरण और यौन उत्पीड़न के डर से कहीं आने-जाने से घबराती हैं.''

असम ने 2020 में गैंगरेप और हत्याओं के 26 मामले दर्ज किए (देश में तीसरा सबसे अधिक) और पुलिस सूत्रों का दावा है कि सभी 26 मामले उन जिलों में हुए जहां मुसलमानों की संख्या असामान्य रूप बढ़ी थी. पुलिस को संदेह है कि आबादी का यह इजाफा अवैध घुसपैठ के कारण हुआ है. धौलपुर, दरांग जिले में पड़ता है. यह असम के नौ मुस्लिम बहुल जिलों में

इंडिया टुडे
देश की भाषा में देश की धड़कन

INDIA TODAY GROUP

यूपी की धान खरीद व्यवस्था में कई छेद
लालफीताशाही के शिकंजे में कारोबार
सरना: पुराने धर्म पर नई बहस
इंडिया टुडे
कोविड-19 वैक्सीन
कितनी सुरक्षित? कितनी कारगर?
बाजार में आने के लिए तैयार नई वैक्सीन से जुड़े सारे अहम सवालों के जवाब

राम मंदिर को माना गया मोदी की प्रमुख उपलब्धि
अनुच्छेद 370 हटाने को मिला जोरदार समर्थन
बेरोजगारी मानी गई सबसे बड़ी समस्या
इंडिया टुडे
देश का मिजाज सर्वेक्षण
मोदी और हिंदुत्व का बोलबाला
देशव्यापी छमाही सर्वेक्षण से जाहिर है कि नरेंद्र मोदी लोकप्रियता के शिखर पर बरकरार हैं और संघ परिवार के एजेंडे को मिली जबरदस्त बढ़त

सबसे भरोसेमंद स्रोतों से, सबसे सटीक जानकारी

सब्सक्राइब करें और पाएं 21% तक की छूट

हां! मैं इंडिया टुडे को सब्सक्राइब करना चाहता/चाहती हूँ

अपनी पसंद के सब्सक्रिप्शन को टिक करें और फॉर्म को इस पते पर भेज दें– **वी केअर, लिविंग मीडिया इंडिया लि. सी–9, सेक्टर–10, नोएडा 201302 (भारत)**

टिक करें	अवधि	कुल अंक	कवर प्राइस (₹)	ऑफर प्राइस (₹)	डिस्काउंट
☐	2 वर्ष	104	~~5200~~	4099	21%
☐	1 वर्ष	52	~~2600~~	2199	15%

कृपया फॉर्म को ब्लॉक लेटर में भरें

मैं चेक/डीडी जमा कर रहा/रही हूँ जिसकी संख्या.....है और इसे दिनांक..... को लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड के पक्ष में ..... (बैंक का नाम).....रुपये की धनराशि (दिल्ली से बाहर के चेक के लिए ₹ 50 रुपये अतिरिक्त जोड़ें, समान मूल्य के चेक मान्य नहीं होंगे) के लिए बनवाया गया है.

नाम..... पता.....

..... शहर..... राज्य..... पिन.....

मोबाइल..... ईमेल.....

सब्सक्राइब करने के लिए यहां स्कैन करें.

ऑफर के विषय में विशेष जानकारी के लिए निम्न माध्यमों से संपर्क भी कर सकते हैं

हमारे टॉल फ्री नंबर पर कॉल करें
18001800100 (0120) 2479900

ईमेल भेजें
wecare@intoday.com

लॉग ऑन करें
subscriptions.intoday.in/indiatoday-hindi

लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड इस ऑफर या इसके अंश को कभी भी समाप्त करने या आगे बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है. अन्य नियम व शर्तों की जानकारी के लिए कृपया देखें-www.indiatoday.in

से एक है जहां जनसंख्या में वृद्धि, राज्य की औसत वार्षिक जनसंख्या वृद्धि 1.7 फीसद से अधिक है. उच्च जनसंख्या वृद्धि और कटाव ने न केवल उन्हें गरीबी के दुष्चक्र में फंसा दिया है, बल्कि भूमि के लिए बड़ी भूख भी पैदा कर दी है और वे अक्सर वन क्षेत्रों और धार्मिक संस्थानों की खाली भूमि को निशाना बनाते हैं. इससे मूल निवासियों से उनका संघर्ष होता है. मसलन, कोकराझार में 2012 की जातीय हिंसा एक आरक्षित जंगल को कब्रिस्तान के रूप में इस्तेमाल करने के प्रयास से शुरू हुई जिसका बोडो आदिवासियों ने विरोध किया था. उस हिंसा में करीब 100 लोग मारे गए थे.

2012 में, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को 'अवैध प्रवासियों' से खाली कराने की मांग करते हुए एक जनहित याचिका दायर की गई थी. असमिया लोगों के लिए बड़े धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व के 16वीं शताब्दी के तपस्वी श्रीमंत शंकरदेव की नगांव स्थित जन्मस्थली बटाद्रव थान (वैष्णव मठ) की भूमि को मुक्त करने की भी मांग की गई थी. पिछली सरकारों, ज्यादातर कांग्रेस नेतृत्व वाली, ने बमुश्किल ही कोई कार्रवाई की.

वहीं, मूल निवासियों के गुस्से को भांपते हुए, भाजपा ने असम को अतिक्रमणकारियों से मुक्त करने के लिए जाति, माटी और भेटी (घर) की रक्षा का चुनावी वादा किया था. 2016 में पहली भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद, तत्कालीन मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, मोरीगांव जिले के मायोंग, बटाद्रव थान और सिपाझार में कई अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाए. दरअसल, 2012 में दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने 9 अक्तूबर, 2015 को अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था और यह कार्रवाई अदालत के आदेश के बाद आवश्यक हो गई थी.

मई में सरमा के शपथ लेने के बाद से, 300 से अधिक परिवारों—सभी बांग्लाभाषी मुसलमानों—को होजई जिले के लंका, शोणितपुर जिले के जमुगुरीहाट और करीमगंज जिले के पाथरकांडी जैसे क्षेत्रों से बेदखल कर दिया गया है.

धौलपुर में क्या गड़बड़ी हुई?

अतिक्रमण हटाने की सबसे बड़ी कार्रवाई धौलपुर में शुरू हुई जिसमें 77,420 बीघा भूमि को खाली कराना था. आलोचकों का मानना है कि यहां पर शिव मंदिर के रूप में एक ऐसी चीज मौजूद थी जिसकी जरूरत भाजपा को असम में अवैध घुसपैठियों के प्रति स्थानीय लोगों के गुस्से में हिंदू राष्ट्रवाद का तड़का लगाने के लिए थी. ऑल असम माइनॉरिटी स्टूडेंट्स यूनियन के सलाहकार ऐनुद्दीन अहमद कहते हैं, ''सरकार की मंशा मुसलमानों को सताने और उसका सियासी लाभ लेने की है.''

जून में सरमा ने धौलपुर शिव मंदिर की 180 बीघा भूमि पर अवैध रूप से कब्जा जमाए 49 परिवारों को अपनी निगरानी में हटवाया. जुलाई में, राज्य के बजट में 77,420 बीघा अतिक्रमित भूमि में वनीकरण और कृषि कार्यों को बढ़ावा देने के लिए एक 'कृषि परियोजना' के लिए 9.6 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए. कृषि विभाग के अनुरोध पर, जिला प्रशासन ने क्षेत्र को 'सामुदायिक कृषि भूमि' घोषित किया. धौलपुर में करीब 10,000 बीघा सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा जमाए एक हजार से ज्यादा परिवारों को हटाया गया.

कांग्रेस और अखिल भारतीय यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट जैसे विपक्षी दलों तथा कई सामाजिक समूहों का दावा है कि 23 सितंबर की पुलिस बर्बरता मुसलमानों के उत्पीड़न की भाजपा की नीति का नतीजा है. वहीं मुख्यमंत्री सरमा हिंसा में बाहरी ताकतों का हाथ बताते हैं, ''घटना के एक दिन पहले, बेदखल परिवारों के लिए भोजन के इंतजाम के नाम पर, पीएफआइ ने उस जगह का दौरा किया था.'' घटना की न्यायिक जांच की घोषणा करते हुए, उन्होंने

आलोचकों का कहना है कि अतिक्रमण-रोधी अभियान ने भाजपा को अवैध आप्रवास के खिलाफ असम के लोगों के गुस्से में हिंदू राष्ट्रवाद का तड़का लगाने का मौका दिया है

दावा किया कि लोगों के एक समूह ने ग्रामीणों को बेदखली से बचाने का वादा करते हुए 28 लाख रुपए जुटाए और उन्होंने एक कॉलेज शिक्षक सहित छह लोगों का नाम लिया. इनमें से दो को गिरफ्तार कर लिया गया है.

अतिक्रमण हटाने के अभियान में शामिल पुलिस अफसरों का दावा है कि ग्रामीणों ने एक 'धनुषाकार' व्यूह रचना में उन पर कुल्हाड़ी, ईंट और डंडों से हमला किया. पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे तो उन्होंने इसके प्रभाव को बेअसर करने के लिए जूट के ढेर में आग लगा दी. दरांग के एसपी सुशांत बिस्व सरमा कहते हैं, ''ये हरकत ग्रामीणों की नहीं हो सकती. उन्हें बाहरी तत्वों ने हमले के तरीके सिखाए थे.''

कुछ ग्रामीणों ने माना कि उनमें से कुछ ने पुलिसकर्मियों ने एक 16 वर्षीया लड़की को मारा-पीटा, जिससे उसका एक हाथ टूट गया, जिस पर आक्रामक प्रतिक्रिया व्यक्त की थी. 26 वर्षीय रुस्तम अली दावा है कि उनके दादा 70 साल पहले धौलपुर आए थे पर उनके पास अपनी पहचान या जमीन के स्वामित्व को साबित करने के लिए कोई दस्तावेज नहीं है. वे कहते हैं, ''हम बांस को काटकर तरह-तरह की चीजें बनाते हैं इसलिए हमारे हाथ में अक्सर एक दाभ होता है. इसका मतलब यह नहीं है कि हम उन पर दाभ से हमले कर रहे थे.'' 48 वर्षीय ताजिमुद्दीन और 60 वर्षीय सुकमान अली जैसे कुछ लोगों ने स्वीकार किया कि उन्हें कहा गया कि अगर वे ''अपनी जमीन और घर की सुरक्षा की लड़ाई लड़ना चाहते हैं'' तो उन्हें कुछ पैसे दान करने होंगे. कई अन्य लोगों ने किसी को पैसे देने से इनकार किया.

आगे क्या?

सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता उपमन्यु हजारिका के नेतृत्व में अवैध घुसपैठ का विरोधी करने वाले संगठन प्रबजन विरोधी मंच के अनुसार, धौलपुर में अतिक्रमण हटाने के काम बीते वर्षों में कई बार हुआ है, पर अतिक्रमणकारी या तो वापस लौट आते हैं या फिर किसी अन्य क्षेत्र में जमीन कब्जा लेते हैं. हालिया अभियान के बाद भी, अतिक्रमणकारियों को बस नदी के उस पार चले जाने के लिए कहा गया है, जो कि 77,420 बीघा सरकारी भूमि का हिस्सा है. कई अधिकारियों का मानना है कि कटाव के कारण कुल क्षेत्रफल 77,420 बीघा से घटकर लगभग 35,000 बीघा रह गया है. इसलिए भले ही सरकार ने 10,000 बीघा जमीन खाली करा ली हो, लेकिन 25,000 बीघा जमीन अभी भी अतिक्रमण के लिए खुली है.

सरमा ने घोषणा की है कि उनकी सरकार, सरकारी भूमि से हटाए गए ऐसे लोगों को छह बीघा भूमि देगी जो वाकई भूमिहीन हैं. वे कहते हैं, ''उनमें से कई बरपेटा और धुबरी जैसे क्षेत्रों से आए हैं जहां उनके पास काफी जमीन है.'' भूमि के रिकॉर्ड को सुव्यवस्थित करने, डिजिटल इंटरफेस शुरू करने और राजस्व विभाग को अवैध भूमि सौदों से छुटकारा दिलाने के लिए, उनकी सरकार ने 2 अक्तूबर से 'मिशन बसुंधरा' योजना शुरू की है. एक अभियान के तहत सितंबर में जमीन के 500 से अधिक दलालों को गिरफ्तार किया गया था.

बेघरों का पुनर्वास कार्य पूरा होने में कुछ प्रक्रियात्मक देरी हो सकती है, हुसैन का एक और सवाल है: उनके पिता उसी भूमि पर खेती क्यों नहीं कर सकते जहां सरकार समर्थित जुताई उन्हें बेदखल किए जाने के मात्र दो दिन बाद ही शुरू हो गई थी? वहां अब कोई मवेशी तो नहीं चरा रहा है. ■

आज तक

देश का नं. 1 हिंदी न्यूज़ ऐप

जुड़े रहिए हर खबर से,
कहीं भी, कभी भी

अभी डाउनलोड करें

aajtak.in/app

उपलब्ध है

तमिल सभ्यता की खोज

तमिराबरानी नदी घाटी में हाल की पुरातात्विक खोजों से इस अंचल में यही कोई ईसा पूर्व 1200 के आसपास एक जटिल सभ्यता के उत्थान का पता चलता है

अमरनाथ के. मेनन

धरोहर की तलाश
शिवगलै में उत्खनन वाली खाइयों का ऊपर से लिया गया चित्र; (नीचे) शिवगलै में जस का तस रखा मिला अस्थि कलश

तमिलनाडु के पुरातत्व आयुक्त रामलिंगम शिवानंतम 27 अगस्त को मायामी (अमेरिका) स्थित बीटा एनैलिटिक टेस्टिंग लैबोरेटरी से आई रिपोर्ट को देखकर हक्के-बक्के रह गए. लैबोरेटरी ने थूडुकुड्डी जिले के शिवगलै से खुदाई में मिले एक अस्थि कलश के अवयवों की रेडियोकार्बन डेटिंग की थी और यह रिपोर्ट उसी के बारे में थी. रिपोर्ट इस नतीजे पर पहुंची कि कलश के अवयव, जिनमें चावल और मिट्टी भी थे, ईसा पूर्व 1155 के थे, यानी उस समय तमिलनाडु में एक कृषि सभ्यता फूल-फल रही थी. यह दिलचस्प खबर देखते ही देखते पूरे महकमे में फैल गई. शिवानंतम ने रिपोर्ट तमिलनाडु के पुरातत्व सलाहकार प्रोफेसर के. राजन के साथ साझा की, जिन्होंने इसे राज्य के पुरातत्व मंत्री तंगम तेन्नारासु तक बढ़ा दिया और उन्होंने फिर इस बारे में मुख्यमंत्री एम.के. स्तालिन को सूचित किया.

स्तालिन ने 9 सितंबर को जब तक राज्य विधानसभा में इसका खुलासा नहीं किया तब तक रिपोर्ट को राज ही रखा गया. उन्होंने कहा, ''निष्कर्षों से यह बात साबित हुई है कि पोरुनै (आज की तमिराबरानी) नदी घाटी सभ्यता 3,200 साल पुरानी थी. वैज्ञानिक तरीके से यह स्थापित करना सरकार का काम है कि भारतीय उपमहाद्वीप का इतिहास तमिल भूभाग से शुरू होना चाहिए.'' इस खोज और राज्य में कई स्थलों पर हुई खोजों से उस इतिहास पर रोशनी पड़ रही है जो उत्तरपश्चिम के ज्यादा जाने-माने सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की छाया में ढक गए हैं (देखें: धरोहर वाली जगहें और निकल रहे आंखें खोलने वाले निष्कर्ष).

पुरातात्विक खोजों की पहचान या उनके सही समय का पता लगाना अक्सर मुश्किल काम होता है. अलबत्ता कुछ खोज इतिहास की हमारी समझ को आमूलचूल बदल देती हैं. शिवगलै से मिला कलश इनमें से एक है. यह हाल की दूसरी खुदाइयों में शिवगंगलै जिले के कीलाड़ी से मिली प्राचीन कलाकृतियों से 600 साल ज्यादा पुरानी है. इसी तरह कीलाड़ी, आदिचनल्लूर, शिवगलै, कोरकै, कोडुमनाल, मयिलादुंपरै और गंगैकोंडाचोलपुरम सहित दूसरे कई स्थलों पर खुदाई से भारतीय प्रायद्वीप में एक स्थापित

फोटोः तमिलनाडु पुरातत्व विभाग

सभ्यता, उसके नगरों और खेती-किसानी के आविर्भाव की अनुमानित तारीख कहीं ज्यादा पहले की साबित होती रही है. आदिचनल्लूर ईसा पूर्व 950 का है और पोरुनै के मुहाने पर प्राचीन बंदरगाह कोरकै ईसा पूर्व 785 का है. ताजातरीन खोज के बाद पुरातत्वविद् और इतिहासकार अब मानते हैं कि करीब 3,000 साल पहले पोरुनै के आसपास एक उन्नत सभ्यता फली-फूली थी, जिसमें आदिचनल्लूर और शिवगलै इनसानी बस्तियां थीं और कोरकै एक महत्वपूर्ण बंदरगाह हुआ करता था.

शिवगलै के अस्थि कलश के काल निर्धारण से पता चलता है कि इस क्षेत्र में ईसा पूर्व 12वीं सदी में चावल की खेती होती थी. दूसरी प्राचीन कलाकृतियों से यह भी संकेत मिलता है कि उस समय यहां लोहे का काम

उन्नत ढंग से किया जाता था. साथ ही रांगे, कांसे और सोने की वस्तुओं का मिलना और उस समय के अत्यधिक विकसित रीति-रिवाज उस सभ्यता के उन्नत स्तर की गवाही देते हैं.

राजन कहते हैं, ''अनुष्ठान, श्मशान का आकार और श्मशान की चीजों की बड़ी तादाद—जिनमें पोरुनै नदी घाटी से मिली मिट्टी की कृतियां, लोहे और सोने की चीजें और दूसरी कलाकृतियां भी हैं—बताती है कि उस वक्त खास किस्म के शिल्पी थे, जो व्यवस्था में बंधे समाज में रहते थे. भित्ति चित्रों की निशानियां और दमिली (जिसे तमिल-ब्राह्मी या ब्राह्मी लिपि के भिन्न रूप तमिलि के रूप में भी जाना जाता है) लिपि में उत्कीर्ण मिट्टी के टूटे बर्तन लिखने की प्रणाली की मौजूदगी का भी संकेत देते हैं.''

धरोहर वाली जगहें और निकल रहे आंखें खोलने वाले निष्कर्ष

कोडुमनाल
यहां एक बावड़ी भी मिली है जिसमें दो तरफ से उतरने के रास्ते हैं. इसके अलावा उत्कीर्ण मिट्टी के बर्तन, मनके और भट्ठियां भी प्राप्त हुई हैं

मयिलादुंपरै
खुदाई में तीन पैरों वाला घड़ा मिला. निष्कर्ष इस बात की ओर संकेत करते हैं कि यहां के लोगों ने 4,000 साल पहले खेती से जुड़ी गतिविधियां शुरू कर दी थीं

आदिचनल्लुर
नाद सरीखे पात्र से ढका हल्के लाल रंग का कलश मौके से प्राप्त हुआ है. (2019 और 2021 के बीच हुए) ताजा उत्खनन में एक रिहाइशी क्षेत्र का अध्ययन किया गया. इसमें 847 वस्तुएं, शिल्पाकृतियां और मिट्टी के बर्तनों के अनगिनत नमूने मिले हैं. प्राप्त वस्तुओं में दमिली लिपि में उत्कीर्ण मिट्टी के बर्तन और भित्तिचित्रण वाले उपकरणों से खुदे 500 से ज्यादा मिट्टी के बर्तन भी शामिल हैं. इसके अलावा तांबे और लोहे की मुद्रिकाएं, हाथीदांत के मनके, दुर्लभ और अमूल्य रत्न, शीशे और टेराकोटा की चूड़ियां तथा टेराकोटा के ड्रेनेज पाइप भी मिले हैं

शिवगलै
अस्थिकलश गाड़ने वाली जगह 1155 वर्ष ईसा पूर्व की है. बड़ी संख्या में चाकू-छुरियां (ऊपर चित्र में) भी यहां प्राप्त हुई हैं

गंगैकोंडाचोलपुरम
यहां मिली ईंटों की एक बड़ी रचना के राजेंद्र चोल-प्रथम के महल का हिस्सा होने की संभावना है. कई दक्षिणपूर्व एशियाई देशों को जीतने के लिए की जाने वाली उनकी समुद्र यात्राओं का इतिहास की गाथाओं में विस्तृत उल्लेख मिलता ही है

कीलाड़ी
यहां मिली चीजों में ईंटों से निर्मित बड़ी रचनाएं, गाड़े जाने वाले कलश और अर्घ्य देने वाले पात्र (ऊपर), दमिली लिपि में उत्कीर्ण मिट्टी के बर्तन, औसत मूल्य वाले रत्न, चांदी के सिक्के और गंगा घाटी के काली पॉलिश वाले बर्तन शामिल हैं. हाल ही में मिले चांदी के एक सिक्के पर सूर्य, चंद्रमा, वृश्चिक तारामंडल के प्रतीक और कुछ ज्यामितीय रचनाएं उभरी हुई हैं और यह सिक्का ईसा पूर्व चौथी शताब्दी का है

कोरकै
खुदाई वाली जगह से हॉप-स्कॉच (खिलौना पत्थर) मिले हैं. उत्तर क्षेत्र के, ईसा पूर्व 5वीं सदी के काले, पॉलिश किए बर्तन भी प्राप्त हुए हैं. यह स्थान ईसा पूर्व 8वीं सदी से भी पहले एक प्रमुख बंदरगाह रहा होगा. शंख की चूड़ियां बनाने का यहां फलता-फूलता उद्योग होने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं

ग्राफिक: तन्मय चक्रवर्ती

स्थापित सभ्यता

नए तथ्यों के उद्घाटन के बारे में बताते हुए राजन कहते हैं कि पोरुनै नदी के नजदीक माइक्रोलिथिक औजारों (पत्थर से बने छोटे औजारों) की खोज बताती है कि कई हजार साल पहले यहां इनसान आबाद थे. पोरुनै नदी के किनारे लौह युग के कई स्थलों की खोज से कृषि आधारित परिपक्व सभ्यता के होने का पता चलता है. पहले मिली प्राचीन कलाकृतियां इस सभ्यता के विकास के स्तर की गवाही देती हैं. इनमें लंबी दूरी के समुद्री व्यापार, मिट्टी के बर्तन बनाने, खनन और धातुओं की ढलाई की विशिष्ट तकनीकों के इस्तेमाल, अनूठी और विस्तृत अंत्येष्टि व्यवस्थाओं और सबसे ज्यादा उत्कीर्ण मिट्टी के बर्तनों के प्रमाण शामिल हैं.

तेन्नारासु कहते हैं, ''आदिचनल्लूर में मिली प्राचीन कलाकृतियों से साबित होता है कि जो लोग यहां रहते थे, वे लौह अयस्क, पिटवां लोहे, ढलवां लोहे और कच्चे लोहे सहित हर प्रकार के लोहे के काम में माहिर थे और यह भी संभव है कि उन्होंने समुद्र में जाने वाली नावें बना ली हों.'' 2014 से कीलाड़ी में हुई खुदाई से तमिलनाडु के प्राचीन अतीत के एक अध्याय का खुलासा हुआ, जिसने इस लोक मान्यता को झुठला दिया कि इस इलाके में नदी तट पर बसी कोई सभ्यता नहीं थी और ब्राह्मी लिपि पूरी तरह मौर्यों से निकली थी. प्रमाणों से सिद्ध हुआ है कि ईसा पूर्व छठी शताब्दी जितने पहले वैगई नदी के किनारों पर एक साक्षर समुदाय फला-फूला.

पोरुनै नदी सभ्यता की गूंज दो सहस्राब्दी पुराने संगम युग के साहित्य में भी सुनाई देती है, जो पहली और दूसरी ईस्वी सदी में लिखा गया. तमिल अध्येता और *जर्नी ऑफ अ सिविलाइजेशन: इंडस टू वैगई* के लेखक आर. बालकृष्णन बताते हैं, ''संगम साहित्य में कोरकै का बंदरगाह के तौर पर 11 जगहों का जिक्र है.'' दूसरा उदाहरण उन नामों का है जो संगम युग के साहित्य में भी मिलते हैं और प्राचीन कलाकृतियों पर भी उत्कीर्ण हैं. बालकृष्णन कहते हैं, ''शिवगलै में तमिलि में 'अतन' नाम से उत्कीर्ण मिट्टी के बर्तन का टुकड़ा मिला है. यही नाम कीलाड़ी में भी मिट्टी के बर्तनों पर तमिलि में उत्कीर्ण मिला है.'' प्राचीन कलाकृतियों और अभिलेखों की खोज से तमिल संस्कृति की पुरातनता का भौतिक प्रमाण मिलता है, जो पहले केवल संगम साहित्य से स्थापित था.

राज्य के पुरातत्व विभाग का लक्ष्य आगे पोरुनै नदी घाटी सभ्यता का विशद अध्ययन करना है. यह एक बहुआयामी काम होगा, जिसमें नदी के बहने की दशा-दिशा, समुद्र तल में उतार-चढ़ाव, मॉनसून के पैटर्न, मिट्टी की उर्वरता, औद्योगिक गतिविधि और प्राचीन स्थलों के भीतर और उनके बीच क्षेत्रीय सांस्कृतिक संबंधों का विश्लेषण किया जाएगा. इस सभ्यता के पैमाने और स्वरूप की थाह लेने के लिए इसमें मोतियों के लिए गोताखोरी, सिंचाई प्रौद्योगिकी और कांस्य तथा लोहे के काम की क्षमताओं सरीखे प्रौद्योगिकीय नवाचारों का अध्ययन भी होगा. शिवानंतम कहते हैं, ''खुदाइयों का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में सबसे शुरुआती बस्तियों का पता लगाना है, ताकि लौह युग और आरंभिक ऐतिहासिक संस्कृति और उसके पारगमन की संभावनाओं को समझा और तमिल-ब्राह्मी लिपि के विकासक्रम का अध्ययन किया जा सके.''

सिंधु घाटी से रिश्ता

ये पुरातात्विक खोजें इस बात पर जोर देती हैं कि भारत के प्राचीन अतीत के बखान में बड़े सुधार की जरूरत है. कुछ इतिहासकार सिंधु घाटी सभ्यता के भौतिक प्रमाणों और दक्षिण भारत के पुरातात्विक स्थलों से खोजे गए भौतिक प्रमाणों में समानता देखते हैं. वे कहते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता और दक्षिण भारत तथा श्रीलंका की सभ्यताओं के बीच भाषाई संबंध रहा हो सकता है. भौतिक प्रमाणों में समानता की बात करें, तो इनमें नारी की एक छोटी-सी मूर्ति (जिसे मां देवी की मूर्ति माना गया है) भी है, जो सिंधु घाटी सभ्यता स्थल से मिली एक अन्य मूर्ति से आश्चर्यजनक ढंग से मिलती-जुलती है. उस समय इस्तेमाल की जाने वाली तांबे की मिश्रधातुओं में भी समानताएं हैं.

2004-05 में आदिचनल्लूर स्थल की खुदाई की अगुआई करने वाले टी. सत्यमूर्ति इसे दक्षिण भारतीय संस्कृति का नाभिकेंद्र स्थल कहते हैं. इसके वे कई कारक बताते हैं, जैसे इसका नदी किनारे

होना, खनन और धातु ढलाई की अत्यंत विकसित तकनीकें, चिकनी चूरा (शुद्ध) मिट्टी का इस्तेमाल और मिट्टी के छोटे-छोटे बर्तनों पर विकसित सजावट. अहम खोजों में कुम्हारों की गोल भट्ठियां, प्रार्थनाघर, सोने के आभूषण, कांसे के बर्तन और लोहे की वस्तुएं तथा हथियार हैं.

राजन कहते हैं, ''पुरातात्विक स्थलों को उनकी ज्यादा बड़ी पृष्ठभूमि में देखने और आंकने की जरूरत है. हमें पुरातात्विक क्षेत्र से निकली हर प्राचीन कलाकृति का अध्ययन करके उसका सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य स्थापित करना होता है. मसलन, मेट्टूर के नजदीक तेलुंगानूर और मंगाडू स्थल लोहे के काम का सबसे शुरुआती समय ईसा पूर्व 1800 बताते हैं. कीलाड़ी दमिलि (तमिल-ब्राह्मी) का सबसे शुरुआती समय ईसा पूर्व छठी शताब्दी बताता है. यह भारत में ब्राह्मी से उत्कीर्ण मिट्टी के बर्तनों का अब तक उपलब्ध सबसे पुराना समय है. पूरे देश में हमने प्राकृत-ब्राह्मी से उत्कीर्ण 100 से भी कम मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े देखे, जबकि तमिलनाडु में और खासकर कोडुमनाल में तमिल-ब्राह्मी से उत्कीर्ण 1,000 से ज्यादा मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े मिले हैं.'' विशाल ईंट के ढांचों के अवशेष स्थल के शहरी स्वरूप की तरफ इशारा करते हैं, जिनसे कपड़ा उद्योग, तमिल-ब्राह्मी से उत्कीर्ण मिट्टी के बर्तनों, उत्तर भारत के औसत मूल्य वाले रत्नों, मानकीकृत बांट और हाथी दांत के पासों सरीखी विलासिता की चीजों के होने का पता चलता है.

देखना होगा नई रोशनी में

पुरातत्वविदों और इतिहासकारों का कहना है कि प्राचीन भारत में शहरीकरण की प्रक्रिया का अध्ययन केवल गंगा के मैदानों की सभ्यता पर ध्यान केंद्रित करके नहीं किया जा सकता. कीलाड़ी और शिवकलै की खोजों में दमिलि लिपि की पुरातनता के सबूत मिलने के साथ तकरीबन उसी वक्त तमिलनाडु में शहरी ढांचों के प्रमाण बढ़ते जा रहे हैं. हड़प्पा काल के भारत के बाद का कालक्रम तय करने की पद्धति पर इसके असर पड़ेंगे ही.

हड़प्पा सभ्यता के स्थान का दक्षिण की तरफ खिसकना पुरातात्विक तौर पर साबित सचाई है. लोथल, धौलावीरा और देसलपुर सरीखे स्थल इसके गवाह हैं. हड़प्पा और हड़प्पा के बाद की सबसे धुर दक्षिणी सीमा 1960 के दशक के बाद से अभी तक महाराष्ट्र के दाइमाबाद में ठहरी है. हो सकता है पुरातात्विक इच्छा न होने की वजह से ऐसा हो. बालकृष्णन सवाल करते हैं, ''वर्ना इस उदासीनता की क्या वजह है कि एलेग्जेंडर रिया (ब्रिटिश पुरातत्वविद् जिन्होंने 1800 के दशक के आखिरी सालों और 1900 के शुरुआती सालों में दक्षिण भारत में काम किया था) के 100 साल बाद

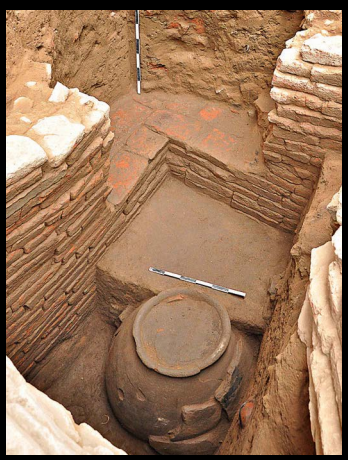

महिमा तमिराबरानी नदी की

तमिराबरानी नदी का उद्गम तमिलनाडु में ही प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर के नजदीक है. वैसे तो इसे सदाबहार नदी माना जाता रहा है लेकिन गर्मी के मौसम में यह सूखकर अक्सर एक पतली धार भर रह जाती है. तमिराबरानी राज्य की सबसे छोटी नदी भी है. यह अंबासमुद्रन तालुका में पश्चिमी घाट की पोथिगै पहाड़ियों से निकलकर तिरुनेल्वेली और थूथुकुड्डी जिलों से होती हुई कोरकै (जिला तिरुनेल्वेली) पहुंचकर मन्नार की खाड़ी (बंगाल की खाड़ी) में मिल जाती है.

इस प्रकरण में ताजा पुरातात्विक खोजों से उभरे तथ्यों को लेकर तमिलनाडु में खासी चर्चा है. इसके निष्कर्ष बताते हैं कि यहां 3,200 साल पुरानी नदी घाटी केंद्रित एक सभ्यता की मौजूदगी थी. इसी संदर्भ में तमिल साहित्य की शख्सियतों ने डीएमके (द्रविड़ मुनेत्र कड़गम) सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है कि नदी को अब इसके ऐतिहासिक नाम पोरुनै से पुकारा जाएगा. (तमिल साहित्य की महानतम कृतियों में से एक और तमिल के महान कवि कंबार के 12वीं सदी में रचे गए महाकाव्य *कंब रामायणम* में भी इस नदी को पोरुनै ही कहा गया है.)

तमिराबरानी को ठेठ संगम काल से लेकर नायकर युग (ईसा पूर्व छठी सदी से 17वीं सदी ईस्वी) तक तमिल साहित्य में थन पोरुनै, पोरुनाल और पोरुंतम भी कहा गया है.

अतीत पर से हटती धूल

(ऊपर बाएं से क्रमशः) तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन कीलाड़ी में खुदाई स्थल पर; मयिलादुंपैरै में मिले गाड़े जाने वाले कलश; शिवगलै में खनन वाली खाइयां; कोरकै में ईंटों की एक आयताकार रचना

संगम के छंदों में छिपे हैं बहुत-से राज

हाल की पुरातात्विक खोजों ने ऐतिहासिक अध्ययनों के लिए संदर्भ सामग्री के तौर पर दो सहस्राब्दी पुराने संगम ग्रंथों के भरोसेमंद होने की बात को वैध ठहराया है. तमिलनाडु की ज्यादातर पुरातात्विक खोजों में जो तथ्य सामने आए हैं वे एक तरह से इन ग्रंथों में फुटनोट के तौर पर पहले से दर्ज हैं. भारत के किसी भी दूसरे पुरातात्विक क्षेत्र में ऐसा नहीं हुआ है.

संगम साहित्य पर शोध करने वाले और सेवानिवृत्त सिविल सेवक आर. बालकृष्णन, जो फिलहाल ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के मुख्य सलाहकार हैं, कहते हैं, ''संगम साहित्य का नजरिया जड़ों से जुड़ा, व्यावहारिक, मोटे तौर पर पंथनिरपेक्ष और समावेशी है. यह उपमहाद्वीप के तमाम लैंडस्केप की अनूठी समझ और प्रत्यक्ष ज्ञान को दर्शाता है. कोई भी दूसरे ग्रंथ समुद्री व्यापार से जुड़ी बारीकियों की इतनी सटीक लिखित तस्वीर नहीं देते. कोई भी प्राचीन साहित्य भारत के दो समुद्रों और एक महासागर को इतनी गहराई से नहीं जानता.''

अध्येताओं का कहना है कि संगम साहित्य से उपमहाद्वीप के इतिहास के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है. बालकृष्णन कहते हैं, ''इसमें ऐसे स्थानों और अतीत की शख्सियतों से साफ तौर पर जुड़ी पिछली यादें हैं जो इतिहास की किताबों को पता नहीं थीं. हम संगम ग्रंथों को बोलने का एक मौका तो दें.''

भी आदिचनल्लूर का अध्ययन नहीं किया गया. यह इस तथ्य के बावजूद कि इसके अहम सुराग 1904 जितना पहले मौजूद थे.''

मगर कुछ लोग ताजातरीन खोजों की व्याख्याओं में एहतियात बरत रहे हैं. कैंब्रिज यूनिवर्सिटी में साउथ एशियन आर्कियोलॉजी के एमेरिटस प्रोफेसर दिलीप के. चक्रवर्ती कहते हैं, ''दक्षिण में मिले शुरुआती मिट्टी के बर्तनों पर चित्रों की ढेरों निशानियां मिली हैं. एक मान्यता हालांकि यह है कि कुछ मामलों में ये सिंधु लिपि से मेल खाते हैं, लेकिन इस मान्यता की गहरी छानबीन नहीं हुई और यह बहुत कमजोर नींव पर टिकी है.'' वे यह भी कहते हैं, ''यह संभव है कि कीलाड़ी कुछ हद तक संगम काल का निरूपण करता हो. मुझे निजी तौर पर लगता है कि संगम साहित्य से 500 ईस्वी के आसपास की जीवनस्थिति की झलक मिलती है.''

तमिलनाडु की पुरातात्विक खुदाई की आगे की कोशिशों के पहले चरण में केरल के अब पत्तनम के रूप में जाने वाले प्राचीन मुसिरि बंदरगाह का अध्ययन किया जाएगा. इसी तरह के अध्ययन आंध्र प्रदेश के वेंगी, कर्नाटक के तलैकाडु और ओडिशा के पलूर में भी किए जाएंगे, जहां तमिल-ब्राह्मी अभिलेख मिले हैं. इनमें अंतरराष्ट्रीय स्थल भी हैं. तमिल लिपि वाले मिट्टी के बर्तन मिस्र और ओमान में भी पाए गए हैं. मिस्र के कसीर-अल-कदीमी और पर्निका एनेक्के में और ओमान के खोर रोरी में अध्ययन किए जाएंगे, ताकि इन स्थलों के साथ व्यापार के प्राचीन तमिल संबंध स्थापित किए जा सकें. इस काम में इन देशों के पुरातत्वविदों को साथ लिया जाएगा. इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया और वियतनाम सरीखे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में भी अध्ययन किए जाएंगे.

काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पुरातत्व विज्ञान के प्रोफेसर रवींद्र एन. सिंह कहते हैं, ''हाल की खुदाइयों से उन सालों के दौरान सांस्कृतिक कायापलट की अच्छी तस्वीर उभरकर आती है. इनसे पता चलता है कि भारत दूसरी सहस्राब्दी ईस्वी से पहले सांस्कृतिक तौर पर अच्छी तरह जुड़ा था.'' मगर आरंभिक ऐतिहासिक काल से पहले इस क्षेत्र में संस्कृति के विकास के बारे में बहुत कम समझा गया है. इस लिहाज से कीलाड़ी अनुसंधान में निर्णायक मोड़ था. तमिल विश्वविद्यालय तंजावुर में समुद्री इतिहास और समुद्री पुरातत्व शास्त्र विभाग के प्रमुख डॉ. डी. सेल्वाकुमार कहते हैं, ''तमिलनाडु और केरल, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में नवपाषाण संबंध और लौह युग की शुरुआती आबादियों के अनुसंधान की जरूरत है ताकि हमारी समझ बेहतर हो सके.''

राजन और भी आगे देखते हैं. वे कहते हैं कि तमिलनाडु और दूसरे दक्षिणी राज्यों में मिल रहे नए प्रमाणों के आधार पर भारत के इतिहास को ही नए सिरे से लिखने की जरूरत है. ■

बेमिसाल
सुब्रत और युष्मिता बोस आसनसूली गांव में प्राथमिक कक्षा के बच्चों के साथ

देवज्योति चक्रवर्ती

सयंभरता रूरल स्किल डेवलपमेंट फाउंडेशन

स्थापना: 2014 में

बकरेश्वर, बीरभूम, पश्चिम बंगाल

आत्मनिर्भरता का सबक

खुशी की सौगात: *साधनहीन बच्चों को सहारा देने वाली शिक्षा, उनकी आर्थिक मदद और करियर के बारे में उन्हें सलाह*

रोमिता दत्ता

यह बात है यही कोई जनवरी 2014 की. पश्चिम बंगाल में बीरभूम जिले के तातीपाड़ा के दिहाड़ी मजदूर मधुसूदन घोष अपने बेटे बापन की पढ़ाई की किताबें खरीदने के लिए 500 रुपए की मदद की खातिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर सुब्रत बोस के पास गए. बोस इस तरह खैरात देने के इच्छुक नहीं दिख रहे थे. लेकिन मधुसूदन ने जब बेटे की मार्कशीट दिखाई तो बोस को लगा कि इस मामले में उनकी सहायता बड़ा गुल खिला सकती है.

तातीपाड़ा हाइस्कूल की कक्षा 9 के टॉपर बापन बस इतना चाहते थे कि वे इंजीनियर बनें और पिता के चूहों से भरे मिट्टी के घर को दुरुस्त करवाएं. स्कूल जाने से पहले सुबह वे लोगों के घरों में दूध और मूढ़ी (भुने चावल से बनी लाई) पहुंचाते, स्कूल से लौटकर इसी तरह के कुछ और काम निबटाते और फिर रात में जागकर पढ़ाई करते.

बापन को देखकर बोस को उन बच्चों की मदद का ख्याल आया जो होनहार तो हैं पर जिनके पास ऊंची शिक्षा के साधन नहीं हैं. यहीं से सयंभरता रूरल स्किल डेवलपमेंट फाउंडेशन की बुनियाद तैयार हुई. बोस और उनकी दोस्त वास्तुकार देवयानी मित्रा और सरकारी नौकरी कर रहे दिलीप पाल, जिनका बाद में निधन हो गया, सहित सात अन्य लोगों ने मिलकर आखिरकार 24 अगस्त, 2014 को इसकी स्थापना की.

सयंभरता का अर्थ है आत्मनिर्भरता. यह बकरेश्वर और नजदीकी 10 गांवों—बहादुरगंज,

खुशी का मंत्र

"मुस्कान के साथ बच्चों के चेहरे पर जो चमक आती है उससे हमारे हमारे दिल को बेहद सुकून मिलता है. हम इन बच्चों के बहुत एहसानमंद हैं. ये हमारी उम्मीद की किरण हैं"

—देवयानी मित्रा,
सह-संस्थापक, सयंभरता

बुरेमा, गद्धारपुर, देदोहा, कोहलियारा, तेतुलबंध, मुक्तिपुर, आसनसूली, तातीपाड़ा और लतुंतोला—के साधनहीन बच्चों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए काम करता है. शुरुआत में गणित, अंग्रेजी और भौतिक विज्ञान सरीखे विषय पढ़ने वाले कक्षा 8, 9 और 10 के 82 छात्रों के लिए मददगार शिक्षा केंद्र खोले गए. स्कूल जाने से पहले रोज तीन घंटों की कोचिंग के नतीजतन न केवल उन्हें मिलने वाले अंकों में सुधार आया, बल्कि सयंभरता स्कूलों में अपने बच्चों को भर्ती करवाने के लिए माता-पिता की जबरदस्त भीड़ लग गई. समंभरता के मजे-मजे में पढ़ाई, मददगार औपचारिक शिक्षा, उच्च शिक्षा सहायता और व्यवसायपरक प्रशिक्षण से जुड़े कार्यक्रमों में फिलहाल 450 छात्र पढ़ रहे हैं.

सयंभरता ने शुरुआत से पहले एक सर्वे करवाया, जिससे पता चला कि 45 फीसद छात्रों और खासकर लड़कियों ने कक्षा 8 के बाद सामाजिक-आर्थिक कारणों से स्कूल छोड़ दिया. सात साल बाद आसनसूली की छह लड़कियां संगठन की कामयाबी की नजीर बन गईं. वे अपने परिवार में शिक्षा हासिल करने वाली पहली पीढ़ी की थीं. उन्होंने न केवल 10वीं बोर्ड परीक्षा पास की बल्कि गांव के सभी बच्चों को लाने में भी मदद की. वे सरकारी फॉर्म भरने में अपने गांवों के अंगूठा-छाप लोगों की मदद करती हैं और तमाम कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताती हैं.

बोस को 'खैरात' शब्द से गहरा ऐतराज है. वे कहते हैं, ''खैरात आपको भिखारी बना देती है. सयंभरता जिम्मेदार नागरिक की तरह बड़े होने में अपने बच्चों की मदद करता है, जो आगे इसे चुका सकते हैं. यह एक किस्म का ब्याज-मुक्त कर्ज है, जिसे आप या तो मार्गदर्शक / दिशादर्शक / शिक्षक बनकर या दूसरे साधनहीन बच्चे को रुपए-पैसे की मदद के लिए अपनाकर सामाजिक भलाई के कामों से चुकाते हैं.'' संगठन उच्च शिक्षा की पढ़ाई के लिए एक बच्चे पर साल में 24,000 रुपए खर्च करता है.

इस प्रयोग के नतीजे खासा हौसला बढ़ाने वाले हैं. बापन अब शिबपुर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस ऐंड टेक्नोलॉजी से एमटेक कर रहे हैं. तातीपाड़ा के ही एक बुनकर साधन के बेटे उमाशंकर आइआइटी कानपुर से रसायनशास्त्र में एमएस कर रहे हैं. उनकी मां नियति कहती हैं, ''उन्होंने मेरे बेटे के लिए बेहतरीन—आइआइटी प्रोफेसर—शिक्षकों का इंतजाम किया. आइआइटी में केमिकल इंजीनियरिंग की प्रोफेसर गार्गी मैम ने केमिस्ट्री में मेरे बेटे की रुचि पहचानने में मदद की.''

बापन की बड़ी बहन तारा भी सयंभरता में थीं. अब वे रामपुर हाट सरकारी अस्पताल में नर्स हैं. आज वे 30,000 रुपए महीना कमाती हैं और एक अन्य बच्चे की पढ़ाई के लिए मदद देती हैं. छह और लड़कियों ने नर्सिंग का करियर चुना और सरकारी तथा पीयरलेस सरीखे निजी अस्पतालों में कार्यरत हैं. कमला, सरमा, मंदिरा, मनीषा, सुप्रीति, सुचंदना और मिनती सरीखी कई लड़कियां खाकी या नर्स की सफेद यूनिफॉर्म पहनने की महत्वाकांक्षा से आगे बढ़ रही हैं. बोस कहते हैं, ''वे स्कूल-पूर्व बच्चों के लिए हमारी शिक्षिकाएं भी हैं. उन्हें बच्चों को पढ़ना, लिखना, जिंदगी के हुनर या पाठ्येतर गतिविधियां सिखाने के लिए 500 रुपए स्टाइपेंड मिलता है.''

देवयानी कहती हैं, ''एक वक्त था जब महत्वाकांक्षा पूछे जाने पर बच्चों को कुछ पता नहीं होता था. गरीबी ने उनसे सपने देखने का हक भी छीन लिया था. हमने बहादुरगंज की कक्षा 9 की छात्रा चंदना से उसका सपना पूछा तो रोने लगी. यह कहने से पहले कि वह डॉक्टर बनना चाहती है, उसने कहा कि वह गरीब है, बहुत गरीब.'' सयंभरता उनके सपनों का जिंदा रहना पक्का कर रहा है.■

मुझे किससे *खुशी मिलती है*

लवलीना बोरगोहैन

2020 टोक्यो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता

''मम्मी, पापा और बहनों के साथ वक्त बिताकर मुझे खुशी बल्कि यूं कहें कि बहुत ज्यादा खुशी मिलती है. पिछले करीब आठ साल से मुझे यह नहीं मिल पाई थी. घर में अपनों के साथ गुजरा हर पल मुझे सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है''

खुशी के सूत्र

कामना छिब्बर

फोर्टिस हेल्थकेयर के मानसिक स्वास्थ्य और व्यवहार संबंधी विज्ञान विभाग की प्रमुख

1. पसंदीदा और सुख देने वाली चीजें करें
2. अपने साथ वक्त बिताएं. खुद अपनी देखभाल खुशी के लिए अहम है
3. जिंदगी में जो मिला है, उसके लिए शुक्रगुजार हों
4. रिश्तों को अहमियत दें और उन्हें संजोएं. प्रभावी सहायता तंत्र बनाने के लिए उनको खाद-पानी दें
5. बड़े लक्ष्य हैं और उसके लिए कड़ी मेहनत में जुटे हैं तो भी अब तक जो हासिल किया उससे संतोष जताएं
6. इस समझ के साथ भावनात्मक संतुलन बनाएं कि अच्छा और बुरा दोनों है और यह सबके साथ होता है
7. स्थितियों को अलग-अलग नजरिए से देखने की कोशिश करके सकारात्मक नजरिया बनाए रखें
8. हालात को लेकर भावनात्मक बोझ से दब जाने की बजाए जिंदगी की स्थितियों के प्रति समस्या का हल खोज लेने वाला नजरिया अपनाएं
9. जिंदगी के छोटे-छोटे लम्हों का आनंद उठाएं. बड़े लक्ष्यों की उपलब्धि में ही सिद्धि न खोजें
10. परिवार और दोस्तों के साथ बिताने के लिए नियमित वक्त निकालें

सिनेमा

अब और जद्दोजहद नहीं

स्कैम 1992 से तकदीर पलटने के साथ **प्रतीक गांधी** हिम्मत और आत्मविश्वास से अपना शिल्प तराश रहे

प्रतीक गांधी की जिंदगी दो हिस्सों में बंटी है—*स्कैम* से पहले और *स्कैम* के बाद. पहले हिस्से में उन्हें रंगमंच और गुजराती फिल्मों के ऐसे अभिनेता के तौर पर देखा गया, जिसने *रांग साइड राजू* (2016) और *बे यार* (2014) सरीखी फिल्मों में अपनी अदाकारी से प्रभावित भी किया और मोहित भी. दूसरा गेमचेंजिंग हिस्सा पिछले साल उनकी पहली हिंदी वेबसीरीज *स्कैम 1992: द हर्षद मेहता स्टोरी* (सोनी लिव पर) की रिलीज के साथ शुरू हुआ. दागदार स्टॉकब्रोकर के किरदार में गांधी इतने दमदार थे कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं की तकरीबन हर ईयर-एंड लिस्ट में उनका नाम शीर्ष पर था. वे कहते हैं, ''लोग मुझे दूसरे नजरिए से देखने लगे. पहले मैं काम के लिए जिन लोगों से मिला, वे अब मेरे साथ काम करने को उत्सुक हैं. वे मुझे मुख्य किरदार के तौर पर लेकर प्रोजेक्ट शुरू करने को तैयार हैं.''

इन्हीं में एक प्रोजेक्ट *भवाई* है, जो इसी महीने रिलीज हो रही है. हालांकि इसकी शूटिंग गांधी ने स्कैम से अपनी किस्मत पलटने के पहले की थी. यह रोमांटिक ड्रामा है, जिसका नाम पहले *रावण लीला* था. कहानी दो महत्वाकांक्षी अदाकारों के इर्द-गिर्द घूमती है, जो रामलीला में रावण और सीता के किरदार निभाते हुए प्यार कर बैठते हैं. बस फिर क्या था, अफरा-तफरी मच जाती है जब लोग मंच पर उनके किरदारों की वजह से उनके रोमांस पर ऐतराज जताते हैं. हाशिये के हिंदू धड़ों को नाराज करने के लिए दो मिनट का ट्रेलर काफी था. उन्होंने फिल्म और बनाने वालों पर ईशनिंदा का आरोप लगाया. गांधी ने जबरदस्त ऑनलाइन ट्रोलिंग झेली. उनके परिवार के सदस्यों को भी जहरीले बहस-मुबाहिसे में घसीट लिया गया.

गांधी को लगता है कि उनके निभाए किरदार की तरह फिल्म को भी गलत समझा जा रहा है. वे कहते हैं, ''आज धारणाएं हमें हांक रही हैं. सूचनाएं तमाम जगहों से आ रही हैं और बहुत ज्यादा सूचनाएं हमें उलझा देती हैं. हम चुन नहीं पाते कि क्या गलत क्या सही है. लोगों को बहकाना आसान है. दस लोग आपके बारे में कुछ कहेंगे और फिर उसे गलत साबित करने की जिम्मेदारी आपकी.'' उन्हें उम्मीद है कि दर्शक फिल्म देखेंगे और सच्ची मंशा खुद ही पता कर लेंगे.

बॉक्स ऑफिस पर *भवाई* का जो अंजाम हो, गांधी का करियर साफ ऊपर बढ़ रहा है. *स्कैम* के बाद उन्होंने दो हिंदी फिल्मों और एक वेबसीरीज (डिज्नी+ हॉटस्टार पर *सिक्स सस्पेक्ट्स*) की शूटिंग की. उन्होंने तापसी पन्नू और विद्या बालन के साथ दो और फिल्में साइन की हैं. गांधी अब दूसरे ज्यादा मशहूर गांधी—मोहनदास करमचंद गांधी—के बारे में एक नाटक को फिर जिंदा करने के लिए रंगमंच पर लौटने को कसमसा रहे हैं.

करियर के इस शायद सबसे संतोषजनक और काम से भरपूर दौर में 41 वर्षीय गांधी को ऐसे 'अनकहे सवाल' से नहीं जूझना पड़ता कि—'हो पाएगा कि नहीं?' स्कैम में उनका काम खुद बोलता है. वे कहते हैं, ''अपनी कला की खोज की हिम्मत और आत्मविश्वास मुझमें है. मुझे खुद को साबित नहीं करना पड़ता.''

—सुहानी सिंह

इस महीने रिलीज हो रही प्रतीक गांधी की नई फिल्म *भवाई* दो नवोदित कलाकारों के इर्दगिर्द घूमती है जो रावण और सीता का रोल करते हुए प्यार में पड़ जाते हैं

किताबें

आतंक से लड़ने के नाम पर सरकारी आतंक

मोहम्मद वक़ास

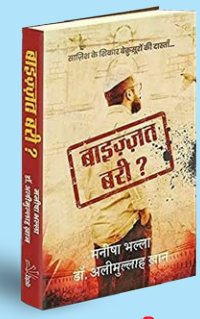

बाइज़्ज़त बरी
लेखकः **मनीषा भल्ला, डॉ. अलीमुल्लाह ख़ान**
बीपीबी पब्लिकेशंस, दिल्ली
कीमतः **295 रुपए**

कश्मीर में जॉनसन ऐंड जॉनसन के इंचार्ज तारिक अहमद डार अनंतपुर के ऑफिशियल दौरे के बाद 10 नवंबर, 2005 को श्रीनगर लौट रहे थे. वहां अस्पताल के बाहर इंतजार कर रहीं अपनी बीवी रुकैया से उन्होंने कहा कि वे 10-12 मिनट में पहुंच जाएंगे लेकिन रुकैया का यह इंतजार 12 साल खिंच गया क्योंकि पांपोर के पास दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के जवानों ने उनके शौहर को अगवा कर लिया. वे उन्हें मारते-पीटते और गालियां देते जम्मू से हेलिकॉप्टर में बैठाकर दिल्ली ले गए. पुलिस ने उसी साल दिल्ली सीरियल बम ब्लास्ट के आरोपी की गिरफ्तारी का दावा किया और मीडिया ने बिना अदालती सुनवाई के उन्हें आतंकी घोषित कर दिया.

पुलिस उनसे इस धमाके की जिम्मेदारी लेने के लिए अड़ी हुई थी लेकिन डार 'नाकरदा गुनाह' कबूल करने को तैयार नहीं थे. उन्हें तब तक खाना नहीं दिया गया था, उनकी टांगें 180 डिग्री पर चीर दी जातीं, कपड़े उतारकर छाती और शर्मगाहों पर बिजली के करंट दिए जाते, बेंच पर लिटाकर सिर नीचे कर दिया जाता, हाथ-पांव बांध दिए जाते और एक आदमी पेट पर बैठ जाता, मुंह में कपड़ा ठूंस दिया जाता और एक आदमी पानी से भरी बाल्टी नाक के अंदर मारता, उनकी पैंट के अंदर चूहा छोड़ दिया जाता और नीचे से पैंट बांध दी जाती. तारिक इसे जुल्म की इंतिहा मान रहे थे लेकिन यह तो शुरुआत थी. उनके मजहब को जोड़कर तरह-तरह की गालियां दी गईं, जबरन पेशाब पिलाया गया, देह पर मानव मल मला गया, सूअर के बच्चे का थूथन उनके मुंह से रगड़ा गया और जब मुंह से अल्लाह निकलता तो मार दोगुनी हो जाती. उनसे कहा गया, ''इंडिया में रहना है तो अब राम-राम बोलना होगा.'' पचपन दिनों तक पुलिस रिमांड में यातना झेलने के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया, जहां उन्हें देखकर कैदियों का राष्ट्रप्रेम जाग जाता था. बारह साल तक कानूनी लड़ाई के बाद 2017 में उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया.

पत्रकार मनीषा भल्ला - डॉ. अलीमुल्लाह खान ने देशभर के ऐसे 21 लोगों की आपबीती पेश की है, जिन्हें पुलिस ने आतंकवाद के झूठे इल्जाम में गिरफ्तार किया और फिर अदालत ने बरसों बाद 'साजिश के शिकार बेकुसूरों की दास्तान' को समझकर उन्हें *बाइज़्ज़त बरी* कर दिया. लेकिन इस बीच उन्हें दुनियाभर की अजीयतें, जुल्म, सितम, रुसवाई झेलनी पड़ीं. हिरासत में उन्हें इतनी यातनाएं दी गईं कि उन्होंने मरने की दुआ शुरू कर दी. इस बीच घर में माता-पिता की मौत हो गई, रिश्तेदारों ने किनाराकशी कर ली, परिवार के बच्चों की शादी मुश्किल हो गई, कारोबार उजड़ गया और माली हालत खस्ता हो गई.

इससे पहले अब्दुल वहीद शेख की *बेगुनाह क़ैदी* (7/11 मुंबई ब्लास्ट और दूसरे आतंकी मामलों में झूठे इल्जामों के साथ गिरफ्तार युवाओं की कहानियां) और पूर्व आइजी पुलिस एस.एम. मुशरिफ की *ब्राह्मनिस्ट्स बॉम्ब्ड, मुस्लिम्स हैंग्ड* में भी यातना और झूठे मुकदमों की दास्तानें हैं. और सबसे बढ़कर मामला सुलझाने का दावा करके इनाम और पदोन्नति पाने वाले कसूरवार पुलिसवालों को कोई सजा नहीं दी गई! यही नहीं, आतंकवाद के पीड़ित लोगों को भी इंसाफ नहीं मिला.

यातना की इन सच्ची, लोमहर्षक कहानियों से कई लोगों का ज़मीर जग सकता है. ■

एक कथाकार के आयाम

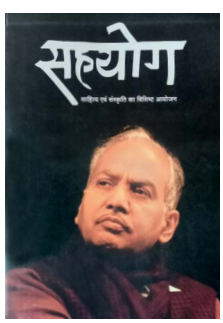

सहयोग (पत्रिका)
प्रधान संपादकः **शिवकुमार यादव**
ईमेलः **mailtosahyog20@gmail.com**
कीमतः **200 रुपए**

लघु पत्रिकाओं के डिजिटल होने का यह दौर और बची-खुची धार पर कोरोना की मार. ऐसे हालात में एक नई साहित्यिक पत्रिका निकालना और वह भी करीब 600 पेज की. *सहयोग* सच पूछिए तो उल्टी दिशा में गंगा बहाने का दुस्साहस है. ढाई सौ से ज्यादा कहानियां और दर्जन भर उपन्यास लिख चुके हिंदी के वरिष्ठ कथाकार संजीव पर एकाग्र इस अंक में यही कोई 75 वरिष्ठ/ युवा सर्जक/ समीक्षक उनके रचनाकर्म और उनकी शख्सियत की थाह लेते हैं. मजदूर, आदिवासी, किसान को केंद्रीय भूमिका में रखने वाले संजीव की कहानियों और उपन्यासों पर जितने आयामों से यहां टीका/समीक्षा की गई है उससे हिंदी कथा संसार में उनका विशिष्ट कद उजागर होता है. हालांकि समीक्षक राहुल सिंह अपने लंबे दिलचस्प तर्कपूर्ण विश्लेषण में उन्हें नैसर्गिक कथाकार नहीं मानते और उनकी आदिवासी, मुस्लिम, दलित, स्त्री प्रतिबद्धता को सलीके से प्रश्नांकित करते हैंः ''प्रतिबद्धता और प्रामाणिकता दो अलग-अलग बातें हैं.'' आलोचना सम्राट नामवर सिंह भी एक पुरानी टिप्पणी में उनकी कहानियों में ब्यौरे और तथ्यों के हावी होने की बात कहते हैं. पर इस पूरे अंक की जान हैं संजीव को लिखे चर्चित संपादक-कथाकार राजेंद्र यादव के चार पत्र, जिसमें वे अपने चुटीले अंदाज में उन्हें सज्जन और सरल मनुष्य होने का सफलतापूर्वक अभिनय करने के लिए साधुवाद देते हैं.

बहरहाल, निशांत ने अपने संपादकीय में *सहयोग* का हर अंक ''युग-रचनाकारों'' पर केंद्रित करते हुए एक विशेषांक की शक्ल में लाने का भरोसा जताया है. उम्मीद करनी चाहिए कि *सहयोग* की उम्र लंबी हो. –शिवकेश

सवाल + जवाब

जिंदगी मेरी फैसले मेरे

सुंदर पिचाई और सत्य नडेला वाली कड़ी में उनसे भी पहले आती हैं इंदिरा नूई. पेप्सिको की पूर्व सीईओ ने नई किताब *अ लाइफ इन फुल* में किया निजी और पेशेवर जिंदगी की बेबाकी से बयान

● आपकी किताब मां-बेटी के रिश्तों की जटिलता पर बात करती है...

बच्चे खासकर बेटियां मां से ही कह-सुन, लड़-झगड़ पाती हैं. और आप कामकाजी हैं तो दस काम और करने होते हैं. दोनों ही आपको अपने बारे में जब-तब याद दिलाते रहते हैं, और यह स्वाभाविक भी है. जिंदगी मुकम्मल कहां होती है! पानी में तैरती बत्तख जैसा हाल है—ऊपर से शांत लेकिन नीचे तेजी से पानी को चीरती चलती है. नेपथ्य में तो हम सब बेसब्री से हाथ-पांव चला रहे होते हैं, घर की चुनौतियों और वहां हो रही कहा-सुनी को जाहिर नहीं होने देते. एक मिसाल से मैंने आपको समझाया. यह सब इतना आसान नहीं होता. पर संतुलन साधते हुए रास्ता निकालते हैं, निकालना पड़ता है.

● डोरिटोज़ चिप्स और केंडेल जेनर विज्ञापन विवाद को किताब में जगह नहीं मिल पाई...

जितना कुछ 90,000 शब्दों में बताया जा सकता था, बताया गया. आप पॉडकास्ट सुनिए, मैंने इतना ही कहा था कि लोग पब्लिक में चिप्स बहुत जोर से चबाना पसंद नहीं करते. तुरंत उससे 'फीमेल डोरिटोज' का अर्थ निकाल लिया गया. केंडल जेनर ऐड एक अश्वेत ने बनाया था, सो हम पर वर्ण संवेदनहीनता का आरोप बेमानी था. कोई बात नहीं. यह किताब किसी को नीचा दिखाने के लिए थोड़े ही है.

● आपने लिखा है कि आपको ''ब्राह्मण के रूप में पैदा होना किस्मत की बात रही''. ऐसा क्यों कहा आपने?

भई, मैं आखिर वही हूं ना! ब्राह्मणत्व को धन-संपदा से जोड़ना गलत है. ब्राह्मण इतने समृद्ध नहीं थे. पारंपरिक ब्राह्मणों के नाते अध्ययन और कर्नाटक संगीत तथा भरतनाट्यम की शिक्षा ही हमारे मूल्य थे. पर जैसा किताब में जिक्र है, ब्राह्मण होने का एक लाभ था. लोग हमें सम्मान देते थे क्योंकि हमें सुशिक्षित तबका माना जाता था. यह कबूलने वाली मैं पहली हूं कि इसका मुझे थोड़ा-सा लाभ मिला.

● क्या भारत में कामकाजी महिलाओं का अलग ही किस्म की चुनौतियों से सामना होता है?

जितने देशों को मैं जानती हूं, उनके मुकाबले भारत में ज्यादा प्रगतिशील कानून हैं पर उन्हें सख्ती से लागू करना होगा. कॉर्पोरेट परिवेश बदलना होगा. वे कहेंगे कि कोई महिला नौकरी में रखे जाने पर भी तभी आती है जब उसके पति का भी तबादला हो. ऐसे पूर्वाग्रह दूर करने होंगे.

—अनु प्रभाकर

आज तक

देश का नं. 1 हिंदी न्यूज़ ऐप

जुड़े रहिए हर खबर से,
कहीं भी, कभी भी

अभी डाउनलोड करें

aajtak.in/app

उपलब्ध है

IndiaContent

SEARCH FOR EDITORIAL IMAGES ENDS HERE